हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

21 अगस्त, 1972

खण्ड 2, अंक 5

अधिकृत विवरण

विषय सूची

सोमवार, 21 अगस्त, 1972

पृष्ठ संख्या

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(5)1
कार्य मंत्रणा समिति का तृतीय प्रतिवेदन	(5)31
मेज पर रखे गए कागज पत्र	(5)32
वर्ष 1972–73 के अनुपूरक अनुमान (प्रथम किश्त) (1) राज्य के राजस्वों पर प्रभृत व्यय के अनुमानों पर चर्चा (2) अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान	 (5)32 (5)32
बैठके के समय में वृद्धि	(5)80
अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान (पुनरारम्भ)	(5)81
बहिर्गमन	(5)95
अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान (पुनरारम्भ)	(5)96

हरियाणा विधान सभा,

सोमवार, 21 अगस्त, 1972

विधानसभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर–1, चण्डीगढ में मध्यान्होपरान्त 2.00 बजे हुई। श्री अध्यक्ष (श्री बनारसी दास गुप्त) ने अध्यक्षता की।

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण प्रश्नोत्तर काल।

Construction of Bund

***63. K.N. Gulati:** Will the Chief Minister be pleases to state-

(a) whether the Government has received any demand from the inhabitants of village Manager (Faridabad Block) for construction of a Bund; and

(b) the time by which the Bund referred to in part (a) above is likely to be constructed ?

Deputy Minister Health (Smt. Sharda Rani):

(a) No.

(b) Question does not arise.

श्री के0एन0 गुलाटीः ऐसा जान पडता है कि मिनिस्टर साहिबान की उस इलाके के साथ कोई नाराजगी है। क्या मैं जान सकता हूं कि मंगर इलाके के लोगों की तकलीफों को जानने के लिए आज तक किसी मिनिटर का वहां विजिट हुआ है ?

गृह मंत्री (श्री के0एल0 पोसवाल): स्पीकर साहब, मैं कई दफा गया हूं।

श्री के0एन0 गुलाटीः मेरे ख्याल में यह इन्फर्मेशन गलत है।

चौधरी फूल चन्द (रोहट): स्पीकर साहब, एक बंध जो खादर के एरिया में सोनीपत और पानीपत के बीच जमुना पर है वह हर साल टूट जाता है और हजारों गांव और लाखों एकड जमीन पानी की जद में आ जाती है। इस एरिया के अंदर ठोकरें बनाने की जो तजवीज थी उस पर काम शुरू नहीं हुआ है ..... (विघ्न)

मुख्य मंत्री (चौधरी बंसी लाल): स्पीकर साहब, आनरेबल मैम्बर ने कहा है कि हजारों गांव पानी की जद में आ जाते हैं। क्या मैं जान सकता हूं कि कितने हजार गांव हैं वहां ?

श्री अध्यक्षः वह तो खादर का एरिया है।

चौधरी फूल चन्द (रोहट): स्पीकर साहब, मेरा मतलब जमुनानगर से लेकर पानीपत की तमाम बेल्ट से था।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न।

चौधरी फूल चन्द (रोहट): क्या यह मेरे प्रश्न का जवाब था जी ? (हंसी)

Committee to Merge Property Tax and House Tax

***125. Sh. Girish Chander Joshi:**Will the Chief Minister be pleases to state-

(a) whether any Committee was set up by the Government to merge Property Tax and House Tax; and

(b) if so, the reommendations there of and the action taken by the Government thereon ?

Chief Minister (Ch. Bansi Lal):

(a) No.

(b) Question does not arise.

श्री गिरीश चन्द्र जोशी: स्पीकर साहब, आप जानते हैं कि प्रौपटी टैक्स और हाउस टैक्स का टैक्स का असर गरीबों पर पडता है। तो क्या मैं मुख्य मंत्री जी से पूछ सकता हूं कि क्या इन टैक्सिज को रेशनेलाइज करने की कोई तजवीज है ?

Ch. Bansi Lal: Mr. Speaker, Sir, I fully agree with the Hon. Member that there should be reationalisation of all this sort of taxes and very recently we had some discussion on this subject. The Government is thinking on these lines whether we should amalgamate these two taxes or other taxes

so that The Taxation Law is simplified and during the next few months we are likely to take some decision in this respect.

चौधरी फूल चन्द (रोहट): स्पीकर साहब, प्रौपर्टी टैक्स के मुताल्लिक हमारे अफसरान का भी ख्याल है कि यह टैक्स नाजेबा और फजूल है। मिसाल के तौर पर उन्होंने बतलाया कि ... ... (विघ्न) इस टैक्स से बचने के लिये लोग अपनी औरत के नाम मकान कर देते हैं।

श्री अध्यक्ष: चौधरी साहब, आप इंफर्मेशन देने की बजाये सीधा प्रश्न कीजिए। ..(विघ्न)

चौधरी फूल चन्द (रोहट): मैं मिनिस्टर साहब से पूछना चाहूंगा कि क्या इस टैक्स को बिल्कुल ऐबोलिश करने का भी कोई ख्याल हे ?

चौधरी बंसी लाल: जी नहीं।

Jeeps to Police Station

***121. Lala Rulya Ram:** Will the Minister for Home be pleases to state-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to provide a jeep to each police station;

(b) the particulars of persons of Karnal district who were previously Badmash Basti (Alif) (10) and Badmash Basti (B) (10) and who are at present on peronal files of various police stations and holding licences of fire amrs; and

(c) whether there is any proposal under consideration of the Government to withdraw such licences from the persons referred to in para (b) above ?

Home Minister (Sh. K.L. Poswal):

(a) A proposal to provide a jeep to each Police Station in the State was considered and it was decided to keep it in abeyance for the time being on account of financial stringency.

(b) There are 27 persons of Karnal district, who were previously Badmash Basti (Alif) (10) and Badmash Basti (B) (10) and who are now on presonal files of various Police Stations, and holding licences of fire arms. Their particulars are given in the attached list.

(c) There is no proposal under consideration with the Government to withdraw such licences from the persons referred to in sub para (b) above.

LIST

Particulars of the persons on personal files of various Police Stations.

1	Jai Singh son of Sohan Singh Balmiki resident of Sithana P.S., Sadar Paniapt	ML Gun
2	Hajoor Singh son of Nand Singh (Jat) resident of Bassa P.S., Nissing	DBBI, Gun
3	Kashmir Singh son of Udham Singh resident of Jalamana P.S., Nissing	Do
4	Nishan Singh son of Swan Singh resident of Jaimana P.S., Nissing	Do
5	Mehanga Sijngh son of Saudagar Singh resident of Dachar P.S., Nissing	Do
6	Harnam Singh son of Washawa Singh resident of Nissing P.S., Nissing	Do
7	Bhagal Singh son of Bajja Singh resident of Nissing P.S., Nissing	DBBL Gun
8	Anokh Singh son of Mehaga Singh resident of Balu, P.S., Nissing	Do
9	Nishan Singh son of Makhan Singh resident of Balu, P.S., Nissing	Do
10	Shangara Singh son of Nishan Singh resident of Balu	Do
11	Sher Singh son of Jhandu resident of Majra P.S., Nissing	Do
12	pala Singh son of Inder Singh resident of Ramanaramani, P.S., Nissing	do
13	Singh Ram son of Kanahya resident of Manchuri, P.S.,	Pistol

	Nissing	
14	Amar Singh son of Mohar Singh resident of Shingar, P.S., Nissing	DBBL Gun
15	Hardyal Singh son of Taje Singh resident of Khanpur, P.S., Nissing	Do
16	Hari Singh son of Mam Raj residnet of Khanpur P.S., Indri	Gun
17	Kapoor Singh son of Havala Singh resident of Chhamu Kalan P.S., Thaska	DBBL Gun
18	Dalip Singh son of Jamal Singh resident of Teleheri, P.S., Thaska	SBBL Gun
19	Balkar Singh son of Jamal Singh resident of Hassanpur, P.S., Thaska	Gun
20	Kundan Singh son of Mangal singh resident of Kumhar Marja, P.S., Thaska	Gun
21	Narain Singh son of Mangal Singh resident of Mangal Garhi, P.S., Ghataunda	Gun & Pistol
22	Rachha son of Harbans resident of Kaurak, P.S., S.D.R. Kaithal	Gun
23	Balkar Singh son of Phul Singh resident of Umedpur, P.S., S.D.R. Kaithal	Gun
24	Sahab Singh son of Phul Singh resident of Umedpur, P.S., S.D.R. Kaithal	Gun

25	Iqbal Singh son of Bhola Singh resident of Sangauli, P.S., Pundri	Gun
26	Ramji Lal son of Kura Ram Gujjar resident of Pansar, P.S., Guhla	Gun
27	Mukhtiara son of Budha Gujjar resident of Pansar, P.S., Guhla	Gun

चौधरी दल सिंहः क्या लाला रूलिया राम का नाम इसमें हैं ? (हंसी)

मुख्य मंत्री (चौधरी बंसी लाल): स्पीकर साहब, इनकी बजाय शायद चौधरी दल सिंह का नाम आने की संभावना है। (हंसी)

श्री के0एल0 पोसवालः गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट के तो भाई ऊंची पदवी पर चले गए हैं। (हंसी)

चौधरी फूल चन्द (रोहट): स्पीकर साहब, इन्होंनें क्या ऐसी भी कोई लिस्ट बनाई है जिससे पता चल सके जो बदमाश बस्ता (10) (अलिफ) और बदमाश बस्ता (10) (बे) के लोग थे उनमें से कितने एम0एल0एज0 बने, कितने ब्लाक समितियों के चेयरमैन और दूसरे चेयरमैन तथा कितने वजीर बने ?

चौधरी बंसी लालः अगर आनरेबल मैम्बर का यह ख्याल है कि उनका नाम उसमें नहीं आया है तो इंक्लूड किया जा सकता है। थोडी मेहनत ये करें, थोडी पुलिस करेगी।

लाला रूलिया रामः स्पीकर साहब, मिनिस्अर साहब ने अभी बताया कि 27 आदमी ऐसे हैं जो पहले बदमाश बस्ता (10) (अलिफ) और बदमाश बस्ता (10)(बे) पर थे और अब असला के लाईसैंस दाराना हैं तो इसके मुताल्लिक मैं यह पूछना चाहता हूं कि जब ये लोग बदमाश गिने जाते हैं तो इनके लाईसैंस कैंसलि क्यों नहीं हुए ?

श्री के0एल0 पोसवालः स्पीकर साहब, बाज दफा ऐसे केसिज होते हैं जिनकी अपनी सिक्योरिटी के लिए आर्म नैसैसरी होता है। दूसरे यह भी होता है कि ये लोग चोर, डाकू, आदि पकडने में कुछ गवर्नमैंअ की मदद भी करे हैं। तो स्पैशल केसिज में इनको लाईसैंस दिया जाता है।

चौधरी पीर चन्दः क्या मिनिस्अर साहब बतलाने की कृपा करेंगे कि यह जो बदमाश बस्ता (10)(अलिफ) और बदमाश बस्ता (10) (बे) लोग होते हैं इनको सुधारने की भी कोई प्रपोजल है या इसी तरह से ये और बढते चले जाएंगे ?

श्री के0एल0 पोसवालः हम तो कोशिश करते हैं। वेसे देखिए भाई साहब सुधर ही गए। (हंसी)

चौधरी फूल चन्द (मुलाना): क्या मिनिस्टर साहब यह बताने की कृपा करेंगे कि कुछ पुलिस स्टेशन्ज जहां जुर्म ज्यादा हैं, जो इम्पोर्टेंट पुलिस स्टेशन्ज हैं, वहां जीप देने की कृपा की जाएगी ?

श्री के0एल0 पोसवालः हम बहुत जल्दी ही इस बात को कंसिडर कर रहे हैं।

श्री अमर सिंहः स्पीकर साहब, प्रश्न के ए भाग के जवाब में मिनिस्टर साहब ने कहा कि फाईनैंशल क्राइसिज की वजह से पुलिस स्टेशन्ज को अभी जीपस नहीं दे सकते। क्या उनके पास यह इंफर्मेशन है कि बी0डी0ओज0 की जीपस जो है। वे इस वक्त फालतू हैं। यदि हैं तो क्या ये जीपस पुलिस स्टेशेंज को हैंड ओवर कर दी जाएंगी ?

चौधरी बंसी लालः स्पीकर साहब, बी0डी0ओज0 की जीप के ऊपर बडा भारी प्रैशर है। आनरेबल मैम्बर को यह पता होना चाहिए कि यह जीप सबसे ज्यादा बिजी जीप है क्योंकि बहुत से डिपार्टमैंटस के साथ उनका काम होता है।

श्री अध्यक्षः वैसे भी यह प्रश्न इससे पैदा नहीं होता।

चौधरी दल सिंहः स्पीकर साहब, जब डी0एस0पी0 और एस0पी0 के पास दो जीपें ही होती हैं तो थानेदार को यह तीसरी जीप देने की गवर्नमैंट को क्या जरूरत है ? इससे तो लोगों को और ज्यादा हैरासमैंट ही होगी। .....

चौधरी बंसी लालः यह आपस में फैसला कर लो, फिर हमको बतलाना।

चौधरी फूल चन्द (रोहट): स्पीकर साहब, लाईसैंस के लिए जो दरख्वास्तें दी जाती हैं उनमें बहुत सी दरख्वास्तें शडयूल्ड कास्टस के आदमियों की भी होती हैं। यह दरख्वास्तें डी0एस0पी0 और एस0एच0ओ0 आदि से तसदीक की बड़ी मुश्किल पडती हैं।

श्री अध्यक्षः चौधरी साहब, आप अपनी राय न दें, जो पूछना है वह पूछिए।

चौधरी फूल चन्द (रोहट): तो क्या मिनिस्टर साहब बताएंगे कि लाईसैंस देने के ढंग को कुछ थोडा सा आसान बनाया जाएगा ताकि लोगों को लाईसैंस लेने में सहूलियत हो ?

श्री के0एल0 पोसवालः तसदीक के बगैर तो लाईसैंस देना बडा मुश्किल है। यदि ऐसा न करें तो फिर बदमाश बस्ता (10) (अलिफ) और बदमाश बस्ता (10) (बे) का कैसे पता चलेगा ?

चौधरी शिव राम वर्माः स्पीकर साहब, अभी मंत्री महोदय ने सिर्फ यह जवाब दिया कि बस्ता (10) (अलिफ) और बस्ता (10) (बे) से लाईसैंस वापिस नहीं लेंगे बल्कि उनकी तारीफ भी की कि वे सरकार की मदद करते हैं। तो मेरा निवेदन यह है कि या तो इन लोगों को बस्ता (10) (अलिफ) और बस्ता (10) (बे) लिस्ट से निकाल देना चाहिए, नहीं तो उनके लाईसैंस वापिस लेने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।

श्री के0एल0 पोसवालः वे इस वक्त बस्ता (10) (अलिफ) और बस्ता (10) (बे) में नहीं हैं मगर भिन्न भिन्न थानों की पर्सनल फाईलों पर उनके नाम हैं। अगर किसी आनरेबल मैम्बर को यह पता हो कि अब भी वे खतरनाक आदमी हैं तो वह हमें बताए, हम उनके लाईसैंस कैंसल कर देंगे।

श्री अमर सिंहः स्पीकर साहब, आनरेबल मिनिस्टर साहब ने पार्ट बी के जवाब में 27 आदमियों के नाम बताएं हैं। क्या आनरेबल मिनिस्टर यह बताने की भी कृपा करेंगे कि इनमें से कोई ऐसा आदमी भी है जो बस्ता (10) (अलिफ) और बस्ता (10) (बे) पर होते हुए भी उसके पास लाईसैंस था ?

चौधरी बंसी लालः पहले भी हो तो वह कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है। किसी आदमी की पर्सनल प्रोटैक्शन के लिए यदि अथौरिटीज समझें कि उसको असला का लाईसैंस देना जरूरी है तो वह किसी भी वक्त दिया जा सकता है। हर जान की हिफाजत करना सरकार का काम है।

चौधरी मेहर चन्दः क्या हमा मिनिस्टर साहब, यह बताने की कृपा करेंगे कि बस्ता (अलिफ) और बस्ता (बे) में किस किस कैटैगरी के बदमाश हैं ? हमने बस्ता (अलिफ) तो सुना था परन्तु बस्ता (बे) आज तक नहीं सुना। कृपया बस्ता (बे) के बारे में भी बता दें। (हंसी)

श्री अध्यक्षः चौधरी साहब, आप तो किसी बस्तें में नहीं आते हैं। (हंसी)

कृषि मंत्री (चौधरी भजन लाल): जो ज्यादा बदमाश हों वे बस्ता (अलिफ) में आते हैं और जो कुछ कम हों वे बस्ता (बे) में आते हैं।

लाला रूलिया रामः जैसा कि अभी चौधरी दल सिंह ने कहा है कि एक जीप एस0पी0 साहब के पास है और एक जीप डी0एस0पी0 साहब के पास है लेकिन थान के अंदर कोई जीप नहीं होती है। एक थान में 60–70 गांव होते हैं। और वहां जीप न होने के कारण थाने वालों को दिक्कत होती है। इसलिए वहां जीप दी जानी चाहिए। यह मैं आप के नोटिस में लाना चाहता था।

श्री अध्यक्षः लाला जी आप नोटिस में कुछ न लाएं। आप तो सजैशन दे रहे हैं। यह सप्लीमैंटरी नहीं है।

चौधरी बंसी लालः यह हम कंसिडर कर रहे है।

लाला रूलिया रामः मैं आपके द्वारा रिक्वैस्ट करता हूं कि मेरी सजैशन पर विचार किया जाये।

चौधरी फूल चन्द (रोहट): थानों के अंदर नफरी काम होने से वहां के एस0एच0ओ0 आदि बड़े मायूस हैं। क्या सरकार की कोई तजवीज है कि थानों की नफरी बढा दी जाए ?

Sh. K.L. Poswal: Yes, ewe are considering this.

Defects in B.K. Hospital Faridabad

***64. Sh. K.N. Gualati:** Will the Minister for Home be pleases to state-

(a) the number of docctors and other staff at present working in B.K. Hospital, Faridabad, who are over age together with their names;

(b) the number of ambulance lorries in the hospital and whether thee is any proposal under consideration of the Government to increase the number of ambulance lorries to meet the demands of the public;

(c) whether it is a fact that adulterated food and milk is being supplied to the patients in the hospital referred to in part (a) above; and

(d) whether any complaint has been received against the store incharge and also against the functioning of X-Ray Department of the hospital referred to in part (a) above ?

Depudy Minister Health (Smt. Sharda Rani):

(a) One Dr. Nirmal Parkash has been re employed beyond the age of superannuation up to 12th December 1972.

(b) One. One new additional ambulance is being purchased during the current year.

(c) No. Milk samples were taken for the analysis and except in one case, they were found to conform to standard specifications. In the one case, the Contractor was punished suitably.

(d) Yes.

श्री के0एन0 गुलाटीः इस सवाल के पार्ट ए के जवाब के मुताबिक ओवर एजड डाक्टर को एक्सटैंशन दी गई। क्या सरकार के नोटिस में यह है कि डाक्टर निर्मल प्रकाश की जेरे निगरानी में हास्पिटल की कंडीशन बिगडती जा रही है ? क्या उनकी जगह किसी दूसरे डाक्टर को लगाने की तजवीज है ?

श्रीमती शारदा रानीः डाक्टर निर्मल प्रकाश को पब्लिक इन्ट्रेस्ट में लगाया गया। यह बात किसी ने भी हमारे नोटिस में नहीं लाई कि हास्पिटल की हालत बिगड़ती जा रही है।

चौधरी दल सिंहः वह पब्लिक इन्ट्रेस्ट क्या है जिसके तहत उसको एक्सटेंशन दी गयी ?

मुख्य मंत्री (चौधरी बंसी लाल): एक्सपर्ट डाक्टर अवेलेबल नहीं थे और Keeping in view the service, seniority and efficiency of the doctor, he was kept in service for that period.

श्री के0एन0 गुलाटीः इस प्रश्न के बी पार्ट के जवाब में बताया गया है कि इस वक्त एक एम्बुलेंस है और एक इस साल खरीदी जा रही है। अगर पूरी तादाद में एम्बुलैंस गाडियां न होने

के कारण किसी का नुकसान हो गया तो उसकी जिम्मेदारी किस की होगी ?

चौधरी बंसी लालः आपने तो यहीं रवहना है, वहां जाना ही नहीं (हंसी) आपको कोई नुकसान नहीं होने देंगें।

राव बंसी सिंहः हरेक डिस्ट्रिक्ट में और हरेक तहसील में जहां पर सिविल हास्पिटल्ज हैं या लेडीज होस्पिटल हैं, हर जगह पर एम्बूलैंस गाडी देने की क्या कोई प्रोपोजल है ?

श्रीमती शारदा रानीः बारी बारी से सभी हास्पिटल्ज में जहां जहां नहीं हैं; वहीं पर प्रोवाइड की जा रही हैं।

श्री के0एन0 गुलाटीः क्या डिप्टी मिनिस्टर महोदया, यह बताने का कष्ट करेंगी कि जो दूध एफिडेविट देकर कि खालिस दूध है, हास्पिटल में सप्लाई किया जाता है, उसका क्या भाव है ?

श्रीमती शारदा रानीः इस सवाल में दूध का रेट नहीं पूछा गया। इसके लिए सैपरेट नोटिस देंगे तो बतला देंगे।

श्री के0एन0 गुलाटीः मैं बतला देता हूं।

चौधरी बंसी लालः गुलाटी साहब नहीं बतला सकते, न मैंने उनको मिनिस्टर बनाया है और न बनाने का इरादा है।

श्री के0एन0 गुलाटी: एक रूपये और सवा रूपये किलो के हिसब से दूध सप्लाई किया जाता है। तो क्या यह मुमकिन है कि इस भाव से खालिस दूध सप्लाई किया जा सकता है। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष: ठीक है। आप रेज जानते होंगे। आप बैठ जाइये।

चौधरी फूल चन्द (रोहट): स्पीकर साहब, कई बार ऐसा होता है कि किसी का अंगूठा टूटा हुआ तो नहीं होता परन्तु ऐक्स रे मशीन में टूटा हुआ आ जाता है। उस मशीन के नीचे कोई प्लास्टिक का धागा रख देते हैं जिससे वह टूटा हुआ आ जाता है। क्या सरकार उन मशीनों में सुधार लाने की कोशिश करेगी ?

श्री अध्यक्ष: यह सप्लीमैंअरी इस प्रश्न से पैदा नहीं होता।

चौधरी बंसी लाल: स्पीकर साहब, चौधरी फूल चन्द अम्बाला चले जायें और वहां जाकर खुद देख लें कि मशीने के नीचे कोई धागा वगैरह होता है या नहीं। आनरेबल मैम्बर को सही पता चल जायेगा।

चौधरी पीर चंद: क्या डिप्टी मिनिस्टर महोदया यह बताने का कष्ट करेंगी कि क्या इस साल कोई नया हास्पिटल खोलने की प्रोपोजल है ?

श्रीमती शारदा रानी: जी है।

चौधरी दल सिंहः जिस हास्पिअल में एम्बुलैंस है उसको ले जाने के लिए कुछ खर्चा देना पडता है और एम्बुलैंस को ले जाने केग लिए डी0सी0 साहब की मंजूरी लेनी पडती है। क्या गवर्नमैंट यह इख्तियारात डाक्टर इंचार्ज को देने को तैयार है ?

Ch. Bansi Lal: That is a good point worth consideration and Government will consider it.

Dispensaries and Hospitals under E.S.I. Scheme

***126h. Sh. Girish Chander Joshi:** Will the Chief Minister be pleases to state-

(a) the number of dispensaries and hospitals working in the State under E.S.I. Scheme;

(b) the total requirement of staff in such hospitals and dispensaries as at present;

(c) whether there is any proposal under the consideration of the Government to meet the shortage of staff by having a separate cadre of staff under E.S.I. Scheme; if so, the time by which is it likely to be provided; and

(d) the year wise amount earmarked by the E.S.I. Corporation to Haryana State together with the total amount spent so far ?

Depudy Minister Health (Smt. Sharda Rani):

(a) Hospitals- 5, Dispensaries- 39

(b) The total sanctioned strength of staff of all categories is 824. A detailed statement showing the number of staff in each Hospital and Dispensary sanctioned and in position is given as Annexure A & B.

(c) Yes. The matter is under the consideration of Government and will be decided in due course.

(d) A statement is given as Annexure 'C'

ANNEXURE A

List showing E.S.I. Hospitals/Dispensaries

1. E.S.I. General Hospital, Faridabad.

2. Chest Diseases Hospital, Faridabad

3. E.S.I. General Hospital, Jagadhri

4. E.S.I. General Hospital, Panipat

5. Chest Diseases Hospital, Panipat

DISPENSARIES

	Name of Place	No. of Dispensaries
1	E.S.I. Dispensary, Faridabad	11
2	E.S.I. Dispensary, Ballabgarh	2
3	E.S.I. Dispensary, Ambala City	1
4	E.S.I. Dispensary, Ambala Cantt.	1
5	E.S.I. Dispensary, Bahadurgarh	2
6	E.S.I. Dispensary, Bhiwani	3

7	E.S.I. Dispensary, Charkhi Dadri	1
8	E.S.I. Dispensary, Gurgaon	2
9	E.S.I. Dispensary, Gannaur	1
10	E.S.I. Dispensary, Hissar	3
11	E.S.I. Dispensary, Panipat	2
12	E.S.I. Dispensary, Rewari	1
13	E.S.I. Dispensary, Rohtak	1
14	E.S.I. Dispensary, Sonepat	2
15	E.S.I. Dispensary, Jagadhri	2
16	E.S.I. Dispensary, Yamuna Nagar	4

ANNEXURE 'B'

A. E.S.I. Hospitals in Haryana State Sanctioned Strength and Staff Position

Sr. No.	Name of the Institution	Administrative Medical Officer H.C.M.S. I, Sanctioned	Position	Vacant	Medical Officer Sanctioned	Position	Vacant	Specialists Sanctioned	Position	Vacant
1	E.S.I. Hospital Faridabad	1	1		1	1		7	7	
2	12 Bedded T.B. Ward Faridabad									
3	60 Bedded ESI	1	1		1	1		6	6	

	Hospital, Jagadhari									
4	15 Bedded E.S.I. Hospital, Paniapat				1	1				
5	35 Bedded E.S.I. Chest Diseases Hospital Panipat	1	1		1	1				
Sr. No.	Name of the Institution	Pharmaicsts Sanctioned	Position	Vacant	Nursing Sister Sanctioned	Position	Vacant	Staff Nurses Sanctioned	Position	Vacant

1	E.S.I. Hospital Faridabad	3	3		1	1		8	7	1
2	12 Bedded T.B. Ward Faridabad	1	1					3	3	
3	ESI Hospital, Jagadhari	3	3		1	1		8	8	
4	15 Bedded E.S.I. Hospital, Paniapat	1	1						3	
5	35 Bedded E.S.I. Chest	2	2		1	1		5	5	

	Diseases Hospital Panipat									
Sr. No.	Name of the Institution	Laboratory Assistants Grade- I Sanctioned	Position	Vacant	Radiographers Sanctioned	Position	Vacant	Clerks Sanctioned	Position	Vacant
1	E.S.I. Hospital Faridabad	1	1		1	1		1	1	
2	12 Bedded T.B. Ward Faridabad							1	1	
3	ESI Hospital, Jagadhari							1	1	

4	15 Bedded E.S.I. Hospital, Paniapat	1	1		1	1		1	1	
5	35 Bedded E.S.I. Chest Diseases Hospital Panipat	1		1	1		1			
Sr. No.	Name of the Institution	Drivers Sanctioned	Position	Vacant	Cleaners Sanctioned	Position	Vacant	Class- IV Sanctioned	Position	Vacant
1	E.S.I. Hospital Faridabad	2	1	1	2	1	1	22	22	

2	12 Bedded T.B. Ward Faridabad							6	6	
3	ESI Hospital, Jagadhari	2	1	1	2	1	1	23	23	
4	15 Bedded E.S.I. Hospital, Paniapat							6	6	
5	35 Bedded E.S.I. Chest Diseases Hospital Panipat							14	14	

B. E.S.I. DISPENSARIES IN HARYANA STATE Sancationed Strngthe and Staff in Position

Sr. No.	Name of Dispensary	Mecidal Officers H.C.M.S. II			Pharmacists			L.H.V's		
		Sanctioned	Position	Vacant	Sanctioned	Position	Vacant	Sanctioned	Position	Vacant
1	Do Faridabad	29	29		47	16	29	11	3	8
2	Do Ballabgarh	4	2	2	6	2	4	2	1	1

3	Do Ambala City	1	1		2	1	1	1	1	
4	Do Ambala Cantt.	2	2		3	2	1	1	1	
5	Do Bahadurgarh	3	2	1	5	3	2	1	1	
6	Do Bhiwani	7	6	1	11	5	6	3	1	2
7	Do Charkhi Dadri	2	2		3	2	1	1		
8	Do Gurgaon	3	3		5	3	2	2	1	1
9.	Do Gannaur	1	1		2	1	1	1	1	
10	Do Hissar	5	4	1	9	5	4	3	2	1
11	Do Panipat	3	3		5	3	2	2	1	1

12	Do Rewari	1	1		1	1		1	1	
13	Do Rohtak	2	2		3	2	1	1	1	
14	Do Sonepat	6	5	1	9	5	4	2	1	
15	Do Jagadhri	4	4		6	6		2	1	1
16	Do Yamuna Nagar	8	3	5	12	4	8	4		4
Sr. No.	Name of Dispensary	ANM's			Laboratory Assistands Grade II			Assistants		
		Sanctioned	Position	Vacant	Sanctioned	Position	Vacant	Sanctioned	Position	Vacant
1	Do Faridabad	12	10	2	10	2	8	10	4	6
2	Do Ballabgarh	2	1	1	2		2	2	1	1

3	Do Ambala City	1	1							
4	Do Ambala Cantt.	1	1		1		1	1		1
5	Do Bahadurgarh	2	2		1		1	1	1	
6	Do Bhiwani	3	3		3	1	2	3	1	2
7	Do Charkhi Dadri	1		1	1		1	1	1	
8	Do Gurgaon	2	2		1	1		1	1	
9.	Do Gannaur	1	1							
10	Do Hissar	3	2	1	1		1	1	1	
11	Do Panipat	2	2		1	1		1	1	

12	Do Rewari	1	1							
13	Do Rohtak	1	1		1		1	1	1	
14	Do Sonepat	3	3		2	2		2		2
15	Do Jagadhri	2	2		2	1	1			
16	Do Yamuna Nagar	4		4	4		4			

Sr. No.	Name of Dispensary	Clerks Staff			Class IV		
		Sanctioned	Position	Vacant	Sanctioned	Position	Vacant
1	Do Faridabad	12	8	4	79	41	33
2	Do Ballabgarh	2	1	1	12	4	8
3	Do Ambala City	1	1		5	2	3
4	Do Ambala Cantt.	1	1		6	3	3

5	Do Bahadurgarh	2	2		11	4	7
6	Do Bhiwani	3	2	1	19	13	6
7	Do Charkhi Dadri	1	1		6	4	2
8	Do Gurgaon	2	1	1	11	6	5
9.	Do Gannaur	1	1		5	4	1
10	Do Hissar	3	2	1	17	7	10
11	Do Panipat	2	1	1	11	7	4
12	Do Rewari	1	1		4	4	
13	Do Rohtak	1	1		6	4	2
14	Do Sonepat	3	3		15	13	2
15	Do Jagadhri	4	3	1	12	7	5
16	Do Yamuna Nagar	4	4		24		24

Sr. No.	Name of Institution	Drivers			Cleaners		
		Sanctioned	Position	Vacant	Sanctioned	Position	Vacant
1	Mobile Dispensary, Faridabad	1	1		1	1	

ANNEXURE 'C'

Statement Showing Yearwise Expenditure, Share of ESI Corporation and State Government

Year	Actual Expenditure	7/8 Share of Expenditure from E.S.I. Corporation	1/8 Share Borne by the State Government
196-67 (1-11-66 to 31-3-67)	1478962	1294092	184870
1967-68	2577543	2255350	322193
1968-69	4349292	3805630	543662
1969-70	3251105	2844717	406388
1970-71	5137840	4495610	642230
1971-72	5251000	4594625	656375
Total	22045742	19290024	2755718

श्री गिरीशन चन्द्र जोशीः डिप्टी मिनिस्टर महोदया ने जो स्टेटमैंट सबमिट की है उसके मुताबिक, काफी पोसटस वेकेंट हैं और यमुनानगर में भी हैं क्या सरकार इन पोस्टस को फिलअप करने के लिए कोई कारगुजारी करेगी ?

श्रीमती शारदा रानीः ये पोस्टस बहुत जल्दी ही भरी जा रही हैं। यह डिस्पेंसरी थोडे ही अर्से से खोली गई हैं। ज्यों ज्यों ट्रैंड स्टाफ अवेलेबल हाचेता जायेगा, इन वैकेंट पोस्टस को भरते जायेंगे।

चौधरी दल सिंहः जो स्टेट में बडे बडे गांव हैं जैसे मिसाल के तौर पर मटोर गांव जिसकी आबादी 12 हजार के करीब हैं क्या वहां पर हास्पिटल खोलने का विचार है?

श्री अध्यक्षः मूल प्रश्न ई0एस0आई0 स्कीम के बारे मैं है। वही प्रश्न पूछें जो इससे संबंधित हों।

चौधरी राम लाल वधवाः क्या डिप्टी मिनिस्टर महोदया यह बताने का कष्ट करेंगी कि किन किन हास्पिटलज में डाक्टर नहीं हैं ?

श्रीमती शारदा रानीः डाक्टर सब में हैं।

श्री अमर सिंहः डिप्टी मिनिस्टर महोदया ने इस सवाल के ए पार्ट के जवाब में अभी बताया है कि ई0एस0अई0 स्कीम के तहत 5 हास्पिटलज और 39 डिस्पैंसरीज हैं क्या कारण है इतनी

कम डिस्पेंसरीज हैं ओर इतने कम हास्पिटल्ज हैं ? क्या ज्यादा खोलने की भी कोई तजवीज है ?

श्रीमती शारदा रानीः ये डिस्पैंसरीज हमारे इंश्योड इम्पलाइज पर डिपैंड करती हैं। जितना ज्यादा इंश्योरड इम्पलाइज का नंबर बढता जायेगा उतनी ही ज्यादा डिसपैंसरीज खोलते जायेंगे और खोलते जा रहे हैं।

चौधरी फूल चन्द रोहटः ई0एस0आई0 स्कीम के तहत जो हास्पिटल्ज चल रहे हैं उमें पेशेंटस का नंबर कम है या बिल्कुल ही नहीं है। क्या मैं जान सकता हूं कि क्या इंडारे पेशेन्टस के लिए बैडज बढाने का कोई विचार है ?

श्रीमती शारदा रानीः आपका यह प्रश्न मेन क्वैश्चन से अराइज नहीं होता है। फिर भी मैं यह बताना चाहती हूं कि इंडारे पेशेंटस इस वक्त इतने नहीं हैं, इसलिए वहां पर इंडोर पेशेंटस का प्रोविजन नहीं किया गया है।

Government Seed Farm Charaunda

***122. Lala Rulya Ram;** Will the Minister for Agriculture be pleased to state the total areea in acres under cultivaiton of Potato, tomato and lady finger crops in Government seed Farm Gharaunda during the years 1971-71, 1971-72, separately and the years wise total income from each such crops vis a vis expenditure separately ?

कृषि मंत्री (चौधरी भजन लाल):

वर्ष	फसल का नाम	क्षेत्र एकड़–कनाल	खर्चा	उत्पादन की कीमत
1970–71	1. आलू	12–4	24795	37729
	2. टमाटर	2–3	1762	3440
	3. भिण्डी	6–3	4405	2622/– (2एकड क्षे की फसल वर्षा से पपडी जम जाने के कारण नहीं उगी तथा 1.5 एकड क्षेत्र में भारी वर्षा से फसल सडने के कारण हल चलाया गया अत 3.5 एकड क्षेत्र में कोई फसल नहीं हुई)
1971–72	1. आलू	15–2	40609	53050
	2. टमाटर	3–3	3425	8692
	3. भिण्डी	8–3	7505	9191

चौधरी दल सिहं: क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि इस सीड फार्म से 1970–71 में क्या आमदनी हुई, क्या खर्चा हुआ और क्या घाटा हुआ है या फायदा हुआ है ?

चौधरी भजन लाल: स्पीकर साहब, 1970–71 में इस सीड फार्म से 3133 रूपय का घाटा रहा है। इस घाटे के कुछ

कारण हैं एक बात तो यह है कि सीड फार्म, कोई प्रोफिट कमाने के लिए नहीं होता। सीड फार्म का मकसद यह है कि किसान को अच्छे बीज दिये जायें और इसी परपज के लिये सीड फार्म बनाए जाते हैं। पिछले साल में नुकसान हुआ तो उससे अगले साल 1971–72 में 16800 रूपये का प्रोफिट भी हुआ है।

पंडित चिरंजी लाल शर्माः मंत्री महोदय ने यह बताया कि सीड फार्म किसी मकसद के लिये होते हैं। जब पिछली बार 16800 रूपये का फायदा हुआ है तो उससे पहले 3 हजार 133 रूपये को नुकसान क्यों हुआ है ? क्या इसके रीजंज जानने की कोशिश की गयी है ?

चौधरी भजन लालः स्पीकर साहब, बात ऐसे हैं कि साढे चार एकड क्षेत्र में भिण्डी बोयी गयी थीं उसमें से कुछ पौधों को ऐसी बीमारी लगी कि भिण्डी का बीज बन नहीं पाया। इसी तरह से आलू में कुछ ऐसी बीमारी पडी कि सीड कम पैदा हुआ।

पंडित चिरंजी लाल शर्माः क्या मंत्री महोदय यह बताने का कष्ट करेंगे कि सीड फार्म की एस्टैब्लिशमैंट पर कितना खर्चा है ?

चौधरी भजन लालः इस पर खर्चा है 17465 रूप्ये

चौधरी दल सिंहः स्पीकर साहब, पिछले साल किसानों को जो बीज मिला और खास तौर पर बाजरे का । वह इतना रद्दी था कि उससे हरियाणा स्टेट में करोडों रूपये का नुकसान हुआ

है। क्या गर्वमैंट के अंडर कंसीड्रेशन कोई ऐसी स्कीम है कि बजाये इसके कि ये बीज बाहर से या प्राईवेट आदमियों से लिये जायें, गवर्नमैंट ये अपने सीड फार्म से या अपनी एजेंसियों की फार्मत किसानों को दे ?

चौधरी भजन लालः स्पीकर साहब, जहां तक बाजरे के बीज का ताल्लुक है। हम बाजरे की सीड नहीं बनाते। यह बीज नेशनल सीड कारपोरेशन आफ इंडिया स्टैट को भेजती है। मगर सरकार ने इस बारे में पूरी कोशिश की है ओर हम हिसार में 1500 एकड का बाजरे का सीड बनाने के लिये एक फार्म बनाने जा रहे हैं इस कार्य के लिए सरकार ने अभी जगह ली है।

श्रीमती चन्द्रावतीः क्या वजी साहब यह बतायेंगे कि गवर्नमैंट के पास कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे वे फार्म को ठीक तरह से एडमिनिस्टर कर सकें ताकि यह फार्म लाभ में चल सकें

चौधरी भजन लालः इसके लिये सरकार अपनी पूरी कोशिश कर रही है।

श्री अमर सिंहः क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि इस सीड फार्म के पास कुल कितनी जमीन है और उसमें से कितनी अंडर कल्टीवेशन है और कितनी बाहर है ?

चौधरी भजन लालः इस घरौंडा सीड फार्म के पास कुल 23 एकड जमीन है। डेढ एकड जमीन पर बिल्डिंग में आफिस बना हुआ है और लगभग 22 एकड जमीन में कल्टीवेशन होती है।

लाला रूलिया रामः क्या मंत्री महोदय बतायेंगें कि 1970–71 वर्ष के अंदर 12 एकड 4 कनाल भूमि के अंदर जो आलू बोये गये थे, उनकी पैदावार का वजन कितना था ?

चौधरी भजन लालः यह है 666 क्विंटल और 62 किलोग्राम।

श्री अमर सिंहः मंत्री महोदय ने अभी यह फरमाया था कि 1970–71 में हुए नुकसान का कारण यह था कि बीज खराब हो गया था। क्या मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि इस चीज की जिम्मेदारी किस अफसर पर डाली गयी है ?

चौधरी भजन लालः स्पीकर साहब, इसमें जिम्मेदारी इसलिये नहीं डाली जाती क्योंकि इसका कारण बरसात न होगना, खराब हवा और मौसम या बीमारी का लगना हो सकता है।

चौधरी दल सिंहः स्पीकर साहब, आम तौर पर यह देखा जाता है कि जब से ये बीज दुकानदारों के पास से मुहैया होने शुरू हुए हैं, तब से इन बीजों से बडा भारी नुक्सान हुआ है, इसलिये क्या गवर्नमैंट कोई ऐसा इरादा रखती है कि सब दुकानदारों को बेचने से मना करके सारा बीज गवर्नमैंट अपनी

एजेसिंज से ही किसानों को मुहैया करवाये ? क्या सरकार इस तरह से किसानों को बीज देने के लिए तैयार है ?

चौधरी भजन लालः स्पीकर साहब, वैसे तो हम प्राइवेट दुकानदारों द्वारा इनका बेचना बंद नहीं कर सकते लेकिन हम गवर्नमैंट द्वारा पैदा किये गये सीडज पर अपनी मोहर लगाने को इरादा रखते हैं

लाला रूलिया रामः स्पीकर साहब, मंत्री महोदय ने यह फरमाया है कि वर्ष 1970–71 में आलू खराब हो गया था, इसलिये नुक्सान हुआ। क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि कितना आलू खराब हुआ या और कितना फरोख्त हुआ ?

चौधरी भजन लालः स्पीकर साहब, हमने उसमें से 211 क्विंटल के करीब आलू मोर्किट में फरोख्त किये थे और 319 क्विंटल के करीब बीज के रूप में बेचे थे।

श्री उमेद सिंहः क्या मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि जहां पर सरकार के द्वारा या नैशनल सीड कारपोरेशन के द्वारा किसानों को बीज दिये जाते हैं ? और उसमें बीमारी लग जाती है सरकार की उन्हें कोई मुआविजा देने की स्कीम है ?

चौधरी भजन लालः ऐसी कोई प्रोपोजल नहीं है।

पंडित चिरंजी लाल शर्माः क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगें कि आलू या भिण्डी में जो नुकसान हुआ है, उससे भविष्य में बचने के लिये गवर्नमैंट ने क्या स्टैपस उठाये हैं ?

चौधरी भजन लालः इसके लिये हमने कीटनाशक दवाईयों का प्रबंध किया है। जिन सीडज पर यह बीमारी लगती है, उन पर अब कीटनाशक दवाईयों का इस्तेमाल किया जा रहा है।।

चौधरी शिव राम वर्माः स्पीकर साहब, यहां पर सीड फार्म का जिक्र चल रहा है। सारी स्टेट में तोरिये का बीज नहीं है और तोरिये के बीज की बहुत कमी महसूस हो रही है, यह बीज कहीं नहीं मिलता। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या इसके लिये कोई प्रबंध किया जा रहा है ? इसके साथ ही यह भी पूछना चाहता हूं क्योंकि पिछले साल आलू का बीज खराब हो गया, इसलिये अगले सीजन के लिये आलू के अच्छे बीज मुहैया करने के लिये क्या कोई प्रबंध किया जा रहा है ?

चौधरी भजन लालः स्पीकर साहब, आलू के बीज की कमी को महसूस नहीं किया जा रहा। आलू का बीज सब जगह अवेलेबल है। यह बीज तो प्राइवेट लोगों के पास भी है और सरकार के पास भी है और काफी मात्रा में अवेलेबल है। हमारी जानकारी के अनुसार आलू के बीज की कोई कमी नहीं महसूस की जा रही है लेकिन अगर आनरेबल मैम्बर कहीं कहेंगे कि वहां पर बीज की कमी है तो हम वहां पर यह बीज फौरन भिजवा देंगे।

तोरिये के बीज के बारे में, सरकार के पास ऐसी कोई शिकायत महसूल नहीं हुई है कि कहीं पर इस बीज की कमी हैं अगर आनरेबल मैम्बर हमें यह लिखकर भेजेंगे कि इस इस इलाके में बीज की कमी है, तो सरकार वहां पर बीज का इंतजाम करने की पूरी कोशिश करेगी।

चौधरी शिव राम वर्माः स्पीकर साहब, मैं जो इन्हें बता रहा हूं कि वहां पर तोरिये के बीज की बहुत कमी है .....

चौधरी भजन लालः आपने तो अभी बताया है, पही कभी नहीं कहा।

चौधरी शिव राम वर्माः स्पीकर साहब, मैं हिसार तक फिर आया हूं इस बीज के लिये, लेकिन मुझे यह हिसाचर यूनिवर्सिटी में भी नहीं मिला।

श्री अध्यक्षः आप इनके नोटिस में लाइये, ये इंतजाम करेंगे। (व्यवधान)

श्रीमती चन्द्रावतीः वजीर साहब ने यह बताया है कि घाटा बीमारी की वजह से हुआ है, क्या वह अब यह कोशिश करेंगे कि आगे को घाटा न हों ? क्या वजीर साहब यह भी तलाश करेंगे कि किसी प्राईवेट फार्म में भी उसी वक्त यह चीजें बोयी गयीं और उन्हें इससे घाटा रहा या फायदा ?

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, यहां पर गवर्नमैंट के सीड फार्म का जिक्र है, प्राइवेट फार्म का नहीं। फिर भी मैं बता देता हूं कि कई बार ऐसा होता है कि एक जगह बीमारी लग जाती है और दूसरी जगह नहीं लगती। इसलिये हो सकता है इसमें कोई फर्क रह जाये।

श्री अमर सिंहः स्पीकर साहब, मंत्री महोदय ने अपने जवाब में यह बताया है कि 1970–71 में 12 एकड 4 कनाल में आलू बोये गये थे। आलू का बीज खराब होने की वजह से घाटा हो गया। क्या मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि इंक्वायरी से यह साबित हो गया है कि वह जो आलू का बीज था, वह एडल्ट्रेटिड था ?

चौधरी भजन लालः ऐसा कुछ साबित नहीं हुआ।

चौधरी मेहर चन्दः क्या मंत्री महोदय with particular reference to the Gharaunda farm establishment यह बतायेंगे कि 1970–71 और 1971–72 में इस फार्म की एसटैबलिशमैंट पर जो खर्च हुआ है, उसका टेक अप क्या है ? इसके साथ ही वे यह भी बतायें कि इसमें सुपरवाइजरी चार्जिज इन्कल्यूडिड हैं या नहीं ?

चौधरी भजन लालः स्पीकर साहब, फार्म पर सारा खर्च लगा कर ही प्रोफिट गिना जाता है। ..... (शोर).....

चौधरी मेहर चन्दः स्पीकर साहब, मेरा पर्टीकुलर क्वैश्चन है कि क्या इसमें सुपर वाइजरी चार्जिज इन्क्ल्यूडिड हैं या नहीं ? (विघ्न)

चौधरी भजन लालः जी हां, इन्कल्यूडिड हैं (श्री मेहर चंद जी की ओर से विघ्न)

श्री अध्यक्षः चौधरी साहब, इन्होंने यह बताया है कि इन्क्ल्यूडिड हैं।

Ch. Mehar Chand: May I know the break up of the expenditure in both the years, if all the expenditure is included ?

चौधरी भजन लालः स्पीकर साहब, मैंने पंडित चिरंजी लाल शर्मा के एक सवाल के जवाब में यह बताया है कि एस्टैब्लिशमैंट पर कितना खच्र है। कुल खर्चे में सुपरवाइजरी चार्जिज भी इंकल्यूडिड हैं (और कुल खर्चा जवाब में दिया हुआ है)

श्री अध्यक्षः चौधरी साहब, इन्होंने यह फरमाया है कि उसमें सुपरवाइजरी चार्जिज भी इन्कल्यूडिड हैं।

चौधरी पीर चन्दः क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जो सीड आप हरियाणा में तैयार कर रहे हैं अगर वह सारे हरियाणा के लिए काफी न हों तो क्या आप बाहर से मंगाएंगे ?

मुख्य मंत्री (चौधरी बंसी लाल): जो बीज यहां होता है वहीं पूरा नहीं उठता फिर बाहर से मंगाने का सवाल ही क्या है।

चौधरी राम लाल वधवा: जैसा कि मंत्री महोदय ने फरमाया कि काफी खराब हो गया तो क्या खराब होने से बचाने के लिए कोई सांइंटिफिक तरीका अपनाया गया है जिससे कि बीज खराब न हो और किसानों को बीज समय पर मिल सके ?

श्री अध्यक्ष: यह तो पहले ही जवाब दिया जा चुका है कि कोशिश की जा रही है कि बीमारी न लगे।

चौधरी राम लाल वधवा: क्या तरीका अपनाया गया है ?

श्री अध्यक्ष: कीट नाशक दवाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं और दूसरे तरीके अपना रहे हैं

राव बंसी सिंह: जैसा कि अभी बताया गया कि पिछले साल बाजरे का सीड खराब हो गया तो क्या उन कम्पनीज के खिलाफ एक्शन लिया गया है ? और अब की बार जो सीड किसानों को सप्लाई किया गया है क्या वह टैस्ट कर लिया गया है कि उसमें कोई खराबी तो नहीं है ?

चौधरी भजन लाल: स्पीकर साहब, वैसे तो इस सप्लीमैंटरी का क्वैश्चन से काई संबंध नहीं है लेकिन फिर भी मैं माननीय सदस्य को बता देता हूं कि पिछले साल बाजरे का जो बीज खराब हो गया था वह नम्बर का था। हमने किसानों को बता

दिया था कि एक और तीन नंबर का बीज बोओ, इसमें खराबी नहीं है। स्पीकर साहब, जो भी बीज आता है वह कारपोरेशन आफ इंडिया द्वारा सप्लाई किया जाता है और उस पर कारपोरेशन नैशनल सीड की मुहर लगी होती है। वे बाकायदा उसको टैस्ट करते हैं और सरकार भी उसको टैस्ट करती है उसके बाद ही हम किसानों को देते हैं।

श्री हरि सिंहः क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सीड की प्रोडक्शन में हमारी स्टेट देश के दूसरे सूबों के किस सीरियल नम्बर पर है और अगर वह देश के किस सीरियल नम्बर पर है और अगर वह देश के दूसरे सूबों से पीछे हैं तो क्या सरकार सीड की उपज बढानें की कोशिश कर रही है ?

चौधरी भजन लालः वैसे तो यह पता नहीं लग सकता कि हमारी स्टेट किस नंबर पर है क्यौंकि मेरे पास इसका जवाब नहीं लेकिन हरियाणा दूसरे सूबों से पीछे नहीं है।

Facilieties to High Schools

***69. Sh. K.N. Gulati:** Will the Chief Minister be please to state-

(a) whether it is a fact that Government Basic Middle School for girls in No. 5 area N.I.T., Faridabad, has been upgraded to High School; and

(b) If so, the time by which the facilities like Office Clerk and phone etc. which are enjoyed by other High Schools will be provided to the School referred to in part (a) above ?

Home Minister (Sh. K.L. Poswal):

(a) Yes.

(b) Post of Clerk is provided in High School and in due course of time Clerks will be appointed. Telephone is not provided in High Schools.

श्री के0एन0 गुलाटीः इस हाई स्कूल में बाउंडरी वाल की कमी है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि यह बाउंडरी बाल का काम कब तक पूरा हो जाएगा ?

श्री के0एल0 पोसवालः सवाल तो स्कूल के अपग्रेड करने तथा क्लर्क के बारे में था यहां बाउंडरी वाल इसमें कहां आती है ?

श्री के0 एन0 गुलाटीः सवाल के आखिर में 'एकस्ट्रा' लिखा है उसमें यह कवर हो जाता है।

Ch. Bansi Lal The Hon. Member is very relevant that the workd etc. is there in the question. But he should recollect the proceedings of the other day, of this House when there was a question regarding boundary walls etc. of schools.

Primary Health Units etc. in the State

***123. Lala Rulya Ram:** Will the Chief Minister be please to state-

(a) the total number of Primary Health Units which were functioning in the State distrrict wise during 1971-72;

(b) the total number of working Family Planning Centres in each district of the State;

(c) the total number of Vasectomy/Tubectomy cases entertained by each unit together with the target set up by the Government for the same; and

(d) the total expendiutre incurred by the Government on the said Centres ?

Deputy Minister Health(Smt. Sharda Rani):

(a) & (b): A statement containing the requisite information is given in Statemetn 'A'.

(c) The total number of cases entertianed by these Units during 1971-72 was 46453 as against the target of 28350. A statement showing Unit wise break up is given below (Statement-B)

(d) Rs. 56 lacs.

STATEMENT 'A'

Statement showing the total number of Primary Health Units/Centres functiioning in various districts during 1971-72

Name of the district	Number of Primary Health Units	Number of Family Planning Centres, both Rural & Urban
Ambala	8	15
Gurgaon	16	23
Hissar	18	25
Jind	6	6
Karnal	16	22
Mohindergarh	9	12
Rohtak	16	21
Total	89	124

STATEMENT 'B'

Targets and achievement of Sterilization in Haryana during 1971-72 by Family Planning Centres and other institutions

Distt./ P.H.C.	Targets	Vasectomy	Achievements Tubectomy	Total

1. Ambala District (a) Rural Centres				
1 Bilaspur	185	44	193	237
2 Naggal	335	66	239	305
3 Mulana	317	42	218	340
4 Mustafabad	277	141	162	303
5 Raipur Rani	255	33	334	367
6 Pinjore	115	59	116	175
7 Sadhaura	274	26	343	369
8 Khizrabad	192	39	211	250
(b) Urban Centres				
9 Ambala Cantt.	184	91	159	250
10 Ambala Cantt. (Mission)	68	10	77	87
11 Ambala City	68	5	23	28
12 Kalka	32	7	7	14
13 Yamuna Nagar	92		43	43
14 Ambala City	68	68	77	145
15 Jagadhri	51	18	69	87

Other Hospital & Dispensaries	427	207	236	443
Total	2940	856	2507	3363
2. Gurgaon District (a) Rural Centres				
1. Farakh Nagar	171	327	22	349
2. Bhora Kalan	185	143	17	160
3. Gangola	185	433	12	445
4. Pataudi	180	617	30	647
5. Guraora	174	415	27	442
6. Khol	175	817	13	830
7. Bawal	175	322	25	347
8. Nuh	324	544	4	558
9. Mandkola	223	323	12	335
10. Nagina	232	361	9	370
11. Punhana	232	194	2	196
12. Hassanpur	171	161	36	197
13. Aurangabad	171	176	17	193
14. Dudola	165	363	24	387

15. Ballabgarh	180	747	47	794
16.Tigaon	180	5	29	34
(b) Urban Centres				
17. Rewari	50	7	22	29
18. Hodel	30	1	1	2
19. Sohna			1	1
20. Palwal	25	1	13	14
21. Faridabad (Sewa Samiti)	50	9		9
22. Faridabad	125	420	22	442
23. Gurgoan	50	22	16	38
Other Hospital & Dispensaries	1134	3171	319	3490
Total	4587	9589	720	10309
3. Hissar District (a) Rural Centres				
1. Mangali	250	460	136	596
2. Siswal	200	77	197	274
3. Barwala	200	275	183	458
4. Jakhal	300	142	193	335

5. Sisai Bola	250	595	157	752
6. Sorkhi	350	469	148	617
7. Khanda Kheri	150	456	144	600
8. Mirchpur	100	148	94	242
9. Kairu	150	112	113	225
10. Tosham	200	137	127	264
11. Naahpur	150	69	30	99
12. Bhattu Kalan	250	55	266	321
13. Bhuna	300	196	259	455
14. Ratia	300	116	320	436
15. Madho Sighana	350	86	271	357
16. Bada Gudha	150	43	163	206
17. Rania	250	47	312	359
18. Odhan	250	43	298	341
(b) Urban Centres				
19. Sirsa	132	31	55	86
20. Dabwali	50	8	39	47

21. Fatehabad				
22. Tosham				
23. Hansi	200	129	78	207
24. Bhiwani	50	14	34	48
25. Hissar	75	31	55	86
Other Hospital & Dispensaries	2486	562	679	1241
Total	7143	4301	4351	8652
4. Jind District (a) Rural Centres				
1. Julana	260	826	88	914
2. Samlikalan	125	179	39	218
3. Safidon	300	730	112	842
4. Kalayat	302	482	185	667
5. Ujhana	260	320	91	411
6. Gogarian	200	218	140	358
Other Hospital & Dispensaries	275	2048	293	2341
Total	1722	4803	948	5751
5. Karnal District				

(a) Rural Centres				
1. Indri	299	67	117	184
2. Bapauli	355	137	25	162
3. Siwan	352	174	142	316
4. Pehowa	246	204	144	348
5. Jhansa	275	41	152	193
6. Samalkha	177	217	111	328
7. Gharaunda	163	102	70	172
8. Ahar	278	91	41	132
9. Assandh	341	153	165	318
10. Nissing	306	109	103	212
11. Rajaund	295	239	140	379
12. Guhla	391	204	149	353
13. Nilikheri	382	77	115	192
14. Radaur	292	73	322	395
15. Kaul	306	127	102	229
16. Ballah	163	68	38	106
(b) Urban Centres				
17. Panipat		53	24	77

18. Karnal	127	6	40	46
19. Kaithal		1	12	13
20. Shahbad	15	5	29	34
21. Ladwa				
22.Karnal (Govt.)	127	31	46	77
Other Hospital & Dispensaries	446	754	536	1290
Total	5336	2933	2623	5556
6. Mohindergarh District (a) Rural Centres				
1. Dochana	137	962	6	968
2. Ateli	216	808	17	825
3. Nangal Choudhri	216	559	1	560
4. Kanina	125	483	8	491
5. Sahlong	108	437	34	471
6. Satnali	208	273	9	282
7. Baund Kalan	254	307	80	387
8. Jhojhu Kalan	162	405	72	477

9. Gopi	197	194	8	202
(b) Urban Centres				
10. Mohindergarh				
11. Dadri				
12. Narnaul				
Other Hospital & Dispensaries	215	403	77	480
Total	1838	4831	312	5143
6. Mohindergarh District (a) Rural Centres				
1. Kaloi	330	434	249	683
2. Kalanaur	280	131	172	303
3. Kharkhoda	190	124	220	344
4. Sampla	161	209	155	364
5. Gohana	226	360	172	532
6. Mundhana	220	164	134	298
7. Madina	227	155	205	360
8. Kathura	223	181	126	307
9. Chhara	280	296	104	400

10. Badli	260	341	138	479
11. Dhakla	245	207	53	260
12. Nahar	230	238	138	376
13. Dighal	200	300	121	421
14. Juan	300	164	72	236
15. Ganaur	281	223	50	273
16. Halalpur	329	81	182	263
(b) Urban Centres				
17. Jhajjar	50	5	48	53
18. Bahadurgarh	40	50	58	108
19. Rohtak	100	153	66	319
20. Sonepat	75	112	8	120
21. Rohtak (Medical College)	100	134	183	317
Other Hospital & Dispensaries	437	490	373	863
Total	4784	4552	3127	7679
Grand Total	**28350**	**31856**	**14588**	**46453**

कार्य मन्त्रणा समिति का तृतीय प्रतिवेदन

श्री अध्यक्षः मैं बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की तीसरी रिपोर्ट पेश करता हूं। जो इस प्रकार है :

The Committe, after some discussion, recommended that the business on Monday, the 21 st August, 1972, be transacted as follows :-

(1) Questions Hour.

(2) Papers to be laid on the Table.

(3) Discussion and voting on the Supplementary Estimates (First Instalment) 1972-73.

(4) Inroduction, consideration and passing of the Punjab Motor Spirit (Taxation of Sales) Haryana Amendment Bill, 1972.

(5) Official Resolution regarding the enhancing of borrowing limit of loans by the Haryana State Electricity Board.

(6) Discussion on the Annual Administration Report ot the Haryana State Electricity Board for the year 1971-72, which was laid on the Table of the House on the 16th August, 1972.

Home Minister (Sh. K.L. Poswal): Sir, I beg to move-

That this House agrees with the recommendations contained in the Third Report of the Business Advisory Committee.

श्री अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआः—

कि यह सदन कार्य मन्त्रण समिति के तृतीय प्रतिवेदन में दी गई सिफारिशें स्वीकार करता है।

श्री अध्यक्षः प्रश्न यह हैः—

कि यह सदन कार्य मन्त्रण समिति के तृतीय प्रतिवेदन में दी गई सिफारिशें स्वीकार करता है।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

मेज पर रखे कागज पत्र

Deputy Minister Health(Smt. Sharda Rani): Sir, I beg to lay on the Table a copy each of the following notifications :-

(1) Notification No. 1450-Pol(2P)-72, dated the 4th April, 1972, regarding the Haryana Ministers Travelling Allowances Rules 1972, as required under Section 9(2) of the Haryana Salaries and Allowanceds of Ministers' Act, 1970.

(2) Nofication No. 1462-Pol(2P)-72, dated the 4th April, 1972, issued under Article 283(2) of the Constitution of India.

वर्ष 1972–73 के अनुपूरक अनुमान (प्रथम किश्त)

(1) राज्य के राजस्वों पर प्रभृत व्यय के अनुमानों पर चर्चा

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्य अगर चार्ज्ड मदों पर चर्चा करना चाहते हैं तो वे बोल सकते हैं

(कोई सदस्य बोलने के लिये खडा नहीं हुआ)

(2) अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान

Chief Minister (Ch. Bansi Lal): Sir, I suggest that all the demands should be considered to have been read and moved.

श्री अध्यक्षः पूर्व प्रथा के अनुसार तथा सदन का समय बचाने के लिए सभी अनुदानों की मांगगे पढी तथा प्रस्तुत की गई समझी जाएंगी, माननीय सदस्य मांगों पर चर्चा उठा सकते हैं किन्तु बोलते समय उन्हें मांग का डिमंड नंबर बताना होगा जिस पर कि वे चर्चा उठाना चाहते हैं सभा के उठने के सामान्य समय से डेढ घंटा पूर्व विवाद बंद कर दिया जाएगा।

कि एक अनुपूरक रकम, जो 123870 रूपये से अधिक न हो, 9–भू–राजस्व के सम्बंध में 31 मार्च, 1973 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को देने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक रकम, जो 654000 रूपये से अधिक न हो, '18—संसद' के सम्बंध में 31 मार्च, 1973 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को देने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक रकम, जो 70000 रूपये से अधिक न हो, '22—जेलें' के सम्बंध में 31 मार्च, 1973 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को देने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक रकम, जो 10 रूपये से अधिक न हो, 'सिंचाई स्थापना पर प्रभार' के सम्बंध में 31 मार्च, 1973 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को देने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक रकम, जो 1750000 रूपये से अधिक न हो, '50—लोक निर्माण कार्य' के सम्बंध में 31 मार्च, 1973 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को देने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक रकम, जो 10 रूपये से अधिक न हो, '70—वन' के सम्बंध में 31 मार्च, 1973 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को देने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक रकम, जो 1250010 रूपये से अधिक न हो, '71—विविध' के सम्बंध में 31 मार्च, 1973 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को देने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक रकम, जो 79100000 रूपये से अधिक न हो, '98—बहुउद्देशीय नदी स्कीमों पर पूंजीगत परिव्वय' के सम्बंध में 31 मार्च, 1973 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को देने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक रकम, जो 10 रूपये से अधिक न हो, '99—सिंचाई इत्यादि निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय (वाणिज्यिक)' के सम्बंध में 31 मार्च, 1973 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को देने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक रकम, जो 100 रूपये से अधिक न हो, '103—लोक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय' के सम्बंध में 31 मार्च, 1973 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को देने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक रकम, जो 10 रूपये से अधिक न हो, 'स्थानीय निधियों तथा गैर सरकारी पार्टियों आदि को कर्जे' के सम्बंध में 31 मार्च, 1973 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के

क्रम में आने वाले खर्चों को देने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

चौधरी रिज़क राम (राई): स्पीकर साहब, यह सप्लीमैंटरी डिमंडज जो हाउस के सामने पेश हुई हैं उनका ज्यादातर रूपया केन्द्रीय सरकार से मिलना है और उन डिमांडज के लिए रूपया मांगा गया है। जो मांगे हमारे सामने आई हैं उन पर मैं संक्षेप में चर्चा करना चाहता हूं। स्पीकर साहब, आप देखेंगे कि इन मांगों में कृषि संगणना के बारे में रूपए की मांग की गइ है और उसके साथ साथ रूरल इंजीनियरिंग सर्वे के बारे में भी मांग की गई है। यह दोनों ऐसी मांगें हैं जिनका कृषि से और देहात के जीवन से और खुशहाली से ताल्लुक है और मैं समझता हूं कि इन मांगों के लिए रूपए की मंजूरी तथा इनमें रूपया लगाना निहायत आवश्यक है। आप देखेंगे कि आजादी के 20–25 साल के बाद कृषि उत्पादन में अभी तीन चार साल से बहुत उन्नति हुई है। इससे पहले हमें काफी अनाज विदेशों से मंगाना पडता था और अब उन्नत बीज और दूसरे तरीके अख्तियार करने के बाद जिन में पानी का इंतजाम भी है, नल कूप भी हैं इत्यादि। ये सारे प्रबंध होने के कारण, आज यह देश खुराक के मामले में आत्मनिर्भर हैं लेकिन मैं ऐसा सोचता हूं कि अनाज का काफी उत्पादन होने के बावजूद भी इस संबंध में देश के किसानों को और इस सरकार को अभी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है और इसके जो प्रोवीजन कृषि संगणना या इंजीनियरिं सर्वे के बारे में

भी रखे हैं, निहायत ही जरूरी हैं। आज हम देखते हैं कि इस दौरान जबकि रासायनिक खाद भी हैं, खेती के लिये उन्नत बीज भी है, पानी का इंतजाम भी है और बिजली की खपत भी हे, इस किस्म के सारे साधन जुटाये हुए हैं तो इसके साथ साथ कई मसले किसानों के लिये पैदा हो गये हैं और उनकी पूरी जांच करने के लिये, जैसा कि इस बजट की मांगों में दिया गया है, निहायत ही आवश्यक हैं लेकिन मैं पहले एक बात कहना चाहता हूं कि जो कृषि संगणना के बारे में पटवारी, गिरदावर या तहसीलदार आदि के द्वारा यह जांच कराने का कार्यक्रम रखा गया है, इससे कोई मतलब हल होने वाला नहीं। जो भी रिकार्ड है वह 16वीं सदी में अंग्रेजों ने सिर्फ माल वसूल करने के लिये तैयार किया था। उस सारे रिकार्ड में ऐसी बातें हैं जिससे सरकार की मालिया की वसूली के लिये तैयार किया था। उस सारे रिकार्ड में ऐसी बातें हैं जिससे सरकार की मालिया की वसूली की चोरी नहीं हो सकती हैं एक एक इंच भूमि का मालिया सरकार को वसूल होता रहे चाहे कल्लर हो, चाहे बंजर हो। इस लिहाज से वे रिकार्ड तैयार करवाते थे और जो उत्पादन में हम बढौतरी करना चाहते हैं, कृषि के क्षेत्र में हम तरक्की करना चाहते हैं, इसके लिये हमारा जो रिकार्ड तैयार करवाय जाएगा वह काफी नहीं होगा। आज दूसरी बातें भी पैदा हुई कि जहां तक इस रिकार्ड की पटवारी और गिरदावर की जिम्मेवारी है या तहसीलदार की, एस0डी0ओ0 और डी0सी0 वगैरह उसे चैक करते हैं और फाइनैंशीयल कमिश्नर तक एक एडमिनिस्ट्रेशन सेट अप बना हुआहै

और आज जब से यह देश आजाद हुआ है, तब से भूमि सुधार कानून की चर्चा हुई और इस लैंड रिकार्ड के बारे में जो सैंकटिटी थी वह न रही। बल्कि आज मालिक या दूसरे लोग पटवारियों से मिल कर पैस वगैरह देकर गलत इन्राज तैयार करवाते हैं ऐसी बात नहीं कि यह बात सरकार के नोटिस में नहीं है।

श्री अध्यक्षः चौधरी साहब, यह कौन सी डिमांड नम्बर है, जिस पर आप बोल रहे हैं।

चौधरी रिज़क राम : स्पीकर साहब, डिमांड नं0 9 सीरियल नं0 11 स्पीकर साहब, सरकार के नोटिस मैं भी यह बात आई कि पटवारियों से मिल कर लोग सारा रिकार्ड गलत करवा रहे हैं। इसी कारण से इनहेंनें लैंड रिकार्डज मैनुअल में तरमीम की और तहसीलदारों को यह अख्तियार दिये कि वह दरख्वास्त आने पर अन्दराज को दुरूस्त कर सकते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि इससे जो इनका मतलब था, वह भी पूरा नहीं होता। आज दरख्वास्तें देने पर बाकायदा मुकद्दमें चलते हैं, गवाह पेश होते हैं। दोनों तरफ मुजारे और मालिक के दरम्यान झगडा होता है। मुजारे के हक में कोई आदमी गवाही देने के लिये आगे नहीं आता। झगडे बढते जाते हैं और इसके इलावा और भी केई किस्म की कठिनाईयां आती हैं। मेरा तो ऐसा विचार है कि कब्जे के बारे में गिरदावरी का जो सिस्तट है, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। इसको गौर से देखा जाए। सरकार का यह काम नहीं है कि वह रिकार्ड को तैयार करवाए और वह इसकी जांच करवाये कि जमीन

पर किस आदमी का कब्जा हैं मलकीयत का रिकार्ड तो ठीक है कि सरकार रखे या देखें लेकिन कब्जा किस का है, इससे सरकार का ज्यादा ताल्लुक नहीं होना चाहिये। स्पीकर साहब, आप शहरों में देखते हैं कि लोग लाखों, करोडों की जायदादें लिये बैठे हैं, और उनमें किरायेदार रहते हैं और सरदार उसका कोई रिकार्ड नहीं रखती। जिस वक्त किरायेदार मकान किराये पर लेता है तो आपस में पटटा लिखते हैं। स्पीकर साहब, मैं एक और बात कहना चाहता हूं कि 1873 में जब वेस्ट बंगाल में परमानेन्ट सैटलमैंट लाई गई थी तो उस वक्त अंग्रेजों का राज था। उनके राज्य में भी ऐसा किया गया था कि गिरदावरी की कोई जरूरत नहीं थी, जो भी काश्त के लिये जमीन लें, उसके लिये पटटा लिखवाना आवश्यक कर दिया गया था और वह पआा मालिक अगर कब्जे के बारे में हो तो वह अदालत में सबूत देकर उसको ठीक करवा सकता है। लेकिन आज कब्जें के बारे में सैंकडों केसिज चली रहे हैं। कोई तो अपना कब्जा बताताच है, पटवारी किसी का कब्जा बताता है। 107, 145 के मुकद्दमें चलते हैं, दिवानी या फौजदारी होती है और इन की वजह से कतल भी होते हैं। ऐसी सूरत बनी हुई है, जिसमें कभी कभी बडी मुशकिल होती है। पटवारी जितना रूपया मांगता है, उसे उतना ही मिलता है। कब्जा किसी को होता है, रिकार्ड में किसी का इन्दराज करते हैं। राजस्थान में भी लैंड रिफार्मज एक्ट के बारे में चर्चा हुई थी तो उस वक्त उन्होंने भी कब्जें के बारे में गिरदावरी इन्दराज का प्रोवीजन खत्म कर दिया था। यह मैं आपके द्वारा सरकार को बताना चाहता था। शुरू शुरू

में थोड़ी सी मुश्किल आ सकती है कि जो लोग कब्जे की बिना पर मारूसियत के अधिकार प्राप्त करना चाहें, उनके लिये कब्जे का सबूत देने में कठिनाई आ सकती है मगर यह सबूत भी पटटे के द्वारा पेश कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि गिरदावार और पटवारी के द्वारा जो ये जांच कराना चाहते हैं, उसके लिए जो लैंड रेवेन्यू एक्ट है, उसमें संशोधन की जरूरत है। इसको देखने की जरूरत इसलिये है कि कोई तरमीम से किसानों को देहातों में फायदा हो सकता है ? दूसरा मैं समझता हूं कि यह तो कृषि संगणना का काम है। इसको पटवारियों के द्वारा करवाने से मकसद हल नहीं हो सकता क्योंकि इसको सारे का सारा रिकार्ड पहले ही सरकार के पास है। इसके साथ इंजीनियरिंग सर्वे की भी मांग की गई है, वह ज्यादा जरूरी है क्योंकि आज हम जहां कृषि के क्षेत्र में इतनी उन्नति पर पहुंचे हैं इसके साथ साथ यह भी देखने की बात है कि रासायनिक खाद आदि के प्रयेाग से भूमि के उपजाऊपन में कमी तो नहीं आती है। आगे देखने की बात तो यह है कि हमारी जो जमीन है, वह किस किस्म की है। आज हरियाणा में तो ऐसी कठिनाई की बात नहीं क्योंकि हम देखते हैं कि इसमें ज्यादातर भूमि ऐसी है, जिस में नमी भी है, रेतीली भी है। (इस समय उपाध्यक्षा पदासनी हुई) मगर देखने की बात यह है कि हमारे प्रान्त में जो गांवों में भूमि हैं उसमें कौन कौन से मिनरल्ज हैं, कितनी परसैंटे पोटाश की है, कितना फास्फोरस हैं, कितना लाईम है और किस किस्म की आर्टीफिशियल फर्टेलाईजर डालने से वह जमीन ज्यादा उपज देने के काबिल बन सकती हैं। डिप्टी स्पीकर

सहिबा, आज हमारे किसानों को यह सब मालूमात हासिल नहीं हैं, हमारे जो बी0डी0 ओज और एग्रीकल्चर इन्सपैक्टर हैं उनको भी इसके बारे में कुछ मालूम नहीं है, बाकी पटवारियों और गिरदावरों के जानने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। गेर्ज कि हमारे पास कोई भी ऐसा अफसर नही ंहे, चाहे वह बी0डी0ओ0 है, एस0डी0ओ0 है या जिला में बैठा हुआ डिप्टी कमिश्नर है, जो यह बता सके कि फलां गांव की इतनी भूमि ऐसी है जिसमें नाईट्रोजन ज्यादा है, इतनी में पोटाश ज्यादा है और उनमें कौन कौन सा खाद डालना चाहिए। आज हालत यह है किसानों को जो भी खाद मिल जाए वही डाल देते हैं जिसका सही फायदा नहीं होता। जो आर्टीफीशिल खाद है उससे कोई जमीन की क्वालिटी नहीं बढती, बलिक उससे सिर्फ स्टिमूलेशन होती है और पैदावार मैं मानता हूं कि बढ जाती है लेकिन कुछ देर के बाद जमीन खराब हो जाती है। जो यूरोप के मुल्क हैं, जहां पर आर्टीफिशल खाद का इस्तेमाल ज्यादा होता था, मिसाल के तौर पर आप अमरीका की मिसाल ले लें वहां पर लाखों एकड भूमि खराब पडी है। इसी तरह जापान में भी जब उन्होंने रासायनिक खाद ज्यादा डाला था तो वहां की जमीन भी खराब होने लगी और फिर उनहोंन अपने ढंग बदले, उन्होंने नाइट कम्पोस्ट खाद डालकर, नहर का कीचड ओर मिटटी का इस्तेमाल कर के जो जमीन खराब होने चली थी उसको खराब होने से बचाया। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जब तक किसानों को हम पूरी जानकारी नहीं दे सकेंगे, मेरा यह अन्देशा है कि हम जो रासायनिक खादों से उत्पादन ज्यादा कर

रहे हैं उससे बहुत सी जमीन थोडे अर्से के बाद नाकस हो सकती है। इसलिए उससे बचने के लिए हमें इंतजाम करने की जरूरत हे। हमारे प्रांत में बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां पर कुएं हैं मगर उनका पानी खारी है, किसी में कोई मिनरल ज्यादा है, किसी में कोई और मिनरल ज्यादा है। उसकी जांच पडताल करने के लिए मैं मानता हूं कि हमारे सूबे में तीन चार प्रयोगशालाएं हैं जहां पर क मिटटी भी टैस्अ की जाती है लेकिन मैं समझता हूं कि वह काफी नहीं हें हमारी सरकार को चाहिए कि लोगों को पूरी जानकारी देने के लिए एक्सपर्अ स्टाफ लगाए जो गांव गांव में जाकर सारी भूमि की पड़ताल करें कि उसमें क्या क्या कमी है और कौन सी खाद की जरूरत है, कुओं का पानी खेती के लिए मुआफिक है या नहीं है। जहां पर जो ऊपर की उपजाऊ मिटटी पानी से बह गई है वहा ंपर क्या इंतजाम करना है यह सब एग्जामिन करने की जरूरत है। कहां पर वाटर लौगिंग का खतरा है और उसको चैक करने का कया प्रबंध होना चाहिए यह सारी चीजें जो हैं यह पटवारी और गिरदावर नहीं कर सकते। इसलिए मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि इसके लिए स्पैशल स्टाफ लगाया जाना चाहिए। आज हमने किसानों की बेहतरी के लिए और जो देहाती आबादी हैं उनकी बेहतरी के लिए डिवैलपमैंट बलक्स बनाए हुए हैं, सन 1952 में वे चालू हुए थे लेकिन अब 1972 चल रहा है मगर इतने अर्से में जो लोगों की आशाएं थीं वह ब्लाक्स के अफसरान पूरी नहीं कर सके। डिप्टल स्पीकर साहिबा, आप खुद अंदाजा लगा सकती हैं कि गांव में बैठा एक विलेज लैवल वर्कर

क्या रहनुमाई कर सकता है, जिसको खुद कोई ज्ञान नहीं वह किसानों को क्या बता सकता है, कि फलां खाद कितना डालना चाहिए और किस किस बीमारी का जो फसलों को लगती है क्या क्या इलाज करना चाहिए। मुझे अफसोस से कहना पडता है कि ब्लाक्स में बहुत से ऐसे अफसरान हैं जो अपनी जिम्मेवारी को महसूस नहीं करते। मैं यह नहीं कहता कि सभी ऐसे हैं, लेकिन बेशतर ऐसै हैं जो यह महसूस नहीं करते कि किसानों को सलाह मशवरा देना उनका फर्ज है। बहुत से बी0डी0ओज0 ऐसे हैं जो शराब पीने के सिवाए और कोई काम नहीं करते और जो विलेज लैवल वर्करज हैं वे सारा सारा दिन बैठे ताश खेलते रहते हैं। जब ऐसी हालत हो तो फिर हम कैसे समझें कि उनके द्वारा हम उन्नति के कामों में सफल होंगे। अगर हम ऐसा समझते हैं तो वह हमारी गलतफहमी है। इसलिए मैं आप को एक सुझाव देता हूं कि जिससे बेरोजगारी भी काफी दूर हो जाएगी और हमारे प्रान्त में लोगों को भी पूरा फायदा हो सकता है। मैं सुझाव देता हूं कि जो बी0डी0ओज0 हैं वे अनट्रैंड नहीं लगाने चाहिए। आज कृषि के सिलसिले में टैक्नालोजी बढती जा रही है, इसलिए जो जो इस सब्जैक्ट के इंजिनियर बन कर आते हैं, उनको बी0डी0ओज0 लगाया जाना चाहिए क्योंकि वे कैमीकल्ज से वाकिफ होने के नाते किसानों को ठीक सलाह दे सकेंगे। आज हमारे देश में 65–70 हजार के लगभग इंजीनियर बेकार फिर रहे हैं आप उनको कामों पर लगा कर किसानों का और अपने सूबे का भला करें। जो इस वक्त आप ने बी0डी0ओज0 रखे हुए हैं, जो कृषि के काम में

सहायता नहीं कर सकते मैं उनसे मुतमइन नहीं। कितने ही आज एग्रीकल्चर के एम0एस0सीज0 पास हैं उनको आप लगाएं और जो आठवीं आठवीं पास तालीम वाले आप ने लगाए हुए हैं, उनको क्योंकि खुद को इन कैमीकल्ज की कोई जानकारी नहीं है इसलिए वह कोई आप की सहायता नहीं कर सकते। इसलिए डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं आप के द्वारा सुझाव देना चाहता हूं कि एक तो जो यह पटवारी और गिरदावरौं का रैवैन्यू स्टाफ है यहा ऐंजसी आप खत्म कर दें और इसकी बजाए आप बेशक दस दस गांव का ब्लाक बना कर कोई इंजीनियर या क्वालीफाईड आदमी एप्वायंट कर लें लेकिन पटवारियों की लानत से आप लोगों को निजात दिलाएं। इसमें यह कहा जा सकता है कि माल गुजारी वगैरह की प्रोबलम हो सकती है लेकिन उस के लिए मैं सुझाव देता हूं कि आप पिछले तीन साल की मालगुजारी को देख कर उसके हिसाब से तीन साल की वसूली कर सकते हैं और उस पर तीन चार सालों के बाद फिर नजरसानी हो सकती है। आज हमें इस बात की शर्म आती है जब हम अखबारों में, सब जगह यह चर्चा सुनते हैं कि यह देश ऐसा है जिस में 65 इंजीनियर बेकार बैठे हुए हैं, यह ऐसा देश है जिस में साइंसदान आत्म हत्या कर के मरते हैं। अभी चन्द दिनों की बात है कि एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीच्यूट, देहली में एक सांयटिस्ट ने आत्महत्या की, उससे पहले एक और ने की और कितने ही ऐसे सायंटिस्ट हैं जिनको आप 50 रूपए रो भी नहीं दे सकते।

3.00 सायं।

आप दूसरे देशों में जाकर देखिए, जगन महता हैं उन्होंने इनामात हासिल किए हैं। उन्होंने ईजादें करके नई चीजें पैदा करके नोबल प्राइज हासिल किए लेकिन हम यहां हैं कि अपने इंजीनियर्ज को साइंटिस्ट को काम नहीं दे सकते। आज कृषि के क्षेत्र में साइंस और टैक्नोलोजी की जरूरत है। चाहे आज खाद इस्तेमाल करें, बीज और दूसरी दवाईयां वगैरह इस्तेमाल करें सब के लिये टैक्नीकल जानकारी की जरूरत है। इसलिये में अर्ज करता हूं कि टैक्नीकल आदमियों को इन जगहों पर लगाएं और जो गड़बड़ पटवारी और दूसरे लोग करते हैं उनसे गरीब अनपढ किसानों को बचायें यह मेरा आपके सामने सुझाव है। इसके इलावा दो तीन मांगें इसमें बेरोजगारी दूर करने के बारे में भी हैं। इनमें एक क्रैस प्रोग्राम लोगों को रोजगार देने के बारे में है दूसरी स्कीम पढे लिखे लडकों को रोजगार पैदा करने के लिये फाईनैंनशियल ऐड देने की है और तीसरी ऐसी ही कुछ स्कीमें हैं। इन के बारे में भी मैं कुछ अर्ज करना चाहता हूं। आज चौथी योजना समाप्त होने चली है और पांचवीं योजना की तैयारियां हैं। आप देखेंगे कि जो भी योजना बनी उसमें इस बारे मैं जो भी टारगैअस रखे गये वह पूरे नहीं हुए। यह टारगेटस न पहली योजना में पूरे हुये न दूसरी और तीसर योजना में ही पूरे हुए और अब जो चौथी योजना है उसमें तो इनके पूरे होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। बेरोजगारी की इतनी बुरी हालत हो रही है

कि बयान से बाहर है। यही नहीं, यह बेरोजगारी देहात में है, यह शहरों में भी है। चूंकि देहात में 80 फीसदी आबादी रहती है और हरियाणा में 82 फीसदी रहती है। इसलिये देहात में यह समस्या ज्यादा है वरना शहरों में भी यह मसला बहुत बडा है। इस बेरोजगारी की समस्या का पता कि यह कितनी है अगर आज एम्पलायमैंट एक्सचेंज के लाईव रजिस्टर्ज के आंकडे देखें तो उन से लग जाता है। यह आंकडें भी कोई सही नहीं हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि देाहता के लोग अनपढ हैं और कम पढे लिखे हैं। इसलिये वे नाम दज्र नहीं कराते। फिर भी आप अगर पिछले तीन चार साल के आंकडें देखें तो आप देखेंगे कि यह बेरोजगारी बढती जा रही है। इस वक्त हरियाणा में एक लाख से ज्यादा लोग बेरोजगारों की लिस्ट में दर्ज हैं और इससे पहले कम थे। अगर आप सारे देश के बेरोजगारी के आंकडें देखें तो आप को पता लगेगा कि बेरोजगारी कितनी भयानक शक्ल अख्तियार करती जा रही है। 1966 में लाई रजिस्टज पर जो बेरोजगारों के नाम दर्ज थे उनकी तादाद 20 लाख थी और 1971 के आंकड़ों के मुताबिक यह तादाद 45 लाख है। 1966 में बेकार इंजीनियरों की तादाद 23 हजार थी लेकिन आज 64 हजार है इन 45 लाख में से जो बेकार थे और मुलाजमत की फिक्र में थे उनमें दसवीं या इससे ज्यादा पास लडकों की तादाद 1966 में 6ह1 हजार थी लेकिन 1970 में यह तादाद एक लाख से ज्यादा हो गईं आप देखें किस रफतार से बेकारी बढती जा रही है। सारे देश में जिन लोगों ने एम्पलायमैंट एक्सचेंजित में अपने नाम दर्ज कराये थे उनकी तादाद 1966 में 3

करोड 61 लाख थी और इस वक्त यानी 1970 में यह तादाद 4 करोड 49 लाख हो गई है। इनमें से कोई सवा दो करोड पढे लिखे हैं। हरियाणा के बारे में मैंने पहले अर्ज किया है कि एक लाख से ज्यादा बेकार लोगों के नाम लाइव रजिस्टर पर दर्ज हैं। हरियाणा की सरकार ने दावा किया है कि उसने 8 फीसदी लोगों को रोजगार दिया है जबकि सरे देश में दो या ढाई फीसदी के करीब लोगों को रोजगार मिल सका है और यह बात मैं मानता हूं कि लेकिन इस बात से भी आंखें मूंदी नहीं जा सकतीं कि यह जो 8 फीसदी बेकारों को रोजगार मिला वह किस वजह से मिला। वह इस वजह से मिला क्योंकि सरकार ने कुछ क्रैश प्रोग्राम चलाये जो कि सडकों, बिजली और नहरों वगैरह के थे। लेकिन आज जब सरकार के सामने माली मुश्किलात आई हैं तो वह पोजीशन शायद आज न चले। कोई अढाइतीन लाख मजदूर नहरों सडकों और दूसरों पब्लिक वर्क्स पर काम करता था लेकिन आज वह घर पर बेकार बैठा है। मैंने पहले भी यहां हाउस में अर्ज किया था कि हम क्रैश प्रोग्राम का पूरा फायदा नहीं उठा सकते। हम तो फेजड प्रोग्राम से फायदा उठा सकते हैं। इसमें हमें बहुत मजदूरों की जरूरत पडती है और अगर हमें अपने प्रांत में इतने न मिल सकें तो दूसरी स्टेटस से लेते हैं, यू0पी0, राजस्थान से लेते हैं। जब काम खत्म हो जाता है तो मजदूर बेकार हो जाते हैं। अगर छोटे छोटे काम चलायें तो हमारे मजदूरों को काफी समय के लिये काम मिल सकता है और इससे प्रांत की बेकारी दूर करने में काफी सहायता मिल सकती है। आज जब क्रैश प्रोग्राम का काम खत्म हो

जाएगा तो फिर रूटीन नेचर का काम रह जायेगा जिसके लिये थोड़े से लोगों को काम मिलता है बाकी को काम नहीं मिलेगा और वह बेकार होकर घर पर बैठ जायेंगे और आज बैठ गये हैं। आज आप देखे लें हरियाणा में बेकारी की ज्यादा पोजीशन खराब है। जो लोग दो महीने पहले नहरों, सडकों वगैरह के क्रैश प्रोग्राम पर काम करते थे वह अब बेकार हो गये हैं। आज सारे देश में बेकारी बहुत बुरा रूप धारण किये हुए हैं। इसे दूर करने के लिये जो प्रोग्राम गवर्नमैंट आफ इंडिया ने दिया है उससे इसका हल नहीं होगा। यह ठीक है कि मर्कजी सरकार ने कुछ स्कीमें बेकारी को दूर करने के लिये चालू की हैं एक तो कृषि प्रोग्राम के बारे में है, दूसरी उन्होंने रूरल वर्कस की स्कीमें, रूरल अनएम्पलायमैंट दूर करने के लिये चालू की हैं और तीसरे ड्राट एरियाज के बारेम में जहां कहत पडते हैं यानि जहां क्रानिक ड्राट हैं वहां के लिये स्कीमें चालू की हैं। इसके अलावा पढे लिखे लोगौं की बेकारी दूर करने के लिये और छोटे किसानों, स्माल फारमर्ज के लिये डिवैल्पमैंट एजैंसीज कायम की हैं। इन सारी स्कीमों के लिये मर्कजी सरकार ने स्टेटस को पैसा दिया है। 1970–71 से यह स्कीमें चालू हैं, लेकिन 1970–71 में कोई खर्च नहीं हो सका जो कि बजट में रखा गया था। हो सकता है कि कुछ गाइड लाइनज बननी होंगी और कुछ पालिसी तै होनी होगी, इसलिये काम नहीं हो सकका। फिर 1971–72 का साल आया और इस साल उन लोगों के लिए जो बेरोजगार हैं जिनको भूख सताती है उनके लिये 47 करोड रूपया दिया कि उनको काम दिया जाये और

उसमें हरियाणा को 86 लाख रूपया मिलां सारे देश में जितने स्टेट सरकारें हैं वह इस पैसे में से बेकाचरी को दूर करने के लिये जिसकी वजह से लोग मारे मारे फिर रहे हैं और उन्हें काम नहीं मिलता जिससे वे रोटी खा सकें, 32 करोड रूपया खर्च कर सकी और बाकी बच गया। इसका मतलब है कि वे बेकारी दूर करने के लिये स्कीमें नहीं बना सकीं। इसके अलावा मैं अर्ज करता हूं कि यह जो जिलावार एक एक हजार आदमी को काम दिया जाये वाली बात है इससे तो मजाब बनता है। मर्कजी सरकार कहती है कि तीन रूपये रोज पर आप मजदूर रखो। यह जो एग्रीकल्चरल लेबर है इसकी वेजिज मुकर्रर हैं और फैक्टरीज में जो मजदूर काम करते हैं उनकी वेजिज मुकर्रर है लेकिन यहां तीन रूपये रोज की बात होती है। ऐसी बातें करके और लोगों को तीन रूपये रोज देने की बात करके आंसू पोंछ रहे हैं कि उनकी बेकारी दूर करेंगे। मैं अर्ज करता हूं कि बहु सारे वजीर ऐसे होंगे जो दिन में तीन चार रूपये की सिग्रेट ही पी जाते हैं। लेकिन मजदूरों को सिर्फ तीन रूपये मजदूरी दी जाती है। आप देखें, तीन रूपये में मजदूर का काम कैसे चल सकता है, इस महंगाई में कुछ नहीं बनता। सब्जी को आप छोडिए। 100 रूपये महीने की आमदनी से घर में आटे का खर्च भी नहीं चलता। आजकल आप देख रहे हैं कि चीनी की क्या कीमत है। मजदूर को दाल भी खरीदनी पडती है, कपडा भी खरीदना पडत है और दूसरी चीजें भी लेनी पडती हैं। आज कपडे की कीमत बहुत बढ रही हैं। सरकार ने कई बार एलान किया कि जो लोग मजदूर तबके से ताल्लुक रखते हैं,

जिनकी आमदनी कम है उनको सस्ते भाव पर कपडा देंगे। ऐसे एलान किये थे कि मिलों में 25 फीसदी कपडा, जिसको कोर्स क्लाथ कहते हैं, मजदूरौं के लिये बनाएंगे ताकि गरीब तबका कम से कम तन तो ढक सके।

उपाध्यक्षाः आप कितना टाईम और लेंगे ?

चौधरी रिजक रामः मैं जल्दी ही खत्म कर दूंगा। मैं अर्ज कर रहा था कि सस्ता कोर्स क्लाथ बनाने और सस्ते दामों पर चीनी देने के लिये सरकार ने कितने बडे बडे एलान किये। पार्लियामैंट में बडे बडे एलान किये लेकिन जब इलैक्शन आता है तो सारी हिदायतें मंसूख हो जाती हैं। आप सारे देश में देख लें, किसी भी दुकान पर चले जाएं, कहीं आपको सस्ता कपडा नहीं मिलेगा। आज कपडा खरीदना गरीब आदमी के बस की बात नहीं। आप देखें पिछले तीन चार महीनों 7 परसैंट से अधिक कीमतें बढी हैं। अगर आप पांच चार साल की कीमतों का हिसाब लगाएं तो 43 फीसदी से ऊपर बढी हैं। मजदूर जिस चीजे को पांच साल पहले 10 रूपए में खरीदता था आज 100 रूपए में भी नहीं खरीद सकता। जो लोग गरीब हैं उनकी देश में कितनी तादाद हैं ? प्लानिंग कमीशन की तरफ से पांचवती पंचवर्षीय योजना का जो अप्रोच पेपर पेश हुआ था उस में लिखा था कि देश में 22 करोड ऐसे आमदी हैं जिनकी माहवार आमदन 20 रूपए से कम है। इस महंगाई के जमाने में 20 रूपए का मैयार रखा गया है। 1960–61 में अगर किसी आदमी की आमदन 20 रूपए थी तो वह उस

आमदनी में थोडा गरीबों की तादाद 22 करोड है जिसको केन्द्रीय सरकार ने माना है। आप जरा गौर करें, गरीबों की तादाद कितनी तेजी से बढती जा रही है। देश में तकरीबन 13 करोड आर्टीजन थे जिनमें लोहार, खाती, कुम्हार और दूसरे लोग थे। ये लोग गांवों में रहते थे, सरकार इन लोगों को काम धंध मुहैया करने के लिये सुविधाएं नहीं दे सकी। परिणाम यह हुआ कि जितने लोहार थे, वे शहराों ने झडप लिए मकैनिक्स बन गए। जो खाती थे उनका काम खत्म हो गया, चाहे वे ट्रैक्टर का काम करते हैं चाहे टयूबवैल्ज का काम करते हैं, चाहे इलैक्ट्रिसिटी का काम करते है। लेकिन वे सारे के सारे शहरों में चले गए हैं। जितनी बेकारी है उसको खत्म करने के लिए केन्द्रीय सरकार 47 से 50 करोड तक रूपया खर्च करती हे और 86 लाख हरियाणा प्रान्त जहां का अधिकतर इलाका रेगिस्तान है, को देती है। हिसार और भिवानी का सारे का सारा इलाका रेगिस्तान है। जिला अम्बाला में से कितने रिवौलैटस, नदियां और नाले निकलते हैं जो बहुत नुकसान करते हैं। लेकिन जो इलाका सूखा है वहां नहरी पानी नहीं मिलता। जमुना नगर को छोडकर कभी भी टयूबवैल्ज कामयाब नहीं होते। महेन्द्रगढ, गुडगांव, झज्जर का इलाका बिल्कुल रेगिस्तान है। बारिश भी कोई नहीं होती। वहां पर दस दस बारह बारह साल से लगातार कहत है। ऐसे इलाकों के लोगों की भूख मिटाने के लिए उन की हालत सुधारने के लिए, दिल्ली की सरकार ने देश के मजदूरों को सिर्फ 47 करोड रूपया दिया है। इससे बडा मजाक मजदूरों के साथ और कोई हो ही नहीं सकता। डिप्टी स्पीकर

साहिबा, इसके बाद अफसोस की बात यह है कि जो रूपया दिल्ली की सरकार ने मंजूर किया है, चाहे ड्राई फार्मिंग के लिए मंजूर किया, चाहे छोटे किसानों की मदद के लिए मंजूर किया, चाहे एम्पलायमैंट देने के लिए मंजूर किया, वह जिस प्रान्तीय सरकार को दिया उसने उसको खर्च तक नहीं किया, उसमें से काफी रूपया बचा लिया गया। स्कीमें मंजूर होती है और फेल हो जाती हैं, कोई प्रोग्राम पूरा नहीं होता।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, आपकी मारफत एक बात बेरोजगारी के बारे में कहना चाहता हूं। हरियाणा की स्थिति बडी अजीब है। यहां की जितनी भी आबादी है वह पहले से ही तालीमयाफता नहीं है। दो चार पुश्तें गुजरने के बाद मुमकिन हो सकता है कि हमारे बच्चे दूसरे प्रान्तों के बच्चों का मुकाबला कर सकें लेकिन आज नहीं क्योंकि तालीम का ढांचा ही इस किस्म का है। जो भाई पंजाब की तकसीम के वक्त हरियाणा में आए हैं उनको तालीम पहले से ही ज्यादा है लेकिन हरियाणा के निवासियें की तालीम पहले से ही नहीं थी। जहां तक दूसरे इम्तिहानों का ताल्लुक है उनमें हमारे लडके इस वजह से पीछे रह जाते हैं कि गरीब आदमी अपने बच्चों को कालेज में भेज कर खर्चा पूरा नहीं कर सकता। गरीब आदमी कुछ नहीं कर सकता। इसकी वजह यही है कि हमारे बच्चों को आगे बढने का मौका नहीं मिलता। जहां तक सर्विसिज का ताल्लुक है, आप मानेंगें कि सर्विसिज पर शहरी लोगों का कंट्रोल है क्येांकि उनके लडके पब्लिक स्कूलों में पढते

हैं। टयूटर घर पर आकर पढाते हैं, वे अपने बच्चों को दूसरे स्कूलों में भेज कर पढाते हैं .....

उपाध्यक्षाः चौधरी साहब, आप किस डिमाडं पर बोल रहे हैं ?

चौधरी रिजक रामः बेरोजगारी पर बोली रहा हूं।

उपाध्यक्षाः आप तो एजुकेशन पर बोल रहे हैं ?

चौधरी रिजक रामः एजुकेशन भी इसमें आ जाती है। हां, तो मैं कह रहा था कि देहाती लोग, देहाती बच्चे शहरी बच्चों का मुकाबला नहीं कर सकते। इस वजह से हालत यह हो गई कि हमारे लडकों को रोजगार मिलने में बहुत कठिनाई होती है। इसके साथ ही साथ में एक और बात कहना चाहता हूं। हमारा प्रान्त हिन्दी भाषी प्रांत हैं। हिन्दी भाषा प्रांत होने की वजह से इस प्रांत में जो भी आसामी, जो भी नौकरी की जगह खाली होती हैं, उसके लिए दूसरे प्रान्तों के लडके मुकाबले में आ सकते हैं, दरखास्तें दे सकते हैं। और नौकरी पा सकते हैं लेकिन दूसरे प्रान्तों में हरियाणा प्रान्त के लडकों को नौकरी में नहीं लिया जाता। हमारे पडौसी पांजब प्रान्त ने यह पाबंदी लगा दी कि वहीं लडका पंजाब में नौकरी पाने के लिए दरखात दे सकता है जिसने दसवीं क्लास के लैवल तक पंजाबी पढी हो। पंजाब के लडकें जो हिन्दी पढे लिखे हैं वे तो हरियाणा में नौकरी पा सकते हैं लेकिन हरियाणा के लडकें वहां नहीं पा सकते। दूसरे प्रान्तों में भी ऐसा

ही है। सिर्फ पांजब में ही ऐसी पाबंदी नहीं है। बंगाल, मद्रास, आसाम, मध्य प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश वगैरह कई ऐसे सूबे हैं जिन्होंने डामीसाईल की पाबंदी लगा रखी है ताकि अपने अपने आदमियों को ज्यादा से ज्यादा नौकरियां मिलें। डिप्टी स्पीकर साहिबा, हिमाचल के बारे में आपने अखबारों में पढा होगा। 1969 में हिमाचल गवर्नमैंट ने एक हुक्म जारी किया था कि हिमाचल में उस आदमी को नौकरी मिलेगी जो हिमाचली हो और हिमाचली वह होगा जिसके बाप दादा हिमाचल के बाशिंदे हों। दूसरी स्टेट के किसी आदमी ने अगर हिमाचल की नौकरी कर ली है तो वह हिमाचली नहीं गिना जाएगा। 1969 में इस बिना पर चर्चा शुरू हुई थी और मैंने कहा था कि हरियाणा में भी हरियाणा के बच्चों को इस किस्म की प्रैफरैंस दी जाए। लेनि सब ने कहा कि ये पंजाबियों के खिलाफ हैं। आप देखें, कोई अंधे अंधा आदमी भी यह कह सकता है कि सन 1947 में जो लोग उजड कर हरियाणा में आये थे वे हरियाणा के निवासी हैं .....

उपाध्यक्षाः आप जरा अपनी स्पीच शोर्ट करें।

चौधरी रिजक रामः थोडी देर में खत्म करता हूं। मैं इस पर बोलना चाहता हूं, आप ऐतराज कर देती हैं। कल सैशन खत्म हो जाएगा, मुझे थोडा सा बोलनें दें। हां, मैं कहना चाहता हूं कि कोई भी ऐसी बात सोच नहीं सकता था इन्होंने कहीं। अखबार वालों ने भी शोर किया। डिप्टी स्पीकर साहिबा, अफसोस की बात यह है कि कोई भी ऐसी खबर तलाश नहीं कर सकता

जिसमें अखबार वालों ने हरियाणा के हक में कहा हो। किसी ने हरियाणा के हक में कुछ नहीं कहा क्योंकि सारे अखबार कैपिटल लिस्टस के चंगुल में हैं। तमाम अखबारों पर कैपिटलिस्टस छाए हुए हैं। दिल्ली से रोजाना अखबार निकलते हैं लेकिन सब जगह सरमायेदार छाए हुए हैं स्टेटस मैन पर टाटा, हिन्दुस्तान टाईमज पर बिरला, टाईमज आफ इंडिया पर डालमियां और ट्रिब्यून के ऊपर भी सरमायेदार छाए हुए हैं। कोई ऐसी अखबार नहीं है जिसमें कोई इंसाफ की बात आती हो। ..... (विघ्न).. डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं यह बताऊंगा कि आज हरियाणा में बेरोजगारी की क्या अवस्था हैं आपके एम0ए0 पास, एम0एस0सी0 पास, बी0ए0 पास आदि लडके ठोकरें खाते फिरते हैं क्योंकि प्रांत में नौकरी ये दे सकते नहीं और दूसरे इलाकों में, सूबों में कोई खडा नहीं होने देता। क्या आप समझते हैं कि वे इन सब चीजों को शांति के साथ बरदाश्त करते रहेंगे ? यह सरकार का गलत ख्याल है। आज का नौजवान वह नौजवान नहीं है जो 20—25 साल पहले का था। आज वह टैलीविजन पर बैठकर, रेडियो से सुनकर और अखबारें पढ कर सारे देशों की व्यव्स्था की जानकारी रखता है। आज वैसे नौजवान नहीं हैं जो शाम को मां या दादी के पास बैठकर चोरों की कहानियां सुनते हों। .(विघ्न) बल्कि वह देखता है कि ईस्ट बंगाल के नौजवानों ने कैसे अय्युब शाही को खत्म किया ? कोरिया में कैसे उन्होंने हकूमत बदली और दूसरे देशों में कैसे क्रांति लाने में अपना रोल अदा कर रहे हैं ? यह सरकार समझती है कि जो पढे लिखे लोग हैं वे इसी तरह से शांति से बैठे रहेंगे।

कितनों को इन्होंने नौकरी से निकाल दिया, किसी को कोई रोजगार का साधन नहीं, फिर यह सोचें कि शांति के साथ देश इसी तरह चलता रहेगा, यह मुगालता इनको रहना चाहिए। आज अढाई करोड नौजवान ऐम्पलायमैंट ऐक्सचेंजिज के सहारे बैठे हुए हैं, लेकिन यह उनका इंतजाम नहीं कर सकते, प्रबंध नहीं कर सकते। कितने ही दूसरे देशों में इस तरह की बातें हुई हैं। जब ताकत का नशा रहता है, ताकत हाथ में रहती है उस वक्त किसी ने कहा है कि सरकार के आंख नहीं होती, कान होते हैं। सरकार अपनी आंख से देख नहीं सकती। जब कोई खराब बात उसके सामने आती है तब वह उसके काबू की रहती नहीं। इसलिए मैं निहायत अदब से अर्ज करूंगा कि आज हमारे प्रांत में जो बेरोजगारी की व्यवस्था है इसका समाधान करने के लिए हमें सब साधन जुटाने चाहिएिं। हमारे हरियाणा में रहने वाले जो लोग हैं, चाहे वे शरणार्थी हैं, या दूसरे हैं, उन सबको प्रैफरैंस देकर रोजगार दिया जाना चाहिए। हमारी सरकार कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता। मैं पूछता हूं कि क्यों नहीं हो सकता। क्या राजस्थान में कांग्रेस की चीफ मिनिस्टर रहते हुए सुखाड़िया साहब ने हिदायत जारी नहीं की थी कि राजस्ताान में जितनी थी इंडस्ट्रीज हैं, कारखाने हैं, उनमें राजस्थान के आदमियों को पहले मौका दें? क्या बंगाल में ज्योतिर्मय बसु ने मार्कसिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी का मैम्बर होते हुए डिप्टी चीफ मिनिस्टर और होम मिनिस्टर की हैसियत से अपने लोगों को प्रैफरैंस नहीं दिलाई थी ? क्या बंगाल में बिरला की जितनी इंडस्ट्रीज हैं, कारखाने हैं, जितने भी दफ्तर

हैं उन्हें उन्होंनें हिदायत जारी नहीं की कि सब में बंगाल के आदमियों का प्रैफरैंस दी जाए ? क्या हम नहीं कह सकते ? आज जितने भी कारखाने लोगों ने यहां लगाए हुए हैं, उनमें वे लोकल आदमियों को, जिनकी जमीन पर उन्होंने कारखाने लगाए हैं, नौकरी पर नहीं लगाते। वे अपने आदमियों को नौकरी देते हैं। चाहे उन्हें अपने रिश्तेदार को कहीं से भी बुलाना पडे मगर क्लर्क और अकाउटैंट वे अपने आदमी को ही रखेंगे क्योंकि अगर बगैर भरोसे के आदमी को अकांउटैंट और क्लर्क लगा लें तो सारा भेद खुल जाए। टैक्स की जो ये चोरी करते हैं या ब्लैक मनी जो होती है कहीं उसका भेद न लग जाए इसलिए सिवाय अपने आदमियों के ये किसी दूसरे की अच्छी जगह पर नहीं लगाते। जिन लौगों की जमीन सरकार इनको लेकर देती है उनके बच्चे भी मारे मारे फिरते हैं। कोई बडी बडी जगहों पर ही ये लौग यहां के लोगों को नौकरी नहीं दे रहे बल्कि चौकीदार तक गढवाल और टीहरी गढवाल से लोग लाकर उन्हें लगाते हैं। (विघ्न) तो आज यह हालत हैं। चौकीदार हमारे फौजी नहीं लग सकते, क्लर्क हमारे लडकें नहीं लग सकते तो फिर बताओ वे कहां जाएंगे ? इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि सरकार इस मामले में हिदायत जारी करे कि जिस कारखाने को बिजली का कुनैक्शन देते हैं, जिस कारखानेदार को आप जमीन देते हैं और कर्जा और सबसिडी आदि देते हैं उनसे ऐग्रीमैंट लें कि जिन लोगों की हम जमीन लेकर दे रहे हैं उनको नौकरी में प्रैफरैंस दी जानी चाहिए। जिस तरह के आदमी उन्हें चाहिए यदि उस तरह के यहां न मिलें तब

तो बेशक बाहर से बुलाएं। जब तक ऐसा नहीं करेंगे तब तक प्रौब्लम हल नहीं होगी।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, बैठने से पहले मैं एक बात और कह देना चाहता हूं और वह स्पीकर साहब के अलाउंस के बारे में है। डिप्टी स्पीकर साहिबा, स्पीकर साहब तो इस समय हैं नहीं लेकिन आप सुन लें।

उपाध्यक्षाः चौधरी साहब, आपको बोलते हुए बहुत टाईम हो गया है। हाउस में और भी बोलने वाले हैं। पांच बजे गिलोटीन लागू हो जाएगा। हमारे पास टाईम कितना रह गया है यह आप देख ही रहे हैं।

चौधरी रिजक रामः केवल दो मिनट और लूंगा।

पंडित चिंरजी लाल शर्माः डिप्टी स्पीकर साहिबा, चौधरी रिजक राम ने आपको मुखातिब करते हुए कहा कि स्पीकर साहब तो हैं नहीं। फिर कुछ दबे हुए स्वर में फिकरा अधूरा रख गए। डिप्टी स्पीकर साहिबा, स्पीकर साहब की गैर हाजरी में आपको वही स्टेटस हाचेगा जिसके थ्रू गवर्नमैंट को ये अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं। यह तो रूल्ज की बात है।

चौधरी रिजक रामः उसमें तो कोई शक नहीं है। (विघ्न)

चौधरी राम प्रसादः डिप्टी स्पीकर साहिबा, चौधरी रिजक राम ने भाषण तो लम्बा चौडा दे दिया कि यह नहीं हुआ, वह नहीं हुआ और बेरोजगारी का मसला चलते हुए काफी देर हो गई है लेकिन यह नहीं बताया कि इस मसले का हल कैसे हो सकता है। कृपया यदि ये यह भी बता दें तो अच्छी बात होगी। (विघ्न)

चौधरी रिजक रामः वह आप बता देना। डिप्टी स्पीकर साहिबा, स्पीकर साहब दूसरे देशों में तशरीफ ले जा रहे हैं। उनके टूर के खर्चे का आइटम भी सदन में इन मांगों में शामिल है। इस पर तो कोई आपत्ति नहीं हो सकती। लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं कि ये दूसरे देशों में जाएं और यह देखें कि वहां किस तरह से डैमोक्रेसी चल रही है या रवायात हैं। वैसे स्पीकर साहब, बेशक पहली मर्तबा स्पीकर बने हों इसमें कोई संदेह नहीं कि उनको अपने काम से पूरी वाकफियत हैं और इस ढंग से वे सदन में काम कर रहे हैं जिसमें सभी सैक्शंज के लोगों को चाहे वे अपोजीशन के हों या सरकार पक्ष के हों उन पर पूरी श्रद्धा और विश्वास है लेकिन एक बात मैं कहन चाहता हूं जो न मालूम किस ढंग से गलत बात हुई। वह कोई मेरी जाति बात नहीं है जो मेरे मुताल्लिक हो बल्कि प्रजांतत्र के सिद्धान्तों से ताल्लुक रखती है। आप देखेंगे कि जिस वक्त पिछला सैशन हुआ था उस वक्त लीडर आफ दी अपोजीशन नियुक्त नहीं किया गया, उसका बाद में फैसला हुआ और उस फैसले के बारे में दो बातें मैं अर्ज करना

चाहता हूं। एक तो यह कि जम्हूरियत में कुछ कायदे कानून हैं और कायदे कानून के अनुसार कोई भी ऐसी पोलिटीकल पार्टी जो हाउस के अंदर भी और बाहर भी एक प्रोग्राम लेकर काम करती है उसका लीडर, लीडर आफ दी अपोजीशन रिकोग्नाइज किया जाता है। ये हजारे रूल्ज हैं किसी ऐसी पोलिटीकल पार्टी के लीडर को, जिसका बाहर और अंदर एक प्रोग्राम न हो और न ही उसका कोई एक पार्टी मैनिफैस्टो हो, लीडर आफ दी अपोजीशन नियुक्त नहीं किया जा सकता। (विघ्न) लेकिन स्पीकर साहब ने जिन माननीय सदस्यों की सहायता से लीडर आफ दी अपोजीशन नियुक्त किया वे एक पार्टी प्रोग्राम पर चुन कर नहीं आए हैं। तो क्या मैं पूछ सकता हूं कि सरकार इस बात की पडताल करेगी कि आया यह पोलिटीकल पार्टी ऐसी है जिसने कोई प्रोग्राम बनाया है जिसकी बिना पर आपने लीडर आफ दी अपोजीशन को अपनाया ? अगर कोई प्रोग्राम नहीं बनाया है तो क्या यह कायदे की खिलाफ वर्जी नहीं है ?

चौधरी मनफूल सिंहः डिप्टी स्पीकर साहिबा, ये कौन सी डिमांड पर बोल रहे हैं ?

उपाध्यक्षाः चौधरी साहब, आपको डिमांड पर बोलना चाहिए।

चौधरी रिजक रामः डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं डिमांड नं0 8 पर बोल रहा हूं।

उपाध्यक्षाः अब आपका टाईम हो गया है।

चौधरी रिजक रामः मेरे ख्याल में आप इस बात पर नाराज हो गई हैं।

उपाध्यक्षाः चेयर के लिये यह कोई सवाल नहीं है मगर मुझे रैलेवैंसी और इर्र रैलेवैंसी जरूर देखनी है।

चौधरी रिजक रामः एक सैंकिड में मैं बैठ रहा हूं। तो डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं अर्ज करना चाहता हूं और जहां तक मेरी जानकारी है, कि जिस वक्त लीडर आफ दी अपोजीशन नियुक्त किये गये तो उस वक्त उनका कोई दूसरा आफिस बेयरर यहां मौजूद नहीं था और न ही इनकी कोई मीटिंग हुई थी।

कृषि मंत्री (चौधरी भजन लाल): ये तो वहीं बतायेंगे कि मीटिंग हुई थी या नहीं हुई थी।

चौधरी रिजक रामः यह तो आप बतायें कि मीटिंग हुई थी या नहीं हुई। मैं तो यह कहता हूं कि यह कायदे के खिलाफ बात हुई है। इस बात को एग्जामिन किया जाना चाहिए, क्योंकि यह पब्लिक इन्ट्रैस्ट का सवाल है। यह मामला अदालत में उठाया जा सकता है। इसलिये मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इस मामले पर जरूर ध्यान दिया जाना चाहिए।

पंडित चिरंजी लाल शर्मा (सोनीपत): डिप्टी स्पीकर साहिबा, माननीय सदस्य चौधरी रिजक राम जी ने बडी ही

इनफर्मेटिव स्पीच दी है। उन्होंने बडा ही सौलिड क्रिटिसिज्म किया हैं जब भी किसी चीज के बारे में सौलिड क्रिटिसिज्म किया जाये तो उसका हमें स्वागत करना चाहिए। उन्होंने बडी मेहनत से गवर्नमैंट आफ इंडिया के आंकडे कलैक्ट करके, सारे हिन्दुस्तान की फिगर्ज कुलैक्ट करके, उन आंकडों को हरियाणा के आंकडों के साथ कमपेरीजन करते हुए और उनका हवाला देते हुए अपने ख्यालात का इजहार फरमाया।

इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि देश में बेरोजगारी का मसला आज बडा गंभीर बना हुआ है। हमारी ही स्टेट में नहीं बल्कि हर स्टेट में बेरोजगारी है। टीचर्ज में भी बेरोजगारी है। आज हमारे क्वालीफाइड इंजीनियर्ज, टीचर्ज और दूसरे पढे लिखे लाखों और करोडों की तादाद में बेरोजगार हैं। जिस तरह से दूसरी स्टेट के अंदर बेरोजगारी है उसी हिसाब से हमारी स्टैट में भी बेरोजगारी है लैकिन मैं यह जरूर कहूंगा कि अगर हरियाणा प्रदेश की फिग्र्ज का मुकाबला दुसरी स्टेटस की फिगगर्ज के साथ कियाजाये तो मैं समझता हूं और मैं कहने में हक बजानब हूंगा कि हमारी पोजीशन दूसरी स्टेटस के मुकाबले में बैटर है।

इलैक्शन के बाद जो सैशन हुआ थ उसमें हरियाणा सरकार की तरफ से कुछ बुक लैटस तकसीम की गयी थी। उनमें यह बताया गया है कि पिछले साल सन 1970–71 में कोई 27 हजार 146 आदमियों को रोजगार दिया गया। उस बुक लैट को

हवाला देते हुए माननीय सदस्य ने फरमाया कि सडकें बनाने के क्रैश प्रोग्राम में बहुत से आदमी लगे हैं, उनमें से अब काफी बेकार हैं। यह बात हो उनकी ठीक है कि अब काफी बेकार हैं लेकिन यह बात भी तो सही है कि उस प्रोग्राम के तहत काफी लोगों को इम्पलाएमैंट मिली थी।

चौधरी रिजक राम जी ने फाइनेन्शियत क्राइसिज का भी जिक्र किया और अपने ख्यालात रखे। डिप्टी स्पीकर साहिबा, जहां तक रोजगार का ताल्लुक है उसके मुताल्लिक मैं अर्ज करूंगा कि रोजगार बहम पहुंचाने के लिए साधन चाहिए। वे साधन पैदा करने पडते हैं हर जगह पर रूपये पैसे की जरूरत होती है। किसी को घर बैठे रूपया तकसीम नहीं किया जा सकता, उस रूपये का जाइज इस्तेमाल इसी तरीके से हो सकता है जिस तरीके से हमारी सरकार ने किया है।

पिछले पांच छः साल के अर्से में बेरोजगारी का मसला हल करने के लिए दो तीन डिपार्टमैंटस की तरफ से काफी मदद की गयी है। वे डिपार्टमैंटस काबले तारीफ हैं। सबसे पहले बिजली के महकमे में क्रैश प्रोग्राम चला, उसके बारे में मैं अर्ज करना चाहता हूं .....

चौधरी दल सिंहः बिजली के महकमे ने तो सारे हरियाणा का सत्यानाश कर दिया, बेडा गर्क कर दिया।

पंडित चिरंजी लाल शर्माः अगर हरियाणा के चप्पे चप्पे में बिजली आने से ही बेडा गर्क होता है तो अंधेरा होने पर तो भटठा ही बैठ जाएग। (विघ्न) डिप्टी स्पीकर साहिबा, मेरे फाजिल दोस्त जो मेरे दायें बाजू पर तशरीफ फरमा रहे हैं कि सबसे और तहमत से सुनें तो सही। चौधरी रिजक राम जी ने अपनी स्पीच में जो कुछ फरमाया है उसमें बडी ठोस बातें बताई हैं। हमें उनको एहतराम करना चाहिए और जो भी अच्छी बातें हों उनको सुनना चाहिए। अगर सरकार कोई अच्छा काम करती है तो उनके बारे में दूसरे साथियों को सुनना चाहिए। ये बातें उनको क्यों अखरती हैं ? हरियाणा के देहातों मैं बिजली पहुंच जाने से जो ट्रिमैंडस प्रोग्रैस हुई है उसकी मिसाल किसी भी स्टेट में नहीं मिल सकती। बिजली पहुंच जाने से सारे हरियाणा को लाभ हुआ है। बिजली के पहुंचने से बेरोजगारी काच भी काफी मसला हल हुआ। हमारे जो क्वालीफाइड इंजीनियर्ज थे, ओवरसीयर्ज थे, लाईन मैन थे वे सैंकडों की तादाद में लगाए गये। जहां तक टीमेटस और मजदूरों का ताल्लुक है वे तो बहुत ही बडी तादाद में लगाये गये। एक मजदूर या एक टीमेट को कोई 156 रूपये के करीब देते हैं और टाईम पर उनको आराम से गुजारा चलता रहा। अब सवाल यह पैदा हुआ कि उनमें से कुछ लोगों को हटा दिया गया। ऐसे क्रैश प्रोग्राम के तहत परमानैंट अप्वायंटमैंट तो नहीं दी जा सकती थी। मैं यह तो जरूर कहूंगा कि इस क्रैश प्रोग्राम के तहत सारे हरियाणा में बिजली का काम राउन्ड दी क्लाक हुआ। उसमें हस्बे जरूरत इंजीनियर्ज ओवरसीवपर, लाइन सुपरइनटैनडैंट और

टीमेटस को नौकरियां दी गयीं। यह भी ठीक है कि जब वह काम पाये–तकसील पर पहुंच गया तो उनको नौकरियां से बर तरफ भी किया गया। वह क्यों किया गया, वह सिर्फ इसलिये किया गया कि जब तक उनकी जरूरत थी। उनको लगाये रखा गया जब काम खत्म हो गया तो उनको हटाना पड़ा। (इस समय सभापतियों की सूची में से एक सदस्य चौधरी स्वरूप सिंह पदासीन हुए) चेयरमैन साहब, जब किसी को मुलाजमात से जवाब मिलता है तो उसे निराशा जरूर होती है, वह मायुसकुन जरूर होता है लेकिन मैं यह कहूंगा कि वह कोई परमानैंट फीचर नहीं था।

चेयरमैन साहब, हमारी स्टेट के अंदर सड़कों को भी प्रोग्राम चलाया गया। हमारी स्टेट के अंदर काफी सड़कें बनी लेकिन हमारे सामने जो निशाना था कि फलां तारीख तक हरियाणा में कोई गांव ऐसा नहीं रहेगा जिसको सडके से न मिला दिया जाए वह शायद पूरा नहीं हो सकेगा। उस प्रोग्राम को पूरा करने के लिये काफी रूपये की जरूरत थी। जहां सरकार के सामने रूपये की कमी आयी वहां साधनों की भी कमी हुई। सडके बनाने के लिये ब्रिक्स अवलेबल नहीं हैं। ब्रिक्स क्यों अवलेबल नहीं हैं, वह कोयले की कमी के कारण नहीं हैं बल्कि ट्रांसपोर्ट की कमी के कारण कोयला समय पर नहीं पहुंच सका। इस कारण से ही ईंटें नहीं मिल सकीं। सडकों के क्रैश प्रोग्राम को पूरा करने के लिये हमने जो डेट मुकर्रर की थी उसको पाया तकमील तक पहुंचने में हम कामयाब न हो सके।

जैसा कि अभी मैंने बताया है कि कुछ साधनों की भी कमी हो गयी। जो हजारों और सैंकडों की तादाद में मजदूर सडकों पर मिटटी डालते थे, रोड़ी कूटते थे, ईंट से सोलिंग का काम करते थे वे बेकार हो गए। इसलिए कुछ साधनों की कमी के कारण हमें यह प्रोग्राम फिलहाल मुलतवी करपा पडा। जब यह काम मुलतवी करना पडा तो वहां पर बेरोजगारी का मसला पैदा हुआ। इसमे कोई दो राय नहीं हो सकतीं कि ऐसी चीजें राज पाल में चलती ही हैं। मैं तो यह कहूगा कि हरियाणा में सारे हिन्दुस्तान से कम बेरोजगारी है। चौधरी रिजक राम जी ने जो तजवीज दी है मैं उस मोहरे तसदीक करने के लिए तैयार हूं। जैसा कि उन्होंने कहा है कि यदि यही हालत हमारे देश में चलते रहे तो जिस तरह से पिछले दिनों बंगाल के अंदर क्रांति आयी और उन नौजवानों ने अपने जजबात की आवाज उठाई, हो सकता है यही हालत दूसरी जगहों पर भी हो जायें। लेकिन मैं यह कहूंगा कि ये जो हालात पैदा हुए यह वहां की गवर्नमैंट के पैदा किये हुए थे। श्री ज्योति बसु की गवर्नमैंट ने ये हालात पैदा किये थे। उन्होंने अपनी पार्टी के वर्कर्ज को एडमिनिस्ट्रेशन में इनफिलट्रेट कर दिया। चेयरमैन साहब, पिछले दिनों आपने सुना होगा कलकता और बंगाल के दूसरे हिस्सों में दस बीस आदमियों को दिन दिहाड़े कत्ल कर दिया जाता था। दिन छुपने के बाद कोई शरीफ आदमी घर से बाहर सैर करने को निकल नहीं सकता था। यह जो भी हालात पैदा हुए ये बेरोजगारी के कारण हुए। लेकिन हमारी हरियाणा सरकार ने फंडज की कमी की वजह या

दूसरी कुछ वजूहात के कारण रोडज के प्रोग्राम को फिलहाल बंद करके एक दूसरे प्रोग्राम को इस पर तरजीह दी है। पानी एक ऐसा मसला है जिसकी जमींदारों को और किसानों को बहुत ज्यादा जरूरत है। चेयरमैन साहब, आपकी इजाजत से मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि जिस वक्त हरियाणा बना, उस वक्त हरियाणा की अनाज की पैदावार यानी प्रोडयूस सिर्फ 26 लाख टन थी और अब से पहले हमारे प्रदेश को बाहर से अनाज मांगना पडता था लेकिन अब हमारी सरकार विदेशों को अनाज एक्सपोर्ट कर रही है।

चौधरी भजन लालः पहले हम एक लाख टन अनाज दूसरे राज्यों से मंगाते थे लेकिन अब हम 20 लाख टन अनाज प्रदेश से बाहर भेजते हैं।

पंडिज चिरंजी लाल शर्माः जैसे कि एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने बताया है कि एक लाख टन अनाज हम पहले मंगवाते थे और अब 20 लाख टन अनाज बाहर भेजते हैं। आप अंदाजा लगाइये जब से हरियाणा वजून में आया है, इस गुजश्ता अर्से में हमारी पैदावार 47 लाख टन हो गयी है। आप अंदाजा लगाइये हमने कितनी तरक्की की है ? इन 5–6 सालों के अर्से में हमारा प्रदेश कितना आगे बढ गया है ? यह तरक्की कैसे हुई है ? इसलिये नहीं हुई कि कुदरत हम पर मेहरबान थी, इसलिये भी नहीं हुई है कि इस अर्से में बारिशें कुछ ज्यादा हुई हैं, इसके लिये सिर्फ एक ही कारण है और वह यह कि हमने इसके लिए साधन पैदा किये हैं। अब आप अपने जिले के अंदर जाइये, हिसार का वह इलाका,

भिवानी का वह इलाका, उधर लोहारू का वह इलाका, जहां पर कभी पीने का पानी नहीं मिलता था वहां अब पानी की कमी नहीं है। पिछली असैम्बली में सन 1962–63 में जिन दिनों में मैम्बर था, हमारे भाई अमर सिंह, सागर राम गुप्ता और मिस्टर जगन्नाथ बडा शोर किया करते थे कि हमारे यहां पानी नहीं हैं हमारे यहां रेत उडती है। हमारे सोनीपत के इलाके में ड्रेनज नम्बर 6 और 8 ने बेडा गर्क कर दिया था। इतना पानी बहा कि लोग बिल्कुल तबाह हो गये। वाकई इस चीज में कोई हकीकत है। चेयरमैन साहब, 15 जुलाई 1970 को मुझे उस इलाके में जाने का इत्तफाक हुआ। यह मैं वह तारीख बता रहा हूं जिस रोज बाबू जगजीवन राम ने जुई कैनाल का उदघाटन किया था। मैंने देखा कि उस इलाके में टिब्बे हैं, जांटी के पंड हैं और जांटी के पेड तो काफी दूर दूर तक दिखाई देते थे, पीने का पानी तो वहां एक परेशान की बात थी। खेतों के लिये तो पानी का सवा0ल ही नहीं था। उस रोज 15 जुलाई 1970 को जब जुई कैनाल का उदघाटन हुआ, मुझे बडा ताज्जुब हुआ, हालांकि वह नहर छोटी सी है, बहुत बडी नहीं है, लोग नहा रहे थे और मै। ऐसा महसूस कर रहा था जैसे उन्हें बहुत बडी नहीं है, लोग नहा रहे थे और मैं ऐसा महसूस कर रहा था जैसे उन्हें बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही हो। ऐसे कह रहे थेः अरे! मेरी मिठरो, जरा मिठो पानी भिवाद दईयो' पानी की तरफ ऐसे देखते थे जैसे कभी देखा ही न हो। कहने का मतलब यह कि वह पानी के लिये तरसते थे। अब आप उस इलाके में जाइये। उस जगह पम्पिंग सैट लगाकर 108 फुट की बुलंदी पर

पानी पहुंचाया गया हे। यह एक अजूबा नहीं तो क्या है। जुई कैनाल, जो बनी है यह 3 करोड 66 लाख रूपये का प्रोजैक्ट था इसमें हमारी सरकार ने 50–52 लाख रूपये बचा लिये। दो करोड रूपया हमें गवर्नमैंट आफ इंडिया से इसके लिये मिला। एक रिकार्ड पीरियड के अंदर जिसका वर्ल्ड के अंदर रिकार्ड है, इस प्रोजैक्ट को पाय तकमील तक पहुंचाया गयां

पिछले 19 सितम्बर 1971 को चीफ इंजीनियर ने उधर का टूर रखा था, मुझे भी हरियाणा इरीगेशन डिपार्टमैंअ की एडवाइजरी कमेटी का मैंबर होने की हैसियत से वहां जाने का इत्तफाक हुआ। 15 जुलाई 1970 से 19 सितम्बर 1971 के बीच के अर्से में मैंने उस जगह जमीन आसमान का अंतर देखा। उस इलाके की वह जमीन जो काला रंग अख्तियार कर चुकी थी, पम्पिंग सैट लगा कर पानी को लिफ्ट करके जो नहर बनाई गयी है, उसकी वजह से वहां गुलाब के पौधे और हरियावल दिखाई देते थे। इस जुई कैनाल से उस इलाके को सैराब करने के लिये साधन उत्पन्न किये गये। इनमें दो रायें हो सकती हैं और नुक्ता चीनी की जा सकती है कि यह प्रोजैक्ट इकौनोमिकल नहीं है या इस प्रोजैक्ट में यह नहीं किया गया है, वह नहीं किया गया है। चेयरमैन साहब, हथेली पर सरसों, हरी नहीं होती। यह तो वक्त बतायेगा कि इसका कितना फायदा होता है। आखिर यह कैनाल आहिस्ता आहिस्ता एक पैरेनीयल सूरत अख्तियार करेगी। इसके साथ ही साथ हमारी सरकार ने एग्रीकल्चर की डिवैल्पमैंट के लिये

व जमींदारों की पैदावार बढाने के लिये और भी साधन मुहैया किये हैं जैसे लोहारू कैनाल है और चक्रवर्ती कैनाल है ऐसे ही कई और प्रोजैक्ट हैं। चेयरमैन साहब, आपकी विसातत से, मैं बडे अदब के साथ यह अर्ज करना चाहता हूं कि जहां तक एग्रीकल्चरल डिवैल्पमैंट का ताल्लुक है, किसान को साधन देने का ताल्लुक है या किसान को सहूलियतें पहुंचाने का ताल्लुक है, हरियाणा सरकार ने एक मिसाल कायम की है, न सिर्फ हरियाणा प्रान्त में बल्कि हिन्दुस्तान भर में। चेयरमैन साहब, अगर मैं आपकी इजाजत से, नैशनल कमीशन आन एग्रीकल्चर, जो हमारी गवर्नमैंट आफ इंडिया का एक कमीशन है जिसके चेयरमैन हैं मिस्टर नाथू राम मिर्धा– जिस के नाम से आप सब साहिबान वाकिफ हैं और दूसरे एक मैंबर हैं श्री शिव रमन, जो एक बडे सीनियर आदमी हैं और पहले कैबिनेट सैक्रटरी हुआ करते थे, की रिपोर्ट हरियाणा के बारे में पढूं, तो मैं समझता हूं कि सब खुशी के मारे झूम उठेंगे। उन्होंने यानी नैशनल कमीशन आन एग्रीकल्चर ने यह लिखा है कि हरियाणा के इंजीनियर्ज ने यह प्रोजैक्ट बनाकर एक अजूबा कर दिखाया है और इससे हरियाणा की उन्नति और हरियाणा के विकास की तरफ काबिले तारीफ काम हुआ है। यह बात मैं नहीं कर रहा। यह बात हमारी सरकार यानी हरियाणा सरकार नहीं कहीती, यह तो नैशनल कमीशन आन एग्रीकल्चर की रिपोर्ट है। उन्होंने यह भी लिखा कि यह जो बावल प्रोजैक्ट है, जिसे 'जवाहर हाल नेहरूर कैनाल' के नाम से पुकारा जाएगा, अगर पाये तकमील तक पहुंच जोय तो इससे महेन्द्रगढ जिले का, झज्जर तहसील का,

रिवाडी तहसील का जाटुसाना, बावल और सोहना का वह इलाका जहां पानी नहीं पहुंचता, सैराब हो सकेगा और इससे हरियाणा की काया कल्प हो सकती है। चेयरमैन साहब, मैं अपनी गवर्नमैंट से पुरजोर अपील करूंगा कि वह इस बावल प्रोजैक्ट को पाय तकमील तक पहुंचाने के लिये भारी सरकार पर जोर डाले, अपने आप को असर्ट करे और उन्हें यह कहे कि हमें रूपया दो, क्योंकि रूपये के बगैर यह प्रोजैक्ट पूरा नहीं होगा। इसके लिये जितना भी जोर लगाना पडे हमारी सरकार को लगाना चाहिए। यह मेरी सारे हाउस की तरफ से सरकार को तजवीज है और मैं समझता हूं कि इस बारे में अपोजीशन के भाई भी मुझसे मुत्तफिक होंगे कि इस प्रोजैक्ट के बनने में, जिससे हरियाणा के खुश्क इलाकों को पानी मिल जाये और जमींदारों को अपने खेतों को सैराब करने के साधन मिल जाएं, किसी को कोई एतराज नहीं हो सकता। लेकिन मेरा कहना यह है कि हमारी गवर्नमैंट इस बारे में जरा जोर लगाये।

चेयरमैन साहब, सप्लीमैंट्री एस्टीमेटस पर की गई बातों को सुनकर बडा ताज्जुब हुआ। 83265550 रूपये की डिमांडज में से 7 करोड 91 लाख की एक डिमांड है जिसका नम्बर है: 43। बाकी तो छोटी छोटी आईटम्ज हैं। जहां 7 करोड 91 लाख रूपये की डिमांड का ताल्लुक है, यह रावी व्यास प्रोजैक्ट के लिये हैं। अभी रावी–व्यास प्रोजैक्ट पाये तकमील तक नहीं पहुंचा। अभी यह कमीशन नहीं हुआ। हमें उसका अभी कोई फायदा पहुंचना शुरू

नहीं हुआ। इसमें कुछ अर्सा दरकार है, लेकिन गवर्नमैंट आफ इंडिया इमसे इनस्टलामैंट विद इन्ट्रैस्ट एण्ड कैपिटल मांग रही है। हमारी गवर्नमैंट मेरी इस गुस्ताखी के लिये मुझे माफ करेगी, अगर मैं यह कहूं कि भारत की सरकार इस बारे में हमारे साथ ज्यादती कर रही है और हमारे साथ जुल्म कर रही है। अभी हमने प्रोजैकट शुरू किया नहीं, अभी हमें उसकी यूटिलेटी का पता लगा ही नहीं कि क्या होगी, काम वह पाये तकमील तक पहुंचा नहीं और हमें कुछ हासिल हुआ नहीं लेकिन गवर्नमैंट आफ इंडिया यह कहतती है कि इन्स्टालमैंट विद इन्ट्रैस्ट एंड कैपिटल दो। चेयरमैन साहब, मैं आपकी विसातत से गवर्नमैंट से पुरजोर अपील करूंगा कि वह गवर्नमैंट आफ इंडिया से लडें कि हमारे छोटी सी स्टेट है। हमारे लिमिटेड रिसोर्सिज हैं, हमारे साधन सीमित हैं, हमारी गिच्ची पर अंगूठा क्यों दिया जा रहा है। यह हमारे साथ ज्यादती है। इस बारे में हरियाणा सरकार को भारत सरकार से लडना चाहिये कि हम उस वक्त तक जब तक कि रावी व्यास प्रोजैक्ट कमीशन नहीं होगा न हम इंस्टालमैंट, कैपिटल व इंट्रेस्ट देने के लिये तैयार हैं और न देने की पोजीशन में हैं और मैं समझता हूं कि इसमें सारे हाउस का सहयोग होगा क्योंकि इसमें प्रांत की भलाई का सवाल है और जो अच्छी बातें हैं उनमें से सब का सहयोग होना चाहिए। चौधरी रिजक राम ने दो तीन बातें और कहीं जो कि बहुत ठोस थीं। सर्विसिज के मुकाबजे में सर्विसिज के लिये इम्तहानों में बाहर के आदमी हरियाणा से ज्यादा आते हैं। मैं इस बात की ताईद करता हूं कि हमारे लिए आल इंडिया कम्पीटीशन में जैसे

आई0ए0एस0, आई0एफ0एस0, आई0पी0एस0 के अलावा दूसरी स्टेटस में कोई जगह नहीं है क्योंकि हर स्टेट में भाषा के आधार पर सर्विसिज में जगह देते हैं। जैसे पंजाब है वहां पंजाबी हैं हम पंजाबी लिख नहीं सकते। बंगाल मे ंजाओ वहां बंगाली है (व्यवधान) अंग्रेजी तो सभी की जवान है। लेकिन हरियाणा ने इतनी उदारता दिखाई हुई है कि हमारे यहां किसी भी सूबे का आदमी आ जाए। वाकई इससे हमारे बच्चों के गले कटते हैं। हमारे से मतलब यह है कि हरियाणा का वह पाकसार जमीन के वे भाई जो इन छह सात जिलों में रहते हैं। हरियाणा का यह मतलब नहीं कि वह लोग जो पंजाब से यहां आए, जो अपने को शरणार्थी कहते हैं या रिफ्यूजी कहते हैं, वे वे हरियाणा के बाशिंदे नहीं हैं। जो हरियाणा में रहती है वह हरियाणवीं हैं। यह तमीज बिल्कुल खत्म होनी चाहिये। ये शब्द हमीन के इतनी नीचे दफना देने चाहिएं कि हमारी आने वाली पीढियों को उसकी बदबू तक न आए। पाकिस्तान से जो भाई इधर आए वे अब पंजाबी नहीं बल्कि हरियाणवीं हैं। जो हरियाणा की सर जमीन पर रहता है, चाहे पाकिस्तान से आया है, चाहे बंगाल से आया है, वह हरियाणवी है। किसी को यह गलतफहमी नहीं रहनी चाहिये और अगर किसी के दिमाग में इस किस्म की तमी है कि जो यहां की लोकल पापूलेशन है वह हरियाणवी है, जो पाकिस्तान से आए हैं वह हरियाणवीं नहीं हैं तो मैं इसको हिमाकत ही कहूंगा। जहां तक सर्विसिज में हरियाणा के लोगों को लेने को ताल्लुक है मैं तो इसका समर्थन करूंगा कि सर्विसिज में हरियाणा के रहने वालों को लिया जाए।

मैडीकल या दूसरे एडमीशंज के बारे में हमने देखा है कि हमारे यहां मैडीकल एडमीशन में बाहर के काफी लोग आते हैं जबकि हमारे यहां के लोगों को काफी दिक्कत होती है। हमारे यहां के लडकों को हरियाणा के अलावा कहीं बाहर दाखिला नहीं मिला। चेयरमैन साहब, जो अच्छी बात कहीं जाए वह किसी तरफ से आए उसको अपनाना चाहिए।

अभी चौधरी रिजक राम ने एक बात और कही। आज जो बिरलाज और टाटाज हैं, मैं बिरलाज़ की बाबत कहूं कि यह कोई बंगाल के रहने वाले नहीं बल्कि ये पिलानी के रहने वाले हैं। लेकिन इनकी जो फैक्टरी बंगाल में है उसमें पांच सात परसैंट को छोड़कर जो कि मारवाडी होंगे बाकी सारे कर्मचारी बंगाली हैं। लेकिन हमारे यहां जो फैक्अरी हैं उनमें आपको हर जगह के लोग मिल जाएंगे। कहीं पुरबिया होंगे, कहीं किसी और प्रान्त के होंगे। सारे हिन्दुस्तान के लोगों को यहां जगह मिलती हैं। तो यह चीज काबिले गौर है। यहां पर हमारे वजीर चौधरी भजन लाल बैठे हैं। मैं उनसे अर्ज करूंगा कि जब हम एक इंडस्ट्रीयलिस्ट को प्लाट देते हैं, फाइनैंस भी देते हैं और भी दूसरी सहूलियत देते हैं तो यह चीज उनको कहें कि यह बात आपको माननी पडेगी कि जब आप हरियाणा की पवित्र भूमि पर इंडस्ट्री लगाने जा रहे हैं, हरियाणा की भूमि से आपको फायदा होगा, हमारी यह कंडीशन है कि हरियाणा के नौजवानों को सर्विसिज में प्रिफ्रैंस दिया जाए। यह

ठोस सजेशन है आढैर इसमें गवर्नमैंट के जोर से सहारे से, काफी आदमियों की रोजगार की खासी मदद लि जाती है।

लाला रूलिया रामः मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। पंडित जी ने फरमाया ..... (व्यवधान)

श्री सभापतिः आप बैठ जाइए।

पंडित चिरंजी लाल शर्माः चेयरमैन साहब, बात ऐसी है कि अगर कोई बात गलत है या जो अखरती है, हाउस के हरेक मैम्बर को अधिकार है .....

श्री सभापतिः सैशन पांच बजे खत्म हो जाएगा और अभी जवाब भी आना है, अब आप खत्म कर दें।

पंडित चिरंजी लाल शर्माः चेयरमैन साहब, अगर ऐसा है तो मैं बैठ जाता हूं। थैंक यूं।

चौधरी रिजक रामः चेयरमैन साहब, कमेटी में यह फैसला हुआ था कि अगर आज खत्म न हो तो यह कल भी चाल रह सकता है। मेरी गुजारिश यह है कि यह डिमांडज जरूरी है इसलिए सबको बोलने का अवसर दिया जाए।

श्री सभापतिः रूल 214 की सब रूल (4) में लिखा हुआ है कि–

"On the last day of the days so allotted, the Speaker shall one and a half hour before the normal hour of

interruption of business, forthwith put every question necessary to dispose of the demand under consideration.

चौधरी रिजक रामः इसमें तो कोई एतराज नहीं है। मेरी तो इतनी गुजारिश है कि अगर खत्म न हो तो कल भी हो सकती है, एप्रोप्रिएशन बिल भी कल आ सकता है। कल कोइ काम नहीं, परसों भी कोई काम नहीं है।

श्री सभापतिः हम पहले ही बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट एडोप्ट कर चुके हैं उसके मुताबिक चलना पडेगा। इसके बाद भी दो तीन आइटमज हैं। इसका मतलब यह है कि यह आज के दिन के लिए हैं कल के लिए नहीं है।

चौधरी रिजक रामः मेरी अर्ज है कि जो काम रह जाए वह कल के लिए चला जाए ऐसा फैसला हुआ था। आप स्पीकर साहब से वैरीफाई कर लें।

श्री सभापतिः काम अगर बाकी रह जाएगा तो लास्ट आइटम आफ दी अजेन्डा कल पर जाएगा।

4.00 सायं।

श्री अमर सिंहः चेयरमैन साहब, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है इस समय हाउस में बडी जरूरी डिस्कश हो रही है और हमारे एम0एल0एज0 साहिबान अपनी अपनी कांस्टीच्यूऐन्सीज के बारे में और इन सभी डिमांडज पर बोलना चाहते हैं। इसलिए मेरी आपसे रिक्वैस्ट है कि वे अगर आज न बोल सकें तो इस मसले को किसी

अगले दिन के लिए रख लिया जाए ताकि हमारे सभी भाई इन डिमांडज पर अपने अपने विचार खुल कर इस हाउस में रख सकें।

श्री सभापतिः यह आइटम तो ऐसी है जो एडजर्नन हो ही नहीं सकती क्योंकि पहली आइटम है। इसके अलावा और दूसरी आइटमज भी रखी हुई हैं। फिर इस बारे में रूलज भी क्लीयर हैं। यह तभी हो सकता है अगर बिजनैस एडवाईजरी कमेटी इस डिस्क्शन के लिए एक दिन की बजाये दो दिन अलाट कर दें।

चौधरी रिजक रामः चेयरमैन साहब, हमारी प्रार्थना है कि अगर यह फैसला बिजनैस एडवाईजरी कमेटी से हुआ है तो ठीक है। अगर दूसरी कोई बात सामने न आए तो फिर इस तरह से कर देना। मेरी राय है कि आप इस बारे में पहले वैरीफाई कर लें।

चौधरी शिव रामः चेयरमैन साहब, यह फैसला हुआ था कि जो काम आज पूरा न हो सके वह आप अगले दिन पर चला जाएगा और डिस्कशन पूरी चलेगी। जबानी बात तो यह थी। लीडर आफ दी हाउस आ गए हैं, आप उन्हें इस बारे में पूछ लें।

श्री सभापतिः यह फैसला भी हुआ होगा कि अगर यह पहली आइटम होगी तो कल पर नहीं जा सकती और लास्ट आइटम जो रह जाएगी वह कल पर जा सकती है। बिजनैस

एडवाईजरी कमेटी की रिपोर्ट आपके सामने भी है और मेरे सामने भी है, आप देख लीजियें इसको हाउस एप्रूव कर चुका है।

चौधरी बंसी लालः चेयरमैन साहब, ये लोग ज्यादा उतावले क्यों होते हैं। जब ये बोल बोल थक जाएंगे तब ही हम हाउस को एडजर्न करेंगे। इसमें कोई झगडे की बात नहीं है। इन डिमांडज पर एप्रोप्रिएशन बिल भी आना है उस पर बोल लें। इन लोगों की सबसे ज्यादा शिकायत इलैक्ट्रीसिटी बोर्ड के बारे में होती है उसमें वह बात कलीयर है और उसके लिए सैपरेट रैजोल्यूशन आ रहा है। जो डिमांडज हाउस के सामने पेश हैं, उससे बाहर, आऊट आफ दी डिमांड, डिस्कशन नहीं हो सकेगी, जिस तरह से चौधरी रिजक राम जी बोलते हैं।

चौधरी फुल चन्द (रोहट एस0सी0): चेयरमैन साहब, एक सप्लीमैंट्री डिमांडज की कापी मेरे हाथ में है और मैंने उसको अच्छी तरह से पढा है और उसका अध्ययन भी किया है। मुझे कुछ अफसोस हुआ कि आठ करोड में करीब रूपया हम उसें खर्च करना चाहते हैं। यह हमारी मांग है और उसमें बहुत से मदों तक हम अखराजात देख रहे हैं लेकिन उसमें कोई कालम ऐसा नहीं पढा गया जिसमें हरिजन वैलफेयर के लिये मांग की गई है। मैं इस मौके पर आपको यह याद दिलाता हूं कि पिछली बार भी जब गवर्नर साहब का अभिभाषण इस हाउस में हुआ था उस समय भी इस किस्म की बात हुई थी, उस समय भी हमारे साथियों को बिल्कुल फरोमोश कर दिया था। इस बार जब कैबनिट में यह

मामला था तो शायद वैलफेयर वजीर सोए हुए थे या वे उंघ रहे थे। मैं यह समझता हूं कि ये एस्टीमेटस अधूरे हैं क्योंकि वह बहुत जरूरी चीज है। हरियाणा के लीडर जब भी कोई भाषण देते हैं तो उन्हें इस का जिक्र करना पडता है इसके बगैर गवर्नमैंट भी नहीं बन सकती।

श्री सभापतिः देखिये, इसके अंदर बहुत सी डिमांडज तो नहीं है, अगर आप उन पर चलेंगे तो यह एक बडी लम्बी चौडी डिस्कशन हो सकती है।

चौधरी फुल चन्द (रोहट एस0सी0): चेयरमैन साहब, मैं तो सिर्फ याद दिला रहा हूं। अगर इस बार खाली रह गया तो कम से कम अगली बार तो उनको याद रखैंगे। चेयरमैन साहब, इन डिमांडज पर चौधरी रिजक राम जी ने बहुत कुछ कहा और पंडित चिंरजी लाल ने उसकी तायद की है। इस बात से मुझे बहुत तसल्ली है। चेयरमैन साहब, स्पीकर साहब, बहार के मुल्क में जा रहे हैं। अक्तूबर 1972 में कांफ्रैंस होने वाली है, उस कांफ्रेंस में वे जाएंगे। यह बड़ा खुशी का मु काम है। आंखों देखा हाल हम उनसे यहां सुनेंगे और जिस सुचारू रूप से वह इस समय हाउस का काम चला रहे हैं, इससे भी अच्छा कार्य करेंगे। इसके साथ साथ मैं यह भी कहूंगा कि उनके साथ वाली सीट अगर खाली हो तो अपोजीशन के लीडर को उस पर बैठने का मौका दें कि वे भी इस कांफ्रैंस में भी ले सकें और वह वाहं से सारी बातें सीखें और हमें भी यहां आकर के सारी बातों की जानकारी कराएं। इससे इस

हाउस की रौनक भी बढेगी। (हंसी) स्टेटस में भी बहुत फर्क आएगा। इसके साथ साथ मैं यह भी कहूंगा कि अगर यह बात इस दफा मुमकिन न हो तो अगला मौका उनको जरूर दिया जाए। (हंसी) चेयरमैन साहब, मैं इसके साथ साथ इस हाउस में अन एम्पलायमैंट के कारे में कुछ कहना चाहता हूं। इस काम के लिए सरकार का काफी रकम खर्च करने का विचार है। मैं आपके के रूबरूह मानता हूं कि हमने अन एम्पलायमैंट को खत्म करने के लिये बहुत कदम उठाए हैं लेकिन फिर भी हम इसके लिए फिकरमंद हैं। यह जो बेकारी का मसला है। यह हम लोगों को खाने लग रहा है। किसी तरी भी यह काबू नहीं हुआ है लेकिन यह भी दुरूस्त है कि जब इसका हल करने के लिए गवर्नमैंट कदम उठाती है तो वह महज नारेबाजी तक महदूद रह जाती है, इसमे लिखा गया है कि

"..... The scheme was also aimed at to provide employement opportunity to the unemployed Engineering and Agricultural graduates."

चेयरमैन साहब, यह मेरे ख्याल में योजना बना कर घोषणा करने वाली बात है। 1968 को जिन लोगों ने एम्पलायमैंट एक्सचेंजिज के अंदर नाम दर्ज करवा रखे थे इसके बारे में मैं कुछ दिन हुए एम्पलायमैंट एक्सचेंजिज में गया था ताकि यह पता लगाया जा सके कि रजिस्टर्ड करवाये गये लोगों में से कितनों को रोजगार मिल गया है। मगर उन्होंने एक मोटा अच्छा रजिस्टर निकाल कर बताया कि सन 1968 में जो नाम दर्ज हुए थे वह

निकले नहीं। तो मैंने कहा कि जो रूल्ज एम्पलायमैंट और अर्बन एम्पलायमैंट के पोस्टटर थे जो इतना लम्बा चौडा प्रोपेगंडा किया जाता रहा है। वह 1968 से 1970 तक रूक गया है और उससे जो आगे चला है यानी उसके बाद जिन आदमियों को एम्पलायमैंट दी हैं उन लोगों को हवाई जहाज से लाकर देते हैं या गवर्नमैंट ने कहीं बाहर से लाकर दी है। मैं अप से निवेदन करूंगा कि इस बात को आप चैक करके पड़ताल करें कि यह मामला कहीं स्टैटिसटिक्स तक ही आकर तो नहीं रह गया। हमारी तो यकीन करने की आदत है और हम यकीन करते भी हैं लेकिन हम कहते हैं कि आप पता कर लें कि कहीं वे कोई गोटाला तो नहीं कर रहे। स्टैटिसटिक्स में तो बताया जाता है कि इतने लोगों को सर्विस दो तो फिर इस बात की समझ नहीं आती कि 1968 के नाम कैसे रूके पडे हैं। मैं चाहूंगा कि आप इस बात को देखें और लोगों को गुमराह करने की कोशिश न करें। (विघ्न) मुझे सुनाई नहीं दिया। आपने क्या कहा चौधरी साहब।

एक माननीय सदस्यः आप अपने कान ठीक करवाएं।

चौधरी फूल चन्द (रोहट): तो चेयरमैन साहब, मैं अर्ज कर रहा था कि आप इन बातों की तरफ तवज्जो दी। चेयरमैन साहब, हमारी हकूमत ने अगली डिमांड एक्सग्रेशिया ग्रांट टू दी फैमिलीज आफ आर्मड परसोनल के लिये पेश की हैं। जो लोग फौज में थे और सरहदों पर जिन्होंने कुरबानियां की आज उनकी जो निशानी बाकी है, उनकी जो फैमिलीज और बच्चे हैं उनके

लिए मैं इस बात को मानता हूं कि हमारी हकूमत ने काफी कुछ किया है। ससाने गांव में हमारे एक मेजर हैं जिनको परमवीर चक्र मिला है और उनको हमारे मुख्यमंत्री चौधरी बंसी लाल जी ने खुद वहां पर जाकन निवाजा और उनकी हौसला अफजाई की। हरियाणा की फौजी कुव्वत और यहां के किसानों के स्टैमिना की लोग बाहर भी तारीफ करते हैं। हमारे हरियाणा के फौजी जवान बाहर के जनरलों के साथ जिन जिन सरहदों पर लडे उन्होंने अपनी बहादुरी का उनके दिमागों पर एक अक्स छोडा और हमारे हरियाणा का सारी दुनियां में सर ऊंचा किया है। इसलिए मैं कहूंगा कि यह 11 लाख रूपए की रकम उनके लिए बहुत ही थोडी है एक कलील रकम है। आप अंदाजा लगाएं कि जिन लोगों ने सरहदों पर जानें दी उनकी कुरबानियों की वजह से हरियाणा का नाम बहुत रोशन हुआ है। इसलिए उनकी हौसला अफजाई के लिए जितनी भी ज्यादा रकम इस मद में रखी जाए उतना ही अच्छा होगा और मैं अपनी सरकार से कहूंगा कि वह इस तरफ ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें।

चेयरमैन साहब, एक मद में जिक्र है कि जो इंडस्ट्रीयल बैल्ट सोनीपत में बनी थी उसकी तरफ दोबारा ध्यान देंगे। मैं अर्ज करूंगा कि इस बात के लिए कई बार अश्योरैंसिज दी गई हैं कि वहां सब सहूलतें दी जाएगी और उसे डिवैल्प किया जाएगा लेकिन आज अगर वहा ंपर जाकर देखा जाए तो आपको वहा ंपर प्लाट वैसे ही खाली पडे हुए दिखाई देंगे। वहा ंपर कुछ लोगों ने

कोशिश की कि वे इंडस्ट्री लगाएं लेकिन जब उनको पूरी सुविधाएं नहीं मिल पाई तो वे छोड छोड कर चले गए। वहां पर 120 इंडस्ट्रीज में से सिर्फ चार या पांच काम कर रही हैं। चेयरमैन साहब, मैं यह बात कहते हुए आपसे माफी चाहूंगा कि कई लोग तो ऐसे हैं जो सिर्फ सरकार से कोटा लेकर ब्लैक में बेच कर मुनाफा लेते हैं और दिखावे के लिए उन्होंन शोरूम बना रखे हैं। इस बात की चर्चा तो बहुत से लोग करते हैं कि वे कोटा ब्लैक में बेचते हैं लेकिन चूंकि उनके काफी लम्बे चौडे हाथ हैं इसलिए उन्हें कोई पूछता नहीं। लेकिन जो लोग सर्विस छोड कर वहां पर काम करना चाहते हैं उनको अगर कोई सुविधा न मिले तो वह बेचारे मायूस होकर चले जाते हैं। इसके इलावा जो छोटे यूनिटस हैं, जो छोटी इंडस्ट्री का काम करना चाहते हैं लेकिन वे आक्ट्रोय के चक्कर को देखकर ही काफी है, कुछ लोग इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं लेकिन वे आक्ट्राय के चक्कर को देखकर चले जाते हैं। तो मैं आपसे अर्ज करूंगा कि इन सब बातों पर ध्यान दिया जाए। हमारे चीफ मिनिस्टर साहब के पास वहां के लोग अर्जदाश्त भी लेकर आए थे, इसलिए मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वहां पर सारी सहूलतें मुहैया करके उस इंडस्ट्रियल बैल्ट को डिवैल्प करनै की कृपा करें। अब मूरथल में भी डिवैल्पमैंट करने लगे हैं, यह बडी अच्छी बात है है इंडस्ट्री को फरोग देना चाहिए।

गृह मंत्री (श्री के0एल0 पोसवाल): दूसरो के कहने पर आप ने कहें, आप अपनी बात करें।

चौधरी फूल चन्द (रोहट): इन की सलाह तो बडे बडे लिया करते थे, मैं तो एक बहुत छोटा सा आदमी हूं।

चौधरी बंसी लाल: जो सलाह लिया करते थे डूबते भी वही रहे।

चौधरी फूल चन्द (रोहट): चेयरमैन साहब, इन डिमांडज में जो कृषि के संबंध में या पानी के साधनों को बढाने के लिए जो रूपया रखा गया है वह बहुत नाकाफी है, इसके लिए जितना भी ज्यादा रूपया रखा जाए उतना ही थोडा है। मेरे से पहले पंडित चिरंजी लाल जी ने कहा था कि जुई कैनाल तेजी के साथ बननी चाहिए। हम तमाम लोग भी इस बात के हक में हैं कि कैनाल जल्दी बननी चाहिए। हम किसी भी डिवैल्पमैंअ की स्कीम के खिलाफ नहीं हैं मगर इतनी बात जरूर है कि कई बार कई चीजौं के बारे में हमें शकूम पैदा होते हैं और वे कई बार दरूस्त भी होते हैं क्योंकि काम करने वाले जो लोग होते हैं वे बीच में गोटाला करते रहते हैं। तो इसलिए अगर हम कोई चीज नुक्स दूर करने के लिए प्वायंट आऊट करें तो उसे बुरा नहीं मानता चाहिए। बल्कि उन बातों पर गौर करके जो शिकायतें हों उनको दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। बल्कि उन बातों पर गौर करके जो शिकायतें हों उनको दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। आज कल हमारे रोहतक जिले में यह खदशा जाहिर किया जा रहा है, और आम लोगों की यह शिकायत भी है कि पहले की निसबत मोरियों का पानी बहुत कम हो गया है, जो मोरियां थीं उनकी

आगे की बैल्टस बहुत तंग कर दी गई हैं और खेतों में पानी बहुत कम आता है। मालूम नहीं पडता कि ऐसे क्या मसलाहात थे जिसके कारण पहले पहले जो ज्यादा पानी मिलता था उसे कम कर दिया गया है। मैं जानता हूं कि आप कह सकते हैं कि ब्यास का पानी मिलने के बाद पानी की बहुतात हो जाएगी लेकिन मैं यह गुजारिश करूंगा कि जिन जिन इलाकों को पहले पानी मिलता था उनको पूरा पानी दें और जहां कहीं मोरियां तंग की गई हैं उन्हें ठीक करवाएं। इन शब्दों के साथ मैं इन सब डिमांडज की सपोर्ट करता हूं और अपना स्थान लेता हूं। थैंक यू।

चौधरी मनफूल सिंह (झज्जर): चेयरमैन साहब, हाउस में दो तीन मैंबर साहिबान ने जनरल भाषण किया है लेकिन मैं जनरल भाषण करने की बाजये जो डिमांडज हाउस के सामने हैं उन पर अपने विचार रखूंगा। मैं आपके जरिये मुख्य मंत्री जी और दूसरे बुजरा साहिबान के सामने जो कुछ दिक्कतें हैं लोगों की वह अर्ज करना चाहता हूं। सबसे पहले मैं अर्ज करता हूं कि जो इरीगेशन के लिए डिमांडज रखी गई हैं। वह बहुत जरूरी हैं। हमारे प्रान्त ने रोडज के बारे में, बिजली के बारे में और दूसरी तरविक्याती कामों के बारे में काफी डिवैल्पमैंट की है लैकिन हमारे सामने इस वक्त रोटी का मसला है जो कि प्रांत को बुनियादी सवाल है। आप जानते हैं कि खेती का आधार पानी है और पानी नहरों से भी जाता है बिजली गई है तो टयूबवैल्ज लगे हैं और उनसे भी पानी मिलता है लेकिन फिर भी अर्ज करूंगा कि हर गांव

में तकरीबन आधा रकबा ऐसा है जो खारा है जहां टयूबवैल नहीं लग सकते हैं और न पम्पिंग सैंटस लग सकते हैं। वहां पर नहरी पानी जाना जरूरी है। नीचे तक डीप बोरिंग भी कराई गई है गवर्नमैंट के जरिए भी और प्राइवेट तौर पर भी लेकिन कामयाबी नहीं हुई। तो मेरे कहने का मतलब है कि कम से कम आधी जमीन ऐसी है जिसमें नहर का पानी नहीं है। जब तक हर किसान को उसकी 100 फीसदी जमीन को 12 महीने पानी नहीं मिलता उसे हम नहरी जमीन और दो फसली आबपाशी वाली जमीन नहीं कह सकते और जक तक सारी जमीन को सैराब नहीं किया जाता तब तक हमारे प्रदेश में खुशहाली नहीं आ सकती और लोगों की आमदनी नहीं बढ सकती। इस बारे में कई स्कीमें कई साल से अधूरी चली आ रही हैं। रिवाडी लिफ्ट स्कीम कोई 12/14 साल पहले शुरू हुई थी और यह स्कीम कई करोड की थी लेकिन अभी तक अधूरी पडी हैं। कुछ जगह खोदी गई हैं और बीच बीच में रह गई हैं। झज्जर तहसील में 20/25 मील खोदी गई थी लेकिन न उसमें कोई मोरी है और न पानी जाता है लेकिन हर साल 30/40 लाख रूपया अलाट हो जाता है और काम सिरे चढने में नहीं आता है। जब तक इस स्कीम को मुकम्मल नहीं किया जाता जो कि करोडों की स्कीम है उस वक्त तक झज्जर रिवाडी और महेन्द्रगढ के इलाकों को कोई फायदा नहीं हो सकूता और वह खुश्क इलाके सैराब नहीं हो सकते। इसलिए इसी तरफ फौरी तौर पर ध्यान दिया जाए और इसे मुक्कल करके उन इलाकेां को पानी दिया जाए। इसके साथ मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि नहरी

रूल्ज भी अजीब किस्म के हैं। जहां नहर जाती हैं और थोडा बहुत नहर का पानी मिलता है वहां पटवारी और दूसरा अमला इतनी गडबड करता है कि जिसकी मिसाल नहीं मिलती। इसकी वजह यह है कि रूल्ज में कमी है और उसमें नुक्स हैं, जो कि पटवारी को गडबड करने का मौका देते हैं। एक किसान के पास अगर 10 किल्ले जमीन है और उसे एक बारी में एक किल्ले को पानी आता है दूसरी बारी में दूसरे किल्ले को पानी आता है और इस तरह बारी बारी से एक एक किल्ले को पानी मिलता है लेकिन अगर आपको गेहूं के लिये 6 पानी की जरूरवत है और आता एक पानी है फिर भी उसे सारे गेहूं का सारा आबियाना देना पडता है। सारा अबियाना उसे तब हो ना चाहिये जब उसे गेहूं के लिये 6 पानी की जरूरत हो तो 6 पानी मिलें और ईंख के लिये 8 पानी की जरूरत हो तो 8 पानी मिलें एक बार पानी आ जाये और 5 बारे अगर पानी न आये तो गरीब किसान का गेहूं सूख जाता है लेकिन उससे आबियाना पूरा लिया जाता है। यह बात ठीक नहीं है। दूसरा गिरदावरी का बडा नुक्स यह है कि काश्तकार को नहर का पानी दिया है या नहीं दिया लेकिन पटवारी गिरदावरी दर्ज कर देता है। कोई अपील नहीं कोई दलील नहीं और वह इसलिये कि कोइ रूल नहीं जिससे सुनवाई हो सके। किसान को 6 महीने के बाद परची मिलती है और उसे सारा आबियाना देना पडता हैं चाहें दो तीन सौ का बिल आ जाये। रूल में हैं कि 15 दिन में अपील हो सकती है लेकिन उसे पता ही नहीं होता और समय ही नहीं मिलता। यह जो गडबड है पटवारी करते हैं और वे पेसे खाते हैं।

गिरदावरी में गडबड करके। होना यह चाहिये कि किसान को नोटिस हो कि उसके नाम इतनी बीघे की गिरदावरी है और इतना आबियाना है लेकिन उनको तो वसूली के वक्त ही पता लगता है कि इतने पैसे देने हैं। इसके इलावा फल्ड आते हैं और वहां से ड्रेन नं0 6 और 8 जाती हैं और सैलाव लाती हैं। एक गांव का चार हजार बीघे रकबा है उसमें सारे के सारे में सैलाब आ गया लेकिन सारे का सारा आबियाना वसूल होता है। यह बात सरकार के नोटस में भी बार बार लाई गई और अफसरों को भी बताई गई लेकिन कोई नहीं सुनता। रूल्ज ऐसे हैं कि एक किसान ने पानी नहीं लिया उसकी सावनी की फसल खडी है और उसमें फ्लड का पानी आ गया तो उस हालत में चाहिये तो यह कि किसान को मुआवजा दिया जाये कि पहली फसल खराब हु ई और दूसरी फसल की बुआई नहीं हो सकती लेकिन उससे सारा आबियाना लिया जाता है कोई सुनता नहीं है। मैं सरकार से अर्ज करना चाहता हूं कि इस तरफ ध्यान दिया जाये और इन रूल्ज को अमैंड किया जाये .....

चौधरी बंसी लालः आबियाना भी साथ ही रिवाइज कर दें क्या ? (हंसी)

चौधरी मनफूल सिंह : यह तो पहले ही बहुत ज्यादा है। मेरी तो दरख्वास्त यह है कि इन नहरी रूल्ज का अमै।ड करके यह जो बडा भारी नुक्स है इसे दूर किया जाये। जहां नहरी पानी नहीं है खास तौर पर झज्जर रिवाड़ी और महेन्द्रगढ के रेतीले

इलाकों में वहां पर नहरी पानी दिया जाये। इसमें एक मांग एक लाख रूपये की विधान सभा लाइब्रेरी के बारे में हैं। यह ठीक है कि लाइब्रेरी बहुत अच्छी होनी चाहिये और अगर एक लाख की बजाये दो लाख भी दे दिया जाये तो कोई एतराज नहीं

चौधरी बंसी लालः अगले साल दो लाख भी दे देंगे।

चौधरी मनफूल सिंह : मेरे कहने का मतलब यह है कि हरियाणा और पंजाब की इकटठी लाइब्रेरी थी लेकिन रीआर्गेनाइजेशन के बाद हमें एक एक किताब भी वहां से नहीं मिली और सारी की सारी पंजाब वाले हडप कर गए हैं जो लाखों की रूपये की हैं। हमने कई बार लिखा लेकिन कोई नहीं सुनता। मैं अर्ज करता हूं कि अगर वहां के स्पीकर साहिब को लिखने का फायदा नहीं होता और वहां पंजाब के चीफ मिनिस्टर साहब को लिखने को कोई फायदा नहीं होता तो फिर गवर्नमैंट आफ इंडिया को लिखा जाये और हमारा जो हिस्सा बनता है वह लिया जाये। एक मांग यहां 5 लाख 54 हजार की इलैक्शन्ज के बारे में है। ठीक है अलैक्शन्ज पर खर्चा होता है लेकिन मैं यह बात कहना चाहता हूं कि देखा गया है कि चण्डीगढ़ से सारा स्टाफ करनाल से लेकर महेन्द्रगढ, गुड़गांव, हिसार वगैरा तक गया और आप देखें इस तरह करने से कितना टी0ए0 और डी0ए0 देना पडा। मेरा ख्याल है कि यह बेहतर हो अगर रोहतक का स्टाफ गुडगांव चला जोय और गुडगांव का करनाल चला जाए और सब जिलों में ऐसा किया जाये तो कितना रूपया टी0ए0, डी0ए0 का बच सकता

है जो कि चण्डीगढ से इतनी दूर स्टाफ ले जाने के लिये देना पडता है। जहां प्रदेश के बैकवर्ड इलाकों की तरक्की के लिए नहरों, सडकों, बिजली, टयूबवैल्ज वगैरा की जरूरत है वहां दस्तकाचरी की भी तरक्की की बहुत जरूरत है। जब तक झज्जर, रिवाडी, और महेन्द्रगढ़ जैसे बैकवर्ड इलाकों में दस्तकारी नहीं लगाई जायेगी तब तक वहां लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा और उनकी तरक्की नहीं होगी। उन इलाकों में न कोई दस्तकारी है और न कोई बडा कारखाना है और न कोई वहां कारखानेदार कारखाना लगाने जाता है। इसकी वजह शायद यह है कि उनको वहां सारी सुविधायें नहीं दी जाती हैं या कोई और वजह भी हो सकती है। वे कहते हैं कि वहां पानी अच्छा नहीं है और दूसरी सारी फैसिलिटीज जो कारखाने लगाने के लिए होनी चाहियें वे नहीं हैं। वहां देखना चाहिये कि कौन सी चीज की दिक्कत है और उसे दूर करना चाहिये और फिर कारखानेदारों को मजबूर करना चाहिये कि वे वहां जाकर कारखाने लगायें ताकि वहां लोगों को रोजगार मिल सके और प्रांत भी तरक्की करें। वहां जमीन तो काफी सस्ती मिल सकती है बाकी फैसिलिटीज सरकार को देनी चाहिये और उनको वहां पर कारखाने लगाने के लिये इन्क्रेज करना चाहिये। इस वक्त बेरोजगारी का मसला बहुत बडा है और कई मैंबर साहेबान ने कहा है कि बेरोजागरी सारे देश में ही है और हरियाणा में भी है। इसके लिये हमारी सैंट्रल सरकार ने कई करोड रूपये स्टेटस को अलांट करने का प्रावधान किया है और अपनी सरकार की कर रही है लैकिन मैं अर्ज करना चाहता हूं कि

इससे यह मसला हल नहीं होगा जब तक कि लोगों को टैक्नीकल एजुकेशन नहीं दी जायेगी और जब तक हर आदमी सैल्फ सफीशैंट नहीं होगा। यह जो बी0ए0 ओर एम0एज0 बनाये जा रहे हैं इनसे बेरोजगारी दूर नहीं होगी बल्कि और बढेगी और कम्यूनिजम ही पैदा होगां मेरे कहने का मतलब यह है कि जब तक टैक्नीकल एजुकेशन का फैलाव नहीं किया जाता और इस एजुकेशन के सिस्टम को चैंज नहीं किया जाता तब तक यह बेकारी का मसला हल नहीं हो सकता। कांस्टीच्यूशन में इक्वैल्टी आफ अप्रर्चुनिटी प्रोवाइड की हुई है लेकिन हमारे यह हो रहे है कि अमीर लोगों के बच्चे पब्लिक स्कूलों में पढकर आई0ए0एस0 और ऐच0सी0एस0 बनते हैं और जो बच्चे देहात के खसता हाल स्कूलों में पढते हैं वह उनका मुकाबला नहीं कर सकते और वह पीछे रह जाते हैं। यह एक बहुत अहम मसला है कि जिसकी तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए। या तो यह हो कि कांस्टीच्यूशन के लिहाज से पब्लिक स्कूल ही न हो ताकि सब एक जैसी तालीम हासिल कर सकें। इन पब्लिक स्कूलों में तालीम प्राप्त करे अमीरों के लडकें तमाम अच्छी सर्विसिज ले जाते हैं। आज मैट्रिक तक हिन्दी भाषा रह गई है इससे ऊपर अंग्रेजी ही चलती हे। जितने भी प्राईवेट कंसर्न्ज या इस्सटीच्यूशंज हैं, बम्बई, कलकता और दिल्ली वगैरा बडे बडे शहरों के अंदर जितने भी कारखाने हैं वहां सारा काम अंग्रेजी में होता है। जिनती भी प्राईवेट फर्म्ज हैं, बिजनैसं कंसर्न्ज या इन्स्टीच्यूशन हैं वे उन बच्चों को सर्विसिज में लेते हैं जो बहुत अच्छी इंगलिश लिख पड सकते हैं। अगर

प्राईवेट कंसर्न्ज अंग्रेजी में कामकाज न करें तो मसला हल हो सकता है। अंग्रेजी हमारे बच्चे जानते नहीं, टैक्नीकल ऐजुकेशन हमारे पास है नहीं तो बेरोजगारी का मसला दूर करने के लिए खास तजवीज निकालनी चाहिए।

चेयरमैन साहब, चौधरी रिजक राम जी चले गये, उन्होंने लीडर आफ दी अपोजीशन के बारे में कहा था कि कोई मीटिंग नहीं हुई, कोई बात नहीं हुई तो लीडर आफ दी अपोजीशन को कैसे लीडर रिकोगनाईज कर लिया ? मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि हमारी मीटिंग्ज हो चुकी हैं, अपोजीशन के लीडर भी हैं और सारी कार्रवाई ठीक है। चौधरी रिजक राम जी इस लिए कह रहे हैं।

चौधरी बंसी लालः इसलिए कह रहे हैं कि वे खुद लीडर आफ दी अपोजीशन नहीं रहे। बने भी कभी नहीं थे। रहते तब अगर बने होते ..... (व्यवधान)। रहता वो है जो कभी बना हो।

चौधरी मनफूल सिंहः चेयरमैन साहब, उनके साथ यह हुआ जैसे किसी की सगाई कर दी। बारात लेकर चला जाए, मोड बांध ले, फेरों पर चला जाए लेकिन फेरे न हों! ..... (हंसी)। उनके ज्यादा घाव हो रहा है, ज्यादा ही दुख हो रहा है। (हंसी) वे चाहे डिमांडज पर बोलते हों, चाहे बजट पर बोलते हों, किसी भी टौपिक पर बोलते हों, लीडर आफ दी अपोजीशन के अल्फाज

जरूर आएंगे। उनको ज्यादा दुख हो रहा है। तो चेयरमैन साहब, जितनी डिमांडज हाउस में पेश हुई हैं हम उनको समर्थन करते हैं, पुरजोर स्पोर्ट करते हैं कि इनको पास किया जाए।

पंडित चिरंजी लाल शर्माः इसका जवाब लीडर आफ दी अपोजीशन अपने शब्दों में दे तो ठीक रहेगा। (हंसी)

चौधरी हरद्वारी लालः मैं दूंगा।

चौधरी बंसी लालः चेयरमैन साहब, एक चीज मैं सदन के नोटिस में लाना चाहता हूं। स्पीकर साहब ने अनाऊंस किया था कि 5 बजे गिलोटिन लगा दें। मेरे ख्याल में बाकी बिजनैस कल ट्रांजैक्ट कर लेंगे और आज डिमांडज पर ही डिस्कशन कर लेते हैं। मेरे ख्याल में ऐसा करने में हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर सदन ऐसा करना चाहे तो हमें कोई इतराज नहीं है।

श्री सभापतिः अगर सारा हाउस इस बता पर मुत्तफिक है तो ठीक है .....

चौधरी बंसी लालः किसी को इतराज नहीं, इसी पर बहस कर लेते हैं। बाहर जाएंगे तो गर्मी लगेगी, यहां एयरकंडीशन में बैठे हुए हैं।

श्री सभापतिः ठीक है, आज इसी आइटम पर डिस्कशन चलेगी।

चौधरी मेहर चन्द (बडोपल): मोहतरिम साहिबे सदर, मैं संक्षेप रूप में बोलूंगा, ज्यादा लम्बे चौड़े भाषणों में विश्वास नहीं रखता। मेरी दास्तां एक दुःख भरी दास्तां है। लेकिन इसके साथ ही साथ एक बात जरूर कहूंगा। मैं गवर्नमैंट को दाद देता हूं उनके अच्छे कामों के लिए। इसमें कोई शक नहीं कि हरियाणा गवर्नमैंट ने जो तरक्की के काम किए हैं, मेरे ख्याल में उनकी मिसाल आजाद हिन्दुस्तान में तो क्या, दूसरे मुल्कों में भी शायद ही कहीं मिलती हो। मैं दूसरे मुल्कों में गया तो नहीं लेकिन पढने से मुझे मालूम देता है कि ऐसी मिसाल दुनियां में कहीं कहीं मिलती है, हर जगह नहीं मिल सकती कि किस तेजी से हरियाणा में तरक्की हुई है। लेकिन इसके साथ ही साथ मैं यह कहे बगैर नहीं रह सकता कि जहां गवर्नमैंट का काम तरक्की करना है वहां तरक्की के कामों में जो नुक्स रह गए हैं उनको रिमूव करना भी है। मैंने जो दुख भरी दास्तां की बात कही है अब मैं उसकी तरफ आता हूं। मेरे मुअजिज दोस्त पंडित चिरंजी लाल जी ने इंजीनियर्ज की बडी तारीफ की है, मैं उनके साथ सहमत हूं। लेकिन मैं यह कहे बगैर नहीं रह सकता कि किसान तबका महकमा नहर के मुलाजिमों के खासा तंग है। क्या कभी सरकार ने सोचा है कि किसान की दौलत कहां गई ? मोहतरिम चेयरमैन साहब, सरकार से क्या पूछते हैं कि किसानों की दौलत कहां गई कुछ तो वुकला खा गये कुछ ब्यूरोक्रैसी ले गई। यह बात ठीक है, इसमें दो राय नहीं हो सकती। जो कुछ मैंने कहा है इसके साथ ही साथ आपकी मारफत हरियाणा सरकार से अर्ज करूंगा कि

महकमा नहर के जो कानून बने हुए हैं वे बाबा आदम के जमाने के बने हुए हैं। हर के आमद इमारते नौसाख्त यानी हर कर्मचारी चाहे छोटे लेवल का हो, चाहे बडे लेवल का हो, अपनी मनमानी करता है। पावर की कंन्सेन्ट्रेशन हद से ज्यादा हें रिश्वत का बाजार हरदम गर्म रहता है। अगर एक्स0ई0एन0 और एम0सी0एन0 एक कमाश के हों तो खुदा ही हाफिज, हरियाणा सरकार तो क्या हाई कोर्ट के दरवाजे भी बंद हो जाते हैं। एस0सी0 के डीसीजन के बाद कोई गुंजाईश नहीं रहती। इसलिए मैं निहायत अदब से सरकार से दुरखास्त करूंगा कि कैनाल एक्ट और रूल्ज में तरमीम होनी चाहिए। उनको इस ढंग से बनाया जाए ताकि अंधा धुंध रिश्वत न चले। इस तरमीम को लाने के लिए मैं हरियाणा सरकार से निहायत अदब से दुरखास्त करूंगा कि इस काम को करने के लिए एक कमेटी मुकर्रर की जाए जो यह देखे कि जो रूल्ज बाबा आदम के जमाने के बने हुए हैं उनको गुडबाई कहा जाए। मैं यह बात रिस्पौंसिबिलिटी के साथ कहता हूं कि कैनाल ऐक्ट के अंदर डैमोक्रेसी की झलक तक नहीं है। इसलिए हरियाणा सरकार से मोअदबाना अर्ज करूंगा और खास तौर से चीफ मिनिस्टर साहब से दुदख्वास्त करूंगा क्योंकि चीफ मिनिस्टर साहब इसका कुछ न कुछ इालज कर सकते हैं लेकिन मुझे इसका इलाज नजर नहीं आता। मुझे कैबिनेट की मारफत भी कोई इलाज नजर नहीं आता। मुझे सिर्फ यही नजर आता है कि अगर चीफ मिनिस्टर साहब इलाज करने के लिए तैयार हो जाएं तो इलाज हो जाएगा वरना नहीं हो सकता। अगर चीफ मिनिस्टर साहब, किसान को ओवर सियर,

जिलेदार, वर्क मिस्तरी पंसाल नवीस पटवारी और ड्राफटस मैने के पंजे से निजात दिलाएं तो यह सबाब का काम होगा। बाकी मैं इस बात को महसूस करता हूं, जैसे मैंन पहले अर्ज किया कि महकमा नहर के अफसरान बहुत अच्छा काम करते हैं। पानी की कमी रफता रफता दूर होती जा रही है, लेकिन इसके साथ ही साथ एक गिला है कि किसान की बात सुनी नही जाती। आफिसर्ज समझते हैं कि जो कुछ उन्होंने कह दिया पत्थर पर लकीर है, उसको परमात्मा भी चेंज नहीं कर सकता, दुनियां की कोई तातक चेंज नहीं कर सकती। अफसरान का नजरिया थोडा सा दुरूस्त होना चाहिए, ठंडा होना चाहिए और किसान की बात सुननी चाहिए। किसान जमीन की रग को ज्यादा जानता है। मैं इंजीनियर्ज साहिबान से मोअदबाना अर्ल करूंगा कि मैं किसी पर असपर्शन कास्ट नहीं कर रहा हूं। लेकिन मैं एक बात कहे बगैर नहीं रह सकता किसान तो दूर रहा वह बात यह है कि अगर इलैक्टड रिप्रेजेंटेटिव्ज जो किसान की बात अफसरान तक पहुंचाना चाहते हैं, उनको भी खातर में नहीं लाया जाता। कम से कम रिप्रेजेंटेटिव्ज की बात तो सुनी जानी चाहिए। वह बातें बताना चाहता हूं लेकिन आफिसर फाईल से नजर तक नहीं उठाता हैं और उसकी बात सुनता ही नहीं। वह एक लाख जनता का रिप्रेजेंटेटिव है, उसकी बातों में वजन होता है और उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। मुझे यह बात बडी अखरती है।

ए आलीजाहो कुछ तो दुआएं ले लो नातवानों की

गम के मारों की बेबस बेसहारों की नीमजानों की।

कम से कम और नहीं करते तो आपके दिल में यह अहसास तो होना ही चाहिए। (विघ्न)। मेरे कहने का तरीका कुछ अजीब है। इसमें यह महसूस तो होगा कि मैं क्रिटिसिज्म कर रहा हूं। परन्तु .....

चौधरी राम लाल वधवाः पोसवाल साहब, यह कौन से चौक पर तकरीर हो रही है ? उस दिन तो आप फरमा रहे थे ..

श्री के0एल0 पोसवालः यह असैम्बली में हो रही है। (शोर)

श्री सभापतिः आर्डर प्लीज, आर्डर।

चौधरी मेहर चन्दः चेयरमैन साहब, मैं अपोजीशन के साथियों को यह बता देना चाहता हूं कि मेहर चन्द हर अच्छ काम के लिए गवर्नमैंट को दाद देगा लेकिन मेहर चन्द इस बैंच पर बैठे हुए भी जहां गवर्नमैंट के अंदर नुक्सा होंगे उनके बारे में बड़े अदब से यह कहेगा कि उस नुक्स को रफा करना चाहिए। मैं अन नसैसरी क्रिटिससिज्म में बिलीव नहीं करता। बिजली बोर्ड पर जब बहस होगी उस वक्त मैं बतालाऊंगा कि जो अन नसैसरी क्रिटिसिज्म किया जा रहा है उसका क्या हशर है। ..... (विघ्न)

अब मैं कुछ सजैशंज पेश कर रहा हूं। चेयरमैन साहब, एक सजैशन तो यह है कि वाटर कोर्सिज और माइनर्ज को पक्का

बनाना चाहिए। सबसे पहले यह काम रेतीले इलाकों में शुरू किया जाए। मेरा हल्का बड़ौपल ऐसा है जिसका बहुत सा हिस्सा रेतीला है। इस वास्ते वहां सबसे पहले वाटर कोर्सिज और माइनर्ज को पक्का किया जाए।

दूसरी बात मैं यह कहूंगा कि सिंचाई के साधन बढाने चाहिएं। यह काम सडकों के काम से कहीं जरूरी हैं नई माइनर्ज बनाये जाएं और मौजूदा माइनर्ज की ऐक्सटैंशन की जाए। हर महकमें के साथ एम0एल0एज0 की एक कंसल्टेटिव कमेटी होनी चाहिए। यह नहीं कि वहां जो चाहे कागजी कार्यवाही होती रहे और हम देखते रहें मायूसी के साथ बेबसों की तरह।

इसके इलावा मैं एक बात और कहूंगा तो मेरी यह बात अखरेगी। जिन जिन दफतरों में मैं जाता हूं, ज्यों ज्यों फील्ड वर्क देखता हूं, मैं तजुर्बे की बिना पर मुख्य मंत्री जी से कहूंगा कि स्टाफ कहीं जरूरत से ज्यादा है। चौधरी रिजक राम जी तो जिनका मैं बहुत कदर दां हूं, किस्से कहानियां ले बैठते हैं। एक बात का उन्होंने नेम बना रखा है कि हमने गवर्नमैंट को क्रिटिसाइज करना है। उनको वह नेम छोड देना चाहिए। गवर्नमैंट को ठीक ढंग से कंस्ट्रक्टिव वे में क्रिटिसाइज किया जाए। मैं यह कहूंगा कि इकोनौमी कमेटी गवर्नमैंअ को फोरन सैट अप कर देनी चाहिए।

चेयरमैन साहब, एक बात मैं और कहूंगा जो एफ0डी0 के मुताल्लिक है। ये सप्लीमेंट्री ऐस्टिमेटस जो इस हाउस के सामने पेश हैं इनके अंदर मैं देखता हैं रैफरैंस दे रखा है कि " Please see page of the Budget 1972-73" मेरे ख्याल में एफ0डी0 एक बात भूल गई कि बहुत से मैम्बरान यहां ऐसे आए हैं जिन्होंने 72–73 का बजट जब पास हुआ था उसमें भाग नहीं लिया था। मेहरबानी करके उन मैंबरान को बजट की कापी सप्लाई की जाए। आज के दिन मैं एफ0डी0 मुताल्लिक ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं परन्तु इतना जरूर कहूंगा कि एफ0डी0 की वर्किंग ठीक नहीं है। मैं अपने ख्यालात का इजहार जिस वक्त फिर मौका मिलेगा उस वक्त करूंगा कि एफ0डी0 का असल फंक्शन कया है और आजकल एफ0डी0 कर क्या रहा है। चेयरमैन साहब, अब मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि मैं समझता हूं कि और साथियों ने भी बोलना है। आखिर में, मैं एक कपलैट कह कर अपनी जगह लेता हूं –

आज के आलम का हर तरजे शहाना बदल गया, तू भी बदल ऐ फलक कि जमाना बदल गया।

श्री अमर सिंह (बवानी खेड़ा–एस0सी0): चेयरमैन साहब, बजट सैशन के बाद सप्लीमेंटरी ऐस्टिमैटस की रस्म है और यह रस्मी सप्लीमैंटरी ऐस्टिमैटस हमेशा बजट सैशन के बाद पेश हुआ करते हैं (इस समय उपाध्यक्षा पदासीन हुई) इसमें कोई दो राय नहीं, डिप्टी स्पीकर साहिबा, कि सप्लीमैंट्री ऐस्टिमैटस में बहुत सारी डिमांडज के जरिए, जो वाजिब खर्च हुआ है उसकी मांग की

गई है। इसमें एक डिमांड "कैपिटल आउट ले आन मल्टीपरपज रिवर स्कीमज", 7 करोड 61 लाख रूपये की है और इसमें यह लिखा है कि–

"The additional expenditure of Rs. 7.91 crores is required to bring the budget provision of Rs. 5.30 crores for the current year on par with that approved by the Government of India, and the Planning Commission for the Beas Project i.e. 13.21 crores for 1972-73."

मैं डिप्टी स्पीकर साहिबा, आपके जरिए इस हाउस से यह दरख्वास्त करूंगा कि स्टेट के अंदर छोटे छोटे माइनर्ज की ऐक्सटैंशन के लिए, आउटलैटस के लिए और एडिशनल छोटे छोटे माइनर्ज बनाने के लिए सरकार का यह जवाब होता है कि पैसा नहीं है। जब फाईनैंशल क्राइसिज भी हों, जब सारे काम प्रैक्टिकली बंद हैं और 30 जून से जो भी कर्मचारी काम कर रहे थे वे डिसबैंड हो गए हैं तो ऐसी हालत में इस किस्म की डिमांड को पास करना मैं नामुनासिब समझता हूं। मैं यह समझता हूं कि इस डिमांड की बाबत सैंट्रल गवर्नमैंट को इस हाउस के जरिए अप्रोच किया जाए कि जब स्टैंडर्ड के अंदर फाइनैंशल क्राइसिज है और सारे विकास के काम डिसबैंड हो गए हैं और ब्यास प्रौजैक्ट जिसका एक कतरा पानी हरियाणा को अभी तक नहीं मिला तथा वह स्कीम भी शायद 75–76 तक कंप्लीट होगी उससे पहले हम इंट्रैस्ट भी और उसका प्रिंसिपल भी अदा करने की बात यदि पास करें तो मैं यह नामुनासिब समझता हूं क्योंकि मुझे याद है कि

पिछले दिनों भगाना माईनर के ऊपर 13 लाख रूपया खर्च होना था उस 13 लाख रूपये से 10 हजार एकड के लिए पानी आना था और तकरीबन 15 गांवों को लाभ होना था लेकिन वह स्कीम महज इसलिए बंद कर दी गई, महज इसलिए इरीगेशन डिपार्टमैंट ने ऐप्रूव नहीं की कि अगर 13 लाख रूपये किसान भाई देने के लिए तैयार हों तो हम इस माईनर को बनाने के लिए तैयार हैं नहीं तो इस माईनर की एक्सटैंशन करने के लिए डिपार्टमैंट तैयार नहीं है। तो इसी सिलसिले में आपके जरिए डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं इस सदन से यह दरख्वास्त करूंगा कि यह ब्यास प्रोजैक्ट वाली डिमांड नं0 43 इस समय पास नहीं होनी चाहिए क्योंकि जब हमें, हरियाणा को इससे अभी लाभ हो नही होना है तो इसे पास करने से क्या फायदा ? हमें चार पांच साल के बाद लाभ क्या होगा, कहां तक होगा किसी को पता नहीं। तो ऐसी स्कीम की बाबत अभी से यदि हम इंस्टालमैंट देनी शुरू कर दें तो मैं यह नामुनासिब समझता हूं और इसको घक्का समझता हूं हरियाणा की इकौनोमी पर। इसलिए एक बार फिर मैं आपके जरिए इस हाउस से यह दरख्वास्त करूंगा कि पुरजोर लफ्जों में हमें गवर्नमैंअ आफ इंडिया को ऐप्रोच करन चाहिए कि हम इस समय इस पेसे को देने की हालत में नहीं हैं। इस पैसे को हमें जो छोटे छोटे माईनर्ज की ऐक्सटैंशन होनी है और जो आउटलैटस छोटे हैं उनको बडा करना है उन स्कीम्ज के ऊपर खर्च करना चाहिए। आउट लैटस के बारे में मैं बताऊंगा कि हमारे साथ क्या धक्का होता है। (विघ्न) इससे अनाज की पैदावार में बढौतरी होगीं तो मैं समझता हूं कि

सरकार को इस काम के लिए तरजीज देनी चाहिए क्योंकि इससे जहां पैदावार बढने की बात है, ऐग्रीकल्चर प्रोडक्शन की बात है, वहां इससे हम भावों को भी नौर्मल कर सकते हैं। आज डिप्टी स्पीकर साहिबा, भाव तो ज्योमैट्रिकली बढ रह हैं लेकिन पैदावार मैथेमैटिकली बढ रही हैं। इनको चैक तभी किया जा सकता है जब हमारी ऐग्रीकल्चरल प्रोडक्शन ज्यादा बढ़े। इसके साथ साथ मैं यह अर्ज करूंगा कि जहां देश के अंदर इन इम्पलायमैंअ और सोशल इन जस्टिस, ये दोनों चीजें हों तो देश के लिए बडी भारी प्रोब्लम है। ये दोनों चीजें देश की जडों को खोखला करती जा रही हैं। पिछले 25 सालों में सरकार ने इन दो प्रोबल्मज को हल करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उइाये हैं। अगर उठाये हैं तो अधूरे हैं। आज देश की आथ्रिक हालत दिन प्रति दिन बदतर होती जा रही हैं हमारी पालियामैंट के आंकडें बताते हैं कि हमारे देश के अंदर अढाई करोड लोग ऐसे हैं जिनको केवल एक टाईम पर रोटी मिलती है, दूसरे टाईम पर रोटी ही नहीं मिलती है। साढे तीन करोड ऐसे हैं जो बडे हाइली क्वालीफाइड हैं, डाक्टर हैं, इंजीनियर्ज हैं, उनको भी आज नौकरियां नहीं मिल रही हैं। 22 करोड लोग हमारे देश में ऐसे हैं जिनकी 20 रूपये महीने से भी कम आमदनी है। अब आप अन्दाजा लगायें कि 25 साल के अंदर जिस देश की आर्थिक हालत ऐसी हो वह देश कैसे तरक्की कर सकता है। जब तक किसी भी देश की आर्थिक हालत अच्छी नहीं होगी तब तक उस देश को तरककी वाला देश या तरक्की पसन्द देश नहीं कहा जा सकता। डिप्टी स्पीकर साहिबा, हमारे देश के

अंदर आज एक और दस का अंतर नहीं, न एक और पचास का ही है और न एक और सौ का अन्तर है बल्कि जमीन और असामान का अन्तर है। जब इतनी ज्यादा डिस्पैरेटी हो तो गरीबी कैसे हट कसती है, समाजवाद कैसे आ सकता है। इस अन्तर को मिटाने के लिए बहुत कडी कुर्बानी देनी होगी। जिस तरह आजादी हासिल करने के लिए लोग फांसी के तख्ते पर झूले, तहरीकें चलीं, उन कुर्बानियों और तहरीकों के बाद हिन्दुस्तार आजाद हुआ। उसी प्रकार से इस फर्क को मिटाने के लिए हमें तहरीक चलानी पडेगी। आज जिस किसी के हाथ में पावर है वह अमीर होता जा रहा है। जिसके पास एक कार हे वह यही चाहता है कि दूसरी कार हो जाये, जिसके पास दो हैं वह यह चाहता है तीसरी और हो जाये, जिसके पास एक कोठी है वह चाहता है कि दूसरी कोठी बन जाये। यह कोई एकोनोमी वाली बात नहीं है और न ही समाज की आर्थिक हालत को सुधारने वाली ही बात है। इसलिये इन चीजों को मिटाने के लिए हमें कुर्बानी देनी ही पडेगी।

उपाध्यक्षाः आप डिमांड पर ही बोलिये। It is not a general discussion. Please speak on the Damand.

श्री अमर सिंहः डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं अन इम्पलायमैंट और सोशल इन जस्टिस के बारे में बोल रहा हूं जो कि बहुत ही जरूरी डिमांड है और बहुत ही अहम मसला है। डिप्टी स्पीकर साहिबा, हमारे हरियाणा में रोडज बनाने का जो क्रैश प्रोग्रांम शुरू हुआ था उसके अंदर अढाई तीन लाख मजदूर

काम करते थे। उन मजदूरों को दूसरे देशों में जो मजदूरी मिलती हैं उससे बहुत कम मिलती थी। हिन्दुस्तान में ही यह प्रथा नजर आती है कि जो आदमी इनती मेहनत से काम करता हो और उसकी मजदूरी इतनी कम हो ? मैं दुनिया के दूसरे देशों में तो नहीं गया लेकिन जो लोग गये हैं वे बताते हैं कि दूसरे देशों में एग्रीकल्चर लेबरर्ज को मिटटी का काम करने वाले को सबसे ज्यादा तनखाह मिलती है परन्तु हमारे देशमें एक अजीब कहानी है, जो आदमी मिटटी का काम करते हैं, सडक बनाने का काम करते हैं, उनको इतनी कम मजदूरी मिलती है कि उनको गुजारा भी नहीं होता हैै। हमारे देश में ऐसी मजदूरी करने वाली औरत को अढाई रूपये औरा साढे तीन रूपये आदमी को मिलते हैं। जो एग्रीकल्चर लेबर हैं उसको पांच या साढ पांच रूपये ध्याडी के मिलते हैं। मैं तो इस सरकार का शुक्रगुजार हूं कि सरकार ने क्रैश प्रोग्राम तो चलता था। अब जून के बाद जब से यह सडकों का क्रेश प्रोग्राम बंद हुआ है तब से बेचारे मजदूर परेशान और बेकार बैठे हैं। जो मजदूर वहां पर काम करते थे उनको पैसा अभी तक भी नहीं मिला है। एस0डी0ओ0 एक्स–ई0इन0 ने तो अपना खाता पूरा कर लिया। जिसके पास एक मोटर साईकिल थी, उसने अगर दूसरी खरीदनी थी तो वह खरीद ली परन्तु मजदूों की जो ध्याडी थी वह यों की यों बकाया पडी हुई है। डिप्टी स्पीकर साहिबा, आप यह सुनकर हैरान होंगी कि उन मजदूरों का उन्होंने अपने रजिस्टरों में अंगूठा लगवाया और उनको कह दिया कि हम आपको पैसा निकलवाव कर भिजवा देंगे। बहुत सारी जगहों पर ऐसे मामले हुए

हैं। अगर सरकार को इस बारे में कोई सबूत चाहिए तो मैं सबूत पेश कर सकता हूं। आज ऐसे मजदूर हैं जिनको दो दो और तीन तीन महीने की मजदूरी नहीं मिली लेकिन रजिस्टरों में उनका अंगूठा लगवाया हुआ है। इसलिए मैं सरकार से बडे अदब के साथ गुजारिश करूंगा कि जिन मजदूरों को इतनी कम ध्याडी मिलती है और समय पर नहीं मिलती है तो वे यह महसूस करते हैं कि हम किस किस्म के शासन में रह रहे हैं। उन मजदूरों की पिछली मजदूरी का एक पैसा भी नहीं मिला और कोई सुनने वाला भी नहीं हैं वे एस0डी0ओ0 के पास जाते हैं, एक्स ई0एन0 के पास जाते हैं लेकिन कोई सुनन वाला नहीं है। जब एस0ई0 के पास जाते हैं तो कहा जाता है कि हमने चैक भेज दिया है लेकिन स्टेट बैंक से डिस ओनर होकरा आ गया। यह हालत हरियाणा सरकार में हो रही है।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि गरीबी तभी हटेगी, समाजवाद तभी आयेगा जब हम कुर्बानी करेंगे। कुर्बानी के बगैर समाजवाद नहीं आ सकता। आज देश के अंदर गरीबी का मसला हल होना चाहिए। सोशल जस्टिस मिलना चाहिए, एम्पलायमैंट मिलनी चाहिए। हमारे देश में दो तरह की अन एम्पलायमैंअ हैं। एक तो वे लोग हैं जो देहातों में रहते हैं। और अनपढ हैं, दूसरा वह तबका है जो एजूकेटिड हैं। देहातों में ज्यादातर अनपढ तबका ही रहता है। देहातों में 90 फीसदी लोग

सिर्फ तीन महीने साल में काम करते हैं और नौ महीने बेरोजगार रहते हैं। उन्हें रोजगार के कोई साधन नहीं दिये जाते।

अभी कई दिनों से गरीबी हटाओं का नारा लगाया जा रहा है। यहां कहा जा रहा है कि लैंड सीलिंग का बिल आ रहा है। यह पता नहीं आयेगा या नहीं लेकिन मैं उस सिलसिले में अर्ज करना चाहता हूं कि यहां अर्थ व्यवस्था, आर्थिक हालत को सुधारने के लिए सिर्फ जमीन पर ही सीलिंग नहीं चाहिए बल्कि जो हमारी छोटी छोटी इंडस्ट्रीज हैं, छोटी छोटी दस्तकारी हैं वे गांव में लगानी चाहिएं और उनमें काम मिलना चाहिए। 25 साल के अंदर देश की कोई आर्थिक हालत नहीं सुधरी। आज देहातों में जो लोग हैं वे सिर्फ जमीन पर ही बोझा न बने बल्कि अपनी आर्थिक हालत को सुधारने के लिए छोटी छोटी दस्तकारियां शुरू करें। हमारी सरकार इस ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही हैं। इसलिए मैं सदन में यह सुझाव दूंगा कि अगर देहातों से अना एम्पलायमैंट को दूर करना है तो लाजमी तौर पर छोटी छोटी दस्तकारियां शुरू करनी पडेंगी। जब तक देहातों में छोटी छोटी दस्तकारियां नहीं शुरू करेंगें तब तक हमारी आर्थिक हालत नहीं सुधर सकती है। फिर मैं यही निवेदन करूंगा कि स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज चालू की जायें और अर्थ व्यवस्था सुधारने का कोइ रास्ता निकाला जाये।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, एक डिमांड लैंड रैविन्यू की बात है। उसके बारे में मैं अर्ज करना चाहता हूं कि जमींदारों के लिए एक पास बुक बनायी गई है जिसमें सारी एंटरी की जाएगी। परन्तु

इन पटवारियों को चैक करने वाली कोई भी ताकत धरती पर नहीं है। अगर गौड ही इस धरती पर जन्म ले ले और उनकी ताकत को चैलेंज कर दे तो दूसरी बात है परन्तु हिन्दुस्तान में कोई ताकत नहीं जो पटवारी की ताकत को चैलेंज कर सकें और चैक कर सें। पटवारी की इतनी पावर है मुझे पता है क्योंकि मैं वकालत भी करता हूं। एब बार हमारे यहां फाइनैंशल कमिश्नर चले गये मैंने उनसे एक सवाल किया कि इस पटवारी को चैक करने के लिए आपके पास कोइ रास्ता है, उन्होंने कहा कि हम पटवारी की चैक नहीं कर सकते। इसलिये इस सिलसिले में एक सुझाव देना चाहता हूं कि अगर पटवारी को चैक करना है तो एक ही रास्ता है जिस तरह से थाने में एफ0आई0आर0 दर्ज कराते हैं और एफ0आई0आर0 की नकल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट और एस0पी0 के पास 24 घंटे के अंदर चली जाती है। इसी प्रकार से जो पटवारी गिरदावरी करता है, उसकी एक कापी एस0डी0एम0 साहब के पास चली जानी चाहिए।

तब तो मैं समझता हूं कि चैक हो सकता है। अदरवाईज उस पर कोई भी चैक नहीं है। वह किसी भी रिकार्ड में फेर बदल कर सकता है। पटवारी को इस बारे में पूरे अख्तियारात हैं। अनपढ सरपंच है, वह उसकी भी हाजिरी दिखा देता है और नम्बरदार की भी हाजिरी दिखा देता है। अगर उसको बंधा हुआ नोट मिल जाये तो काम हो जाता है वरना नहीं। छोटा नोट भी नहीं, बंधा हुआ बडा नोट ताकि गिनने में भी तकलीफ न हो।

अभी मेरे लायक दोस्त चौधरी मेहर चन्द जी ने भी इस बारे में कुछ बताया। वह कांग्रेस के मैंबर हैं और इस बारे में बहुत जानकारी रखते हैं।

5.00 P.M.

चौधरी मेहर चन्दः मैं अपोजीशन का नहीं बन सकता, कांग्रेस का ही हूं।

श्री अमर सिंहः उन्होंने बड़े दिमाग से कहा कि रिश्वत का बाजार गर्म है। अगर मैं यह बात कहता तो हमारी सरकार यह समझती है कि मैं for the sake of criticism बात कर रहा हूं ऐसा मेरे फाजिल दोस्त हुक्मरान समझ लेते। लेकिन आज हुक्मरान टोले का एक आदमी अपने दिल की बात कहता है और ठीक कहता है कि रैवेन्यू डिपार्टमैंट के अंदर अंधेरगर्दी हैं आज से 10 साल पहले लोग यह कहा करते थे कि सिर्फ थानों में ही रिश्वत ली जाती है यानि सिर्फ थानों में ही रिश्वत से काम होता है लेकिन आज मैं यह कहे वगैर नहीं रह सकता कि कहीं कोई काम श्वित के बगैर नहीं होता। सारे डिपार्टमैंट में यह हाल है कि मेज पर पांव रख कर बैठा हुआ अफसर सरेआम कहता है कि यह काम तो मैं तब करूंगा, जब मुझे पैसा मिलेगा। हम उसे कुछ कहते हैं तो वह कहता है कि ऊपर वाले भी तो खाते हैं। डिप्टी स्पीकर साहिबा, मेरा यह सुझाव है अगर मेरे यह आनरेबल हुकमरान साथी इस बात को उचित समझें कि पअवारी की पावर्ज को चैक करने के लिये, जिस तरह से एफ0आई0आर0 की कापी, अगर क्रिमिनट

केस है तो जुडिशियल मेजिस्ट्रेट को जाती है, वरना एस0पी0 के पास जाती है, उसी तरह से अगर गिरदावरी की नकल विद इन सैवन डेज एस0डी0एम0 के पास चली जाया करे तो फिर कोई फेरबदल नहीं कर सकता।

पंडित चिरंजी लाल शर्माः जमाबंदी और गिरदावारी की कापी तो पटवारी भेजता है।

श्री अमर सिंहः परन्तु वह एस0डी0एम0 को तो नहीं भेजता!

इसके अलावा आबियाने की बात है। आबियाने की बाबत मेरे फाजिल दोस्त चौधरी मेहर चन्द ने बतलाया कि तीन चार अफसर/कर्मचारी ऐसे हैं जो अपनी मनमानी करते हैं। इस बारे में मेरा एक सुझाव है। अगर सरकार की इरीगेशन डिपार्टमैंट से करप्शन दूर करने की मंशा है तो आबपाशी का एक मियार तय करें। जैसे गेहूं में 5 पानी की जरूरत होती है। जिस गेहूं की फसल को 5 पानी मिल जायें, उससे नहर का पूरा आबियाना ले लें। इसके बाद अगर दो पानी मिलते हैं तो 2/5 , 3 पानी मिलते हैं तो 3/5 और यदि 4 पानी मिलते हैं तो 4/5 आबियाना वसूल किया जाये। इस तरह से इसको तकसीम करें और डिवीजन और सब डिवीजन में एस0डी0ओज0 की रिस्पौंसिबिल्टी फिक्स करें कि जिस एस0डी0ओ0 के सब डिवीजन में कम आबियाना आयेगा, उसेा डिमोट किया जायेगा और जिस सब डिविीजन में ज्यादा आबियाना

वसूल होगा, उसको एक स्पैशल इंक्रीमैंट दी जायेगी। यह एक तरीका है जिससे हम इरीगेशन डिपार्टमैंट की करप्शन को दूर कर सकते हैं। नहरों को कटवाते हैं मोड़ते हैं, उखड़वाते हैं, मैट, ओवरसियर या जिलेदार और तावान की शक्ल में देता है किसान। चूहे की वजह से नहर घुरलू हो जाती है।

पंडित चिरंजी लाल शर्माः नहर क्या हो जाती है ?

श्री अमर सिंहः नहर घुरलू हो जाती है और उसको भुगतता है किसान। इस तरह से किसान को यह सब दिक्कतें बरदाश्त करनी पडती है। मेरा यह कहना है कि सरकार अगर मेरे सुझाव को, जो मैंने दिया है, एग्जामिन करे ओर यदि पौसीबल हो, तो लागू करे, तो यह सबसे आसान तरीका है जिससे हम इरीगेशन डिपार्टमैंट की करप्शन को चैक कर सकते हैं और करप्शन को इस डिपार्टमैंट से दूर कर सकते हैं। Otherwise it is very dificult to chek corruption in the Irrigation Department.

डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं एक स्पैसिफिक बात का जिक्र करना चाहता हूं। हिसार मेजर राजस्थल से हांसी तक है। यह एक पुख्ता नहर बनी है। वहां पर लाईन वाटर कोर्स बना है। यह नहर जैसी भी बनी है, यह तो आने वाला वक्त बतायेगा कि उसमें सीमेंट की कितनी मात्रा लगी है और कितनी नहीं लगी है लेकिन मुझे इस बात को कहते हुए बडा दुःख होात है कि वहां पर सीमेंट के एक एक कटटे के पांच पांच रूपये इकटठे किये गये हैं। लेकिन हम किसको कहें, क्योंकि इस बात की इंक्वायरी करना एक

सवाल है। इसलिये हम चुप बैठे हैं। वह वक्त आयेगा जब यह चीज खुद ही नुमाया हो जायेगी कि किस तरह से यह नहर बनी हैं

पंडित चिरंजी लाल शर्माः क्यों यह मनाते हो कि पाट जाये .।

श्री अमर सिंहः हम तो यह कहते हैं कि अगर ठीक चल जाये तो अच्छी बात है। लेकिन इसमें मेरा एक और खास प्वायंट है। मैं आज उसे सरकार के नोटस में लाना चाहता हूँ। चौधरी सरूप सिंह जी भी हिसार से, इस हाउस के मैम्बर हैं और उनकी कांस्टीच्यूंसी में भी इस नहर का पानी लगता है। यह नहर राजस्थल से हिसार के एण्ड तक जाती है। पुख्ता बनने के बादे अब को तो मुझे पता नहीं लेकिन पहले हम आउटलैटस में पानी निकलता देखते थे। आज हालांकि शहरों मैं पानी की मिकदार बढी है लेकिन मोघों से पानी नहीं निकलतां जब हम इरीगेशन अथारिटीज से पूदते हैं, एस0डी0ओ0 से या एक्स0ई0एन0 से तो यह कहते हैं कि अभी तो नहीं, एक दो साल के बाद जब ब्यास प्रौजैक्ट बन जायेगा और हमें ज्यादा पानी मिलेगा तब देखना कितना पानी इन मोघों को मिलेगा। जब हमने उनसे यह कहा कि वे लोग तब तक क्या करेंगे जो पहले पांच किल्ले बोते थे और पांच पांच पानी लेते थे और अब एक किल्ला भी नहीं बो सकते, तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। पिछले दिनों हमने आउटलैटस के बारे में एक्स0ई0एन0 के नोटिस में यह बात लायी

कि साहब! आप किसी 10 आउटलैटस को एग्जामिन कर लो। आप उनमें यह देखो कि कितना पानी निकलता हैं हम तो उनमें यह देख पाये हैं कि रेती पर रास्ता बनता चला जाच रहा हैं उनमें बहुत थोडा थोडा पानी निकलता है। हम देखते हैं कि नहर तो पानी से भरी हुई आती है लेकिन किसानों के मोघों के अंदर पानी नहीं निकलता। डिप्टी स्पीकर साहिबा, मेरी दरख्वास्त यह है, कि इस बात को ये एग्जामिन करायें। अगर इसी तरह से किसान को गला काट कर उसको मारना है और एग्रीकल्चर प्रोडक्षन का दावा करना है कि आपकी प्रोडक्शन बढेगी तो मेरा ख्याल यह है कि प्रोडक्शन बढने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। उसी नहर से छोटे छोटे माईनर निकलते हैं, हमारे एग्रीकल्चरव मिनिस्टर साहब, यहां बैठे हुए हैं .....

चौधरी भजन लालः किसानों के ठेकेदार तो आप ही बन बैठे हो, जैसे और कोई है ही नहीं ..... (व्यवधान) सारी गलत बातें तो आपने कह दही कि 5–5 रूपये में भी कटटा बिका है।

श्री अमर सिंहः इसका तो आप जवाब दे दें। मेरा कहने का हक है।

चौधरी भजन लालः मैंने कहा कि आप ने कहें लेकिन रीजनेबल तो कहें।

चौधरी फूल चन्द (रोहट): आन ए प्वायंट आप आडर, मैडम! ये कहते हैं कि ठेकेदार हैं, लेकिन ठेका है किसके पास ? ..... (व्यवधान व शोर)

श्री अमर सिंह: अगर चौधरी साहब के पास एग्रीकल्चर और इरीगेशन डिपार्टमैंट साइमल्टेनीयसली होता, तो उनको यह बात कहने का मौका नहीं मिलता। चूंकि यह प्वायंट कहने का है, इसलिए मैं कहे बगैर नहीं रह सकता। अगर पानी होगा तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढेगी और अगर पानी पानी नहीं होगा तो नहीं बढेगी। इसलिए मेरी गुजारिश यह है कि जहां तक पानी का मसला है, इसको बहुत गम्भीरता से देखना चाहिए क्योंकि हमारी 82 प्रतिशत पापुलेशन हमारे देहातों के अंदर रहती है और देहात के जिन लोगों की आपने गरीबी हटानी है, जिनको हरिजन कहिए, पिछडे हुए कहिए या बैकवर्ड कहिए, उन लोगों को दारोमदार जमीन पर है। हम उनको हैल्दी एम्पलाइमैंट नहीं दे पाए हैं। इसलिए एग्रीकल्चर डिपार्टमैंट और इरीगेशन डिपार्टमैंअ को बहुत बेहतरीन बनाकर चलाना पडेगा।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, बुटाना माइनर एक्सटेंश्ज्ञन जिसमें कि उमरा से लेकर चीफ मिनिस्टर के आठ दस गांव आते हैं और आठ दस गांव मेरी कांस्टीच्यूंसी बवानी खेडा के हैं, वह स्कीम अंडर एग्जामिनेशन है। पिछले साल महज यह कह कर इंकार कर दिया था कि क्योंकि यह 13 लाख की स्की है इसलिए बुटाना स्कीम की एक्सटैंशन नहीं करते। अगर 13 लाख किसान

देने के लिए तैयार हों तो इसका सारा इंतजाम कर सकते हैं। मेरी सरकार से गुजारिश है कि अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढानी है और जबकि आपके पास उपजाऊ भूमि है, पानी आपके पास है तो मैं समझता हूं कि यह जो पानी देने की स्कीम्ज हैं इनको आप बनाएं। (घंटी) डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं तो दो मिनट और लूंगा। मैं यह अर्ज कर रहा था कि जहां तकक डिमांडज ताल्लुक है डिमांडज का मैं कोई विरोधी नहीं हूं। डिमांडज आती हैं और हाउस मे ंवे पास भी हो जाती हैं। मैं तो इन पर जो खर्च करने का मुद्दा है उस पर अधिक जोर देना चाहता हूं। कितना अच्छा होता कि अगर 34 लाख रूपया जो हरिजनों के लिए पिछले साल लैप्स हो गया वह भी इन डिमांडज में आत जाता। 17–18 लाख हरिजनों की आबादी है उनको ऊंचा उठाने के लिए सरकार को कोशिश करनी चाहिए। डिवैल्पमैंट मिनिस्टर ने बताया कि पूरा पैसा पिछले साल खर्च नहीं कर पाए थे और अब वह पैसा अगले साल खर्च होगा लेकिन जयादा अच्छा होता कि वह सप्लीमैंटरी डिमांडज में ले आते। डिप्टी स्पीकर साहिबा, क

उपाध्यक्षा: आपका समय हो गया है। अब आप बैठ जाएं।

(इस समय भी अध्यक्ष पदासीन हुए)

श्री राम सरन चन्द मित्तल (नारनौल): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं डिमान्डज नम्बर 43 और 38 पर अपने कुछ विचार

सदन के सामने रखना चाहता हूं। अभी इस साल वर्षा काफी अर्से तक नहीं हुई थी खासकर बारानी इलाके में और इस वजह से उन इलाके के अंदर बडा खतरा पेदा हो गया था और ऐसा लगने लगा था कि अब पूरा अकाल पडेगा। वर्षा हो गई, इससे वह बात तो नहीं हुई जिसका कि डर था लेकिन हर साल बगैर वर्षा के लोगों को बडा भारी संकट रहता है कि अगर भगवान की कृपा नहीं हुई तो अकाल का मुंह देखना पड़ेगा। इस संकट को दूर करने के लिए सरकार का सिंचाई का प्रबंध करना अत्यंत आवश्यक कर्त्तव्य है और मुझे इस सप्लीमैंटरी डिमांडज में एक बात बहुत पसंद आई। गवर्नमैंट ने सात आठ करोड रूपया इन डिमांडज में ब्यास प्रोजैक्ट के लिए निकाला है। इससे काम तो नहीं चलेगा और स्पए की की जरूरत पडेगी। मुझे यह बताया गया है कि सरकार द्वारा महेन्द्रगढ डिस्ट्रिक्ट और रिवाडी, गुडगांवा के इलाकों में जवाहर लाल नेहरू नाम की नहर जारी की जाएगी जिसमें ब्यास प्रोजैक्ट का पानी आएबीा और वह पैरेनियल कैनाल होगी। इस बात के लिए मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूं। यह काम थोडा लेट जरूर है लेकिन फिर भी बहुत अधिक लेट नहीं है। असल में हरियाणा में कोई ऐसी रिवर नहीं है जो पानी की सप्लाई जारी रख सके। पानी किसी भी जगह की इकानोकिम प्रासपैरिटी के लिए बहुत जरूरी है और हमारी गवर्नमै।ट इसके लिए मुस्तअद है। हमारे यहां जमीन की क्वालिटी अच्छी है और हमारे यहां के लोग बडी मेहनत करते हैं, किसान लोग बडी मेहनत से काम करते हैं इससे पैदावार और अच्छी हो सकती है सिर्फ सिंचाई की कमी है।

पहले भी मेंने कई दफाच इस बात की मांग की है कि अगर नहर नहीं आ सकती हो तो डीप बोरिंग के लिए रिग आएं, ड्रिलिंग मशीनें मंगवाई जाएं ताकि काम पूरा हो। लेकिन वह तो होता रहेगा यह जो कैनाल का सिटम शुरू होने वाला है यह काफी फायदेमंद साबित होगा और मैं समझता हूं। कि सरकार जल्दी से जल्दी जवाहर लाल नेरूरी कैनाल जिसे बावल प्रोजैक्ट भी कहते हैं, पूरा करेगी। कैनाल के इंजीनियरों के पास मैंने नक्शे देखे हैं। मैं समझता हूं कि कुछ पहाडी इलाकों को छोड कर इस नहर का पानी तमाम जगह जाएगा।

स्पीकर साहब, नहरों के साथ साथ एक सवाल था अन एम्पाइमैंट का अन एम्पालइमैंट बहुत ज्यादा है इससे कोई इन्कार नहीं कर सकता। अभी हमारे एक माननीय सदस्य जो राई से आते हैं यह तो नहीं कहा जा सकता कि वे लीडर आफ दी अपोजीशन हैं (व्यवधान) वह इस जगह बैठे जरूर थे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्षः मित्तल साहब, आप जारी रखें।

श्री राम सरन मित्तलः अन एम्पलाएमैंट का सवाल आज हर जगह है यह नहीं कि यह सवाल सिर्फ भारत मैं है बल्कि जो एडवांसड कंट्रीज हैं, काफी डिवैल्प हो चुके हैं वहां पर भी अन एम्पलाइमैंट का सवाल पैदा हो गया है। अमेरिका जैसा कंट्री जो कि सबसे रिचैस्ट कंट्री है वहां अन एम्पलाइमैंट को डौल्ज दिया जाता है। यह ठीक है कि हमारे याहं अन एम्लाइमैंट के लिए

सरकार को क्रिटिसाइज किया जाता है। लेकिन अगर अन एम्लाइमैंट के सवाल को साइंटिफिकली एग्जामिन किया जाए तो हमें पता लगता है कि गवर्नमैंट का इसमें कोई दोष नहीं है। गवर्नमैंट चाहती है कि जो हमारे यहां अन एम्लाइमैंट है वह खत्म हो। लेकिन जो हालात हैं उसमें सरकार का कसून नहीं है। हमारे यहां तीन तरह की अनएम्लायमैंट है– एक अनपढ लोगों की, दूसरे पढे लिखे लोगौं की और तीसरी जो टेक्शनियंज हैं, इंजीनियर हैं या टैक्नोलोजी के एक्सपार्ट हैं उनकी अन एम्पालएमैंट। जहां तक अनपढ लोगों की अन एम्लाइमैंट का ताल्लुक है यह एक्जेजरेटिड है। हमारे यहां पिछली दफा सडकों के बनाने का प्रोग्राम चला और उसके लिए लेकर की जरूरत पडी। हमने देखा कि हमारे यहां राजस्थान से लोग काम करने के लिए आए, दक्षिण तक से लोग हमारे यहांए आए। हरियाणा में लेबर नहीं मिली। इससे साफ पता लगता है कि हमारे यहां अनपढ लोगों की अन एम्लाइमैंट का जो शोर है वह एक्जेजरेटि है। पढे लिखे लोगों में अन एम्लाईमैंट जरूर है। अध्यक्ष महोदय, हमारे देश में हर साल इतने लडके मैट्रिक, बी0ए0, एम0ए0 पास करते हैं और मैं कह सकता हूं कि उनकी तादाद लाखों में होती है क्या गवर्नमैंट उन सबको सर्विस दे सकती है। कोई भी गवर्नमैंट हो, कांग्रेस की गवर्नमैंट हो, अपोजीशन की हो या कोई और गवर्नमैंट हो इतने पढे लिखे लोगों को हर साल सर्विस नहीं दी जा सकती। और प्राइवेट सर्विस भी इतनी आसानी से नहीं मिलती। कुछ तो हमारी पापूलेशन बढी है, कुछ हमारी एजुकेशन बढी है, और सबसे बडी

बात यह है कि जो हमारे पढे लिखे लडके निकले हैं वे अपने हाथ से काम नहीं करेंगे। घर पर बिल्केल बेकार बैठे रहेंगे। वे सोचते है। कि गवर्नमैंट का कर्मचारी कुर्सी मेज पर सफेद पोश बन कर बैठा रहता है फिर वे भी तो इतने ही पढे लिखे हैं वे छोटा काम क्यों करें, मेहनत का काम क्यों करें। यह जो भयंकर रूप दे देगी। हमारे यहां से बहुत से विद्यार्थी पढने के लिए अमेरिका जाते हैं। अमेरिका में हमारें यहां से खर्चा होता है। कई लोग ऐसे भी गए हैं जिनके पेरेन्टस, गारजियन्ज की इतनी आमदनी नहीं होती कि वे उनको खर्चा भेज सकें। मैंने देखा है सुना भी है और लोगौं से बातैं भी की हैं कि लोग बाहर के देशों के अंदर होटलों के अंदर पार्ट टाइम काम करते हैं, बर्तन साफ करते हैं और साथ साथ पढते भी हैं। इससे जो पैसा कमाते हैं, उसी से अपना गुजारा भी करते हैं। ऐसा करने से उन्हें किसी भी प्रकार का संकोच नहीं है। मैरा कहने का मतलब यह है कि हाथ से काम करने को वहां पर कोई बुरा नहीं समझता पर हमारे यहां हाथ से काम करने वाले को अच्छा नहीं समझा जाता, कितनी बुरी बात हैं। स्पीकर साहब, आप एक कारपेन्टर को ही ले लीजिए। वह दस पन्द्रह रूपए रोज कमाता है और कमा भी सकता है। चाहे वह गांवों में है, चाहे वह शहरों में है। मैं आपको बतलाता हूं, अजमेर में मैंने लोको वर्कशाप में एक फोर्मैन को देखा, वह चार सौ, पाच सौ रूपये तनख्वाह लेता है और वह बिल्कुल अनपढ है। उसके साथ एक बाबू क्लर्क लगा हुआ है वह ग्रेजुएट है और वह बिल्कुल अनपढ फोरमन के अधीन काम करता है। फोरमैन उसका अफसर है।

कारण यह है कि वह इंजीनियरिंग वर्क में माहिर है, हाथ का का काम जानता है, हाथ का काम करने पर उसे कोई संकोच नहीं है उसके कपडे आप को मैले मिलेंगे क्योंकि वह हथ से काम करता है और ग्रेजुएट बाबू के कपड़ आपको बडे साफ सुथरे मिलेंगे क्योंकि वह हाथ से काम करना बुरा समझता हैं यहां मैनटैलिटी को चेलेंज करते हैं, फिर गवर्नमैंट को हर तरह का दोष समझता है। यहां मैनटैलिटी को चेलेन्ज करते हैं, फिर गवर्नमैंट को हर तरह का दोष देते हैं इस तरह से टैक्नीकल आदमियों की तरफ हमें देखना चाहिए जो हाथ से काम करते हैं और ज्यादा पैसा कमाते हैं पर हमारे नौजवान गवर्नमैंट सर्विस के पीछे पडे हुए हैं कि हमें गवर्नमैंट सर्विस मिले या प्राइवेट फर्म के अंदर को नौकरी ही मिल जाए चाहे थोडे ही पैसोंपर काम करना पडे पर वे अपने हाथ का कोई काम करने के लिए तैयार नहीं है जिससे कि ज्यादा पैसे मिल सकते हैं। स्पीकर साहब, 1962 में जब मैं मंत्री था, उस समय मेरे पास लेबर डिपार्टमैंट था और इस सिलसिले में मैं बार कुल्लु के रास्ते जाते हुए मण्डी में रात के लिए ठहर गया। वहां का लेबर इन्सपैटटर मुझे मिलने के लिए आया मैंने उससे फैक्टरीज के बारे में कुछ पूछ ताछ की तो उसने मुझे कहा कि आप गन फैक्टरी ही देख लीजिए। वहां के एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट से उसने मुझे मिलाया जिसने वहां पर एक छोटी सी गन फैक्ट्री लगाई हुई थी। मैंने वहां पर रा मैटीरियल लेकर फिनिशड मैटीरियल तक सब कुछ देखा और फिर कैसे उस नौजवान ने राड को काट कर बोर किया, फिर सारा काम उसने मुझे समझाया, कैसे

उसने गन तैयार की। उस एक गन को बनाने पर उसके 125 रूप्ये खर्चा आता था और वह उस गन को 300 रूपये में बेचता था। मैंने उससे पूछा कि आप ने यह काम कहां से सीखा तो उसने कहा कि लाहौर के पास कसूर में कहीं कोई जगह का नाम बताया, कि उसने वहां इंजीनियरिंग कालेज से यह सब कुछ ट्रेनिंग हासिल की। उसने मुझे कहा कि उसे इस तरह के हाथ के काम करने का बडा शौक था और फिर गवर्नमैंट ने उसे इसको बनाने का लाईसैंस भी दे दिया। मुझे तो इन्सपैक्अर ने बताया कि कैसे उसने पहले लोहारों की तरह काम शुरू किया था और फिर कैसे इसको बढाया बल्कि हमारे यहां कोई नौजवान ऐसे और दूसरे तरीके के हाथ के कामों में इन्ट्रैस्ट नहीं लेते। वे तो सिर्फ इस ताक में बैठे रहते हैं कि उन्हें गवर्नमैंट सर्विस मिल जाए। हम मानते हैं की सभी को सर्विस देना गवर्नमैंट का काम है, फर्ज भी है, पर यहां पर हाथ से काम करके रोटी कमाना तो लोग अपनी तौहीन समझते हैं। स्विटजरलैंड में भी आप देख लीजिए कि वहां पर लोग हाथों का काम करने के कारण ही बडी फ्लशिंग कंडीशन में हैं। स्पीकर साहब, जापान में भी लोग हाथों से काम करने को बडी प्राथमिकता देते हैं, तभी वहां के लोगों की कंडीशन अच्छी है और जापान की उन्नति का कारण भी एम्पलायमैंट को दूर करने के लिए भी अभी तक हमारे जिले में कोइठ कदम नहीं उठाया गया। हमारा जिला जो है वह मिनरल्ज में बहुत रिच है, वहां पर कच्चा लोहा बहुत मिलता है, इस लिए और वहां पर कोई लोहें को प्लांट लगाया जाए तो एक तरफ महेन्द्रगढ के जिले की अन

एम्पलायमैंट काफी हद तक दूर हो सकती है और दूसरी तरफ हरियाणा में डिवैल्पमैंट के लिए उस प्लांट से काफी रूपया जा सकता है जिससे कि हमारे प्रान्त का भला हो सकता है। यह जो एग्रीकल्चर क लिए इरीगेशन की डिमांडज रखी है उनसे भी मैं सहमत हूं और मैं कहता हूं कि सैंटर से अधिक से अधिक मदद लेकर जवाहर लाल नेहरू कैनाल की जो स्कीम है उसको पूरा करके महेन्द्रगढ, झज्जर बगैरा के जिन इलाकों में पानी नहीं है वहां पर नहरों के जरिए पानी पहुंचाया जाए।

चौधरी शिव राम वर्मा (नीलोखेड़ी): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आज सप्लीमैंट्री डिमांडज के ऊपर जो बहुत चल रही है इस पर काफी चर्चा तो ही चुकी है लेकिन इसके अंदर मैंने कुछ मदें ऐसी देखी हैं जिनमें केवल 10 रूपए ही सरकार ने मांगे हैं। इससे मैं यह समझता हूं कि या तो खजाने में रूपया नहीं है और या सरकार को कोई काम करने की जरूरत नहीं है। महज रस्मी तौर पर 10 रूपये मांगने का मैं यह मतलब समझता हूं कि या तो सरकार ने इस बात की तरफ ध्यान नहीं दिय कि कौन कौन से काम करने हैं और अगर यह बात नहीं है तो दूसरा साफ मतलब निकलता है कि खजाने में पैसा नहीं है। अगर खजाने में रूपया नहीं है तो फिर यहां पर की हैं उनमें से कोई बात पूरी हो पाएगी। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप रस्मीं बातें छोड कर अपने प्रदेश की उन्नति की बातें गम्भीरता से सोंचे और उनके ऊपर अमल करें तभी हमारा प्रदेश आगे बढ सकता है वरना केवल

बातें करने से कोई तरक्की होने वाली नहीं है। मैं सदन का अधिक समय नहीं लूंगा, थोडी ही देर में अपनी बातें समाप्त करना चाहूंगा। आज सबसे बडा मसला जो वैसे तो सारे देश में ही है और हमारे प्रदेश में भी काफी गंभीर रूप धारण कर चुका है जिस पर काफी चर्चा हो चुकी है वह बेरोजगारी का मसला है। लोगौं को काम नहीं मिलता। लाखों लोग काम मांगते हैं। उन सबको नौकरियां देना मैं समझता हूं इतना आसान नहीं है। इस बात से कोई इंकार नहीं किया जा सकता कि सभी लोगों को नौकरियां नहीं दी जा सकतीं। यहां पर स्पीकर साहब, सदस्यों ने बडे लम्बे चौडे भाषण दिए कि लोगों को ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि केवल भाषण देने से उनको कोई लाभ नहीं पहुंचता जब तक कि उन कि उन नौजवानों को काम करने के लिए सुविधाएं न दी जाएं। आज जो पढे लिखे नौजवान हैं वे काम करना चाहते हैं लेकिन कमी इस बात की है कि उन्हें जो सुविधाएं चाहिएं वह नहीं मिल पातीं। आज एक ग्रेजुएट जब कालेज से निकलता है तो उसका जी करता है अपना कोई काम करने को लेकिन उसके पास साधन नहीं हैं। जब तक उसको साधन न दिए जाएं तब तक केवल उसे उपदेश देने से, ऐसा कारखाना लगाना चाहिए और फलां काम करना चाहिए, कोई फायदा नहीं। आज समस्या है उसको सुविधा देने की। यदि उसे सरमाए की जरूरत है या टैंक्नीकल सुविधा की जरूरत है तो उसे मिलनी चाहिए ताकि वह अपनी अक्ल और हिम्मत से कुछ आगे बढ सके और अपनी रोजी कमा सके। लेकिन अध्यक्ष महोदय ऐसी

कोई बात दिखाई नहीं देती। जब कोई रास्ता दिखाई नहीं देता तो नतीजा यह होता है कि कई नौजवान कुछ कोशिश करते हैं और जब किसी तरफ से कोई सुविधा मिलती दिखाई नहीं देती तो हार कर बैठ जाते हैं। स्पीकर साहब, आपने भी बहुत नौजवानों को जैसे सुविधाएं चाहिएं वह नहीं मिल पाती तो वे मायूस होकर नौकरी की तलाश में निकल पडते हैं इस समस्या को हल करने के लिए सरकार को गम्भीरता से विचार करना चाहिए। इस विषय पर मैं एक दो सुझाव देना चाहता हूं पहला यह है कि जब कोई नौजवान काम करना चाहे तो उसे जरूरी सुविधाएं दी जाएं। आपका जो ग्राम उद्योग विभाग है, स्माल स्केल इंडस्ट्रीज का विभाग है उन को अगर आप हिदायतें करें कि वे नौजवानों को काम करने के लिए सुविधाएं दें तो कम ठीक हो सकता हैं लेकिन हम देखते हैं कि यहां पर बडे कारखानेदारों को मदद देने की तरफ ज्यादा ध्यान दिया जाता है जैसे कि दिल्ली में कारें बनाने का एक कारखाना लगाया जा रहा है, ऐसे लोगों के लिए तो कराडों रूपए की और हर किस्म की सुविधाएं दी जाती हैं मगर जो लोग छोटे छोटे काम शुरू करना चाहते हैं उनको कोई सुविधा नहीं दी जाती। आप स्विटजरलैंड की मिसाल देखिए वहा पर बहुत अच्छी अच्छी किस्म की घड़ियां बनती हैं लेकिन वहां पर घड़ियां बनाने के बडे बडे कारखाने नहीं हैं। वहां पर घर घर में छोटे छोटे वर्कशाप हैं। किसी में कोई पुर्जा बनता है और किसी में कोई और बाद में उसको एक जगह पर असैंबल करके घडियां बनती हैं। इसी प्रकार लाखों की तादाद में घर घर छोटे छोटे

कारखाने हैं और सब को रोजगार मिला हुआ है। कई देशों में जहां पर ट्रैक्टर बनते हैं वहां पर भी कई जगहों पर अलहदा अलहदा किस्म के पुर्जे बनाए जाते हैं और फिर उनको असैंबल करके ट्रैक्टर बना कर मार्किट में भेजा जाता हैं **(इस समय सभापतियों की सूची में से एक सदस्य चौधरी मनफूल सिंह पदासीन हुए)** तो इस तरह सबको काम मिलता है और वह काम एक ही जगह न रह कर सारे देश में फैलता है। इससे न सिर्फ लोगों को घर के पास काम मिलता है वरन गवर्नमैंट के भी कई मसले हल हो जाते हैं। आप जानते हैं कि जब कारखाने एक ही जगह इकट्ठे हो जाते हैं तो उससे कई किस्म के मसले, लेबर प्रोबल्मज बगैरा पैदा हो जाते हैं रोज झगडे होते हैं और हडतालें होती हैं। लेकिन अगर उद्योग को घर घर में फैलाया जाएगा तो न कोई झगडा हेागा न हडतालें होंगी और न सरकार के लिए यह सरदर्दी पैदा होगी और लोगों को भी अपने घर के पास रहकर काम मिलेगा और न उनको शहरों में मकानों वगैरा की दिक्कत होगी। हडतालों से सब को नुकसान होता है, कारखानेदार को नुकसान होता है, लेबर को नुकसान होता है और अगर एक महीने के लिए कारखाना बंद हो जाए तो आप अंदाजा लगाएं देश को कितना माली नुकसान होता है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो लोग अपने गांव में घरों में इस तरह से उद्योग लगाना चाहते हैं और छोटे छोटे उद्योग लगा कर रोटी कमाना चाहते हैं उनको सरकार पूरी सुविधाएं दे और ऐसा न हो कि वे लोग दफ्तरों के चक्कर काटें जिस तरह कि आज कल हो ही रहा है।

हमारे प्रदेश में एक हरिजन कल्याण निगम बना है, उसे सरकार की तरफ से रूपया अलाट होता है हजारों दरखास्तें हरिजनों की तरफ से कर्ज के लिए आती हैं। हरिजनों के सामने कोई नौकरियां वगैरा मांगने की बात नहीं है और वह अपने घरों में छोटे छोटे उद्योग लगाकर रोटी कमाना चाहते हैं और इसके साथ देश की पैदावार बढा कर देश की सेवा भी हो सके लेकिन उनसे दफ्तरों के चक्कर कटवाए जाते हैं। हमारे विकास मंत्री हैं जिनके पास हरिजन कल्याण का काम भी है। उन्होंने यहां बताया था कि हरिजनों के लिए वर्ष 1970–71 में 38 लाख रूपया अलाट हुआ जिसमें से केवल 12/13 लाख रूपया ही बतौर ऋण बट सका और फिर वर्ष 1971–72 में 50 लाख रूपया अलाट हुआ तो केवल 23 लाख ही उनका बट सका। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या इस तरह से जिस तरह से आप चल रहे हैं कभी बेरोजगारी दूर हो सकती हैं ? नहीं हो सकती। जो लोग काम करन चाहते हैं अपने उद्योग लगाकर बेकारी का मसला दूर करना चाहते हैं उनके लिए रखा गया रूपया भी सरकार पूरी तरह से बांट न सके तो फिर आप किस मुंह से कहते हैं कि आप बेकारी और गरीबी दूर करना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि यह तो केवल नारेबाजी है और कुछ नहीं। आप देखें कि यह रूपया क्यों नहीं पूरा बट सका कहां पर कमी रह गइ और कौन इसके लिए जिम्मेदार हैं और जो जिम्मेवार हैं उसे सजा दें ताकि आयंदा ऐसा कोई न कर सके। अगर आप इस तरफ ध्यान नहीं देते तो इन फोकी सरमन्ज से लोगों का पेट भरने वाला नही ंहै गरीबी और बेकारी दूर होने वाली नहीं है।

अगर यह 50 लाख रूपया पूरा बट जाता तो कितने लोगों को काम मिलता कितनी प्रदेश की आमदनी बढती और कितने लोगों को जो बेकार फिरते हैं रोजगार मिलता वे लोग मुजरिम हैं जो उन गरीब आदमियों से दफ्तरों के चक्कर कटवाते हैं और उनको कर्जा न देकर पैसा न बांटकर उनके रोजगार में बाधा डालते हैं। ऐसा करने के लिए जो जिम्मेदार हैं और जिनकी लापरवाही की वजह से हरिजनों को दिक्कत पैदा होती है उनके खिलाफ एक्शन लेना जरूरी है। तो मेरा सुझाव है कि उद्योग धंधों को एक जगह न इकट्ठे करके इनको घर घर में चलाया जाए ताकि बेरोजगारी की समस्या भी हल हो और सरकार के लिए भी समस्यायें पैदा न हो .....

चौधरी मेहर चन्दः आन ए प्वायंट आफ क्लैरिफिकेशन ..... (विघ्न)..... हां मैं क्लैरिफिकेशन ही करना चाहता हूं। मेरे एक दोस्त ने एक बात फरमाई है जो कि बडी ही मिसलिडींग है और मैं उसे क्लीयर करना चाहता हूं। वर्मा साहब ने फरमाया कि हरियाणा सरकार का दिवाला निकल चुका है। इसीलिए 10 रूपए की मांग पेश की गई है। मैं उनसे कहूंगा कि वह मैंमोरैंडम को पढ कर देखें कि उसमें क्या लिखा है। उसमें लिखा है–

"The entire expenditure will be met from the savings. This is only a token demand."

चौधरी राम लाल वधवाः मुख्य मंत्री जी जब इनको मंत्री बना देंगें तो ुरि यह कलैरिफिकेशन दे सकेंगे अब नहीं दे सकते।

चौधरी शिव राम वर्मा: पता नहीं माननीय सदस्य को बीच में बोलते हुए टोक दिया था इसलिए बदला निकालने की कोशिश की है।

Ch. Mehar Chand: No, no. I am not revengeful.

चौधरी शिव राम वर्मा: जो बात उनहोंने कही हैं वह भी ठीक हैं और वह सुन ली हैं लेकिन मैंने जिस ढंग से बात की थी वह मैं समझात हूं गलत नहीं थी। (घंटी) मैं अभी खत्म करता हूं और जो बातें पहले आ चुकी हैं उनको मैं दोहराना नहीं चाहता और मैं सिफ दो तीन बातों की तरफ सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। यह ठीक है कि बिजली का काम बहुत हुआ लेकिन वह इतनी जल्दबाजी मूं, बिना किसी सोच समझ कें और बिना प्लैनिंग के हुआ कि उसमें काफी कमियां रह गई हैं और वे नुक्स निकालने में अब उतना ही रूपया लगेगा जितना बिजली के लगाने पर खर्च हुआ है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि चाहे कितना ही खर्च करना पडे वे नुक्स निकाले जाने चाहिएं। इसमें ट्रिपिंग होती है और जब भी यह शिकायत करते हं तो जवाब आता है कि जल्दीबाजी में काम हुआ है इसलिए नुक्स रह गया है। इसी तरह सडकें भी जल्दबाजी में बनी हैं। उनके ऊपर मिटटी अच्छी तरह से प्रैस नहीं हुई और दूसरा सारा मैटीरियल भी जल्दबाजी में काम हुआ है इसलिए नुक्स रह गया हे। इसी तरह सडकें भी जल्दबाजी में बनी हैं। उनके ऊपर मिटटी अच्छी तरह से प्रैस नहीं हुई और दूसरा सारा मैटीरियल भी जल्दबाजी में लगा है। कई सडकें तो

काबले मुरम्मत हो गई हैं। अगर उनकी मरुम्मत का काम हो जाए तो ठीक है नहीं तो और ज्यादा नुकसान होगा। इसके साथ ही मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच यमुना नदी पर थोडे थोडे फासले पर जितने ज्यादा से ज्यादा पुल डालकर इनको मिलाया जाएगा उतना ही अधिक लाभ हमारे प्रदेश को होगा क्योंकि उत्तर प्रदेश एक बहुत बडा प्रान्त है और वह अभी अपनी जरूरतें अपने तौर पूरी करने के योग्य नहीं हुआ हे। इसएिल हरियाणा के लिए वह एक मंडी साबित हो सकता है। इसके लिए हरियाणा में यमुना नदी पर अगर दो तीन पुल बना दिए जाएं तो ठीक होगा। इसमें लिखा है कि पलवल के नजदीक एक पुल बनेगा। इसी तरह से मैं चाहूंगा कि एक पुल पानीपत और यमुनानगर के बीचज करनाल के आसपास और एक पुल सोनीपत के आसपास बना दिया जाए तो उत्तर प्रदेश में आने जाने में बडी आसानी होगी। खर्च तो होगा लेकिन ऐसा खर्च बरदाश्त करना चाहिए क्योंकि इससे हमारे प्रदेश को बहुत फायदा होगा। इसके इलावा एक सुझाव और देना चाहता हूं और उसमें हमारी सरकार को ज्यादा खर्चा नहीं करना पडेगा और उसका ज्यादा बोझ केन्द्रीय सरकार पर पडेगा। आप जानते हैं कि जी0टी0 रोड हरियाणा के बीच से गई है। इसे कम से कम 50 फुट चौडा करके पक्का कर दिया जाए और उसके बीच में 6 फुट चौडी एक फुट ऊंची पटडी बना दी जाए ताकि आने का रास्ता अलग हो जाए और जाने का अलग हो जाए तो इससे प्रदेश को बहुत फायदा होगा। हमारे प्रदेश को ही नहीं होगा बाकी लोगों को भी होगा।

इससे जी0टी0 रोड पर ट्रैफिक तेज हागा, समय की बजत होगी और एक्सीडेंट का खतरा कम हो जाएगा। अब रोजाना आमने सामने से एक्सीडेंट होते हैं और लाखों रूपए का जानी औ माली नुक्सान होता है। रात का लाइट में कुछ दिखाई नहीं देता और फिर ट्रक तो सडके के बीचों बीच चलते हैं इसलिए आमने सामने से एक्सीडेंट होते हैं। अगर सडक चौडी हो जाएगी और बीच में 6 फुट चौडी पटडी हो जाएगी तों ट्रैफिक अपनी अपनी साइड पर चलेगा और एक्सीडेंट का खतरा नहीं रहेगा। वहां जमीन भी एक्वायर नहीं करनी पडेगी क्योंकि जितनी दोनों तरफ कच्ची पडडियां पडी हैं अगर उन्हें ही पक्का कर दिया जाए तो 50 फुट चौडी बन जाएगी। चूंकि यह नैशनल हाईवे है इसलिए इस पर जो खर्च होगा वह सैंट्रल सरकार को ही देना पडेगा और हमारे ऊपर यह बोझ नहीं पडेगा। मैं समझता हूं कि यह मेरी बहुत बडी मांग है और जरूरी है। इसलिए सभापति महोदय, आप के द्वारा इस ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि इस काम को जितनी जल्दी हो सके, पूरा करने की कोशिश करें। इस तरह सदन में शिक्षा के बारे में बात चली, सदस्यों ने थोडा थोडा जिक्र किया। जगह जगह पर काफी स्कूल अपग्रेड हो चुके हैं, लेकिन स्टाफ पूरा नहीं है। कई प्राईमारी स्कूल भी ऐसे हैं जिनमें कोई स्टाफ नहीं हैं। स्टाफ न होने से बच्चों की पढाई में काफी हानि पहुंच रही है। सभापति महोदय, मैं अभी एक मिनट में खत्म करता हूं स्कूलों के बारे में मैंने यह चलती बात कह दी है .....

चौधरी बंसी लालः सारी बातें चलती ही कहीं हैं, जिम्मेदारी की एक बात नहीं कही।

चौधरी शिव राम वर्माः मैंने जरूरी बातें कही हैं, इनकी तरफ सरकार पूरा पूरा ध्यान दे ताकि देश को जहां दूसरे लाभ पहुंचेंगे वहां आर्थिक उन्नति भी होगी और देश आगे बढेगा। इन शब्दों के साथ आपका धन्यवाद करता हूं।

बैठक के समय में वृद्धि

चौधरी बंसी लालः चेयरमैन साहब, मेरी प्रार्थना है कि या तो सिटिंग को थोडी देर के लिए बढा लिया जाए या मुझे बोलने दें। 6 बजने को आए हैं, मुझे भी जवाब देने में टाईम लेगगा।

श्री सभापतिः आधा घंटा बढा देते हैं। सिटिंग 7 बजे तक चलेगी।

अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान (पुनरारम्भ)

श्री उमेद सिंह (मेहम): चेयरमैन साहब, मैं डिमंड नंबर 50 के बारे मे जिक्र करयना चाहता हूं। कई मैम्बरान ने इस पर बोलते हुए काफी कुछ जिक्र किया है। वास्तव में यह हरियाणा के

अंदर एक अहम समस्या हे। माननीय चिरंजी लाल जी ने कहा है कि हरियाणा के अंदर वही समस्या है जो सारे देश की समस्या है। केवल इस बात को कहने से पीछा नहीं छूटता कि हमें नौजवानों को नौकरियां देने के लिए योजनाएं बनानी पडैंगी बल्कि योजनाओं को अमलीजामा पहनाना है, उनको कार्यरूप में लाना है। आज हरियाणा में जितने पढे लिखे नौजवान बेरोजगार हैं, उनको देख कर हमारा दिल दहलता है। इसके पीछे कमजोरी यह है कि हमारे नौजवनावों को बेकार की ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग और एम्पलायमैंट का आपस में कोई संबंध नहीं है। सरकार ने हजारों ओवरसीयर ट्रैंड किए हैं जबकि स्टैट में इतने ओवरसीयर्ज की जरूरत नहीं है। स्टेट में कई हजार अध्यापक ट्रैंड करके छोड दिए। जब अध्याप के लिए इंटरव्यू होता है तो उनको रिजैक्ट कर दिया जाता है जब इंटरव्ययू आता है तो जिन अध्यापकों को रखा जाता है उनसे एक एक हजार, दो दो हजार रूपया रिश्वत लेकर लगाया जाता हैं एक गरीब आदमी पहले पढाई पर खर्च करता है और बाद में नौकरी लगने के लिए दो दो साल की तनख्वाह पहले ही बोर्ड में दे देता है। इससे आप अंदाजा लगाएं कि आज देश की क्या हालत है। नौजवान कितनी देर तक इस चीज को सहन करेगा। इस समस्या पर यह हाउस और सरकार पूरी अहमीयत देकर विचार करे और नौजवानों के लिए कोई अच्छा रास्ता निकाले। मैं तो यहां तक कहूंगा कि जो नौजवान शिक्षा पा लेता है उसको रोजगार देना चाहिए और रोजगार लेना उसका मौलिक अधिकार है। उसे विश्वास दिलाया जाए कि पढने के बाद उसे

रोजगार जरूर मिलेगा। इसके इलावा गरी आदमी का जो बालक कम्पीटीशन में आता है उसके सामने सबसे बडी दिक्कत यह होती है कि वह गांव के स्कूल से पढा होता हैं गांवों में स्कूलों की हालत बहुत खराब है। स्कूलों में 50 फीसदी से ज्यादा स्टाफ नहीं है। लेकिर शहर के बच्चे देहाती बच्चों की निस्बत ज्यादा जानते हैं। उनके माता पिता दूसरे तरीकों से भी अपने बच्चों को पढा लेते हैं लेकिन गांव के बच्चों को दूसरी सुविधाएं नहीं हैं। इसलिए सबसे पहले स्कूलों में स्टाफ पूरा करना चाहिए। चीफ मिनिस्टर साहब से मेरी रिक्वैस्ट है कि स्कूलों में स्टाफ पूरा किया जाए।

इसके इलावा पानी की बडी भारी दिक्कत है। पानी के लिए सरकार आगमैंटेशन कैनाल बना रही है। ब्यास लिंक बना रही है, सतलुज लिंक बना रही है, सारी चीजें हैं लेकिन पुरानी कठिनाईयां जहां की तहां खडी हैं। बयास लिंक के बारे में हम अभी तक डिटर्मिन नहीं कर पाए हैं कि पानी का कितना शेयर हरियाणा को मिलेगा और पंजाब को कितना मिलेगा। यह चीज जल्दी तय कर लेनी चहिए क्योंकि अब भाखडा से जो पानी मिलता है उसको लेने के लिए काफी दिक्कत पेश आती है। भाखडा में जो स्टाफ काम करता है उसमें 40 परसैंट हिस्सा हरियाणा का है और 60 परसैंट पंजाब का है। मैं कल ही भाखडा गया था। मुझे ए0पी0आर0ओ0 ने बताया कि हरियाणा सरकार क्या कर रही है। हमने उससे पूछा था तो उसने बताया कि हरियाणा का शेयर 40 परसैंट है लेकिन 40 परसैंट शेयर भी एम्पलायमैंट में नहीं दिया

जाता। जब ये हमारे आदमी ही पूरे नहीं करते तो इलैक्ट्रिसिटी और पानी का शेयर लेने के लिए अभी तक हरियाणा गवर्नमैंट ने नहर तैयार नहीं की। आज पंजाब और हरियाणा में कांग्रेस की सरकारें हैं जल्दी जल्दी पांजब वालों से बातचीत करके लिंक कैनाल तैयार करनी चाहिए। इस पर कितना ही रूपया खर्च हो, इसको पूरा करना चाहिए क्योंकि यह बहुत अहमियत रखता हैं दूसरे काम जरा पीछे कर लें लेकिन पाचनी और बिजली जल्दी से जल्दी मुहैया करना चाहिए क्योंकि हरियाणा की इकानौमी पानी और बिजली पर आधारित है। हरियाणा के किसान के मन में तब तक खुशाहाली नहीं आ सकती, कोई डिवैल्पमैंट नहीं हो सकती जब तक ये चीजें मुहैया न की जाएं। सरकार ने डेरी डिवैल्पमैंट की स्कीम चल रखी है। जब तक पशुओं को चारा पूरा नहीं मिलेगा तक तक यह स्कीम पनप नहीं सकती। विकास के सब काम हो जाएंगे अगर नहर बना कर पानी पूरा दिया जाए। चेयरमैन साहब, चौधरी मेहर चन्द जी ने कहा था कि प्रांत मे ंब्यूरौक्रेसी है। यह वास्तव में ऐसा रोडा है जिसका हमें पता नहीं चल पाता कि इसको कैसे टैकल किया जाए। पटवाचरी, जिलेदार, गिरदावर, ओवरसीयर जितने ये छोटे कर्मचारी हैं ये सब रिश्वत खाते हैं। आफिसर लोग बडी मेहनत करते हैं परन्तु नीचे का जो स्टाफ है वह वास्तव में हरियाणा के लिए खतरा हें सकरार को उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही करनी चाहिए। मिसाल के तौर पर, मेरे गांव के आस पास दो माईनर इरीगेशन स्कीमें लगती है। वहां पर एक्स0ई0एन0 का दौरा हो चुका है। एस0ई0 साहब भी दौरा

कर चुके ळं लेकिन कोई सुधार नहीं हो रहा है। आजकल बरसात के दिनों में भी दो इंच पानी चलता है। इस चीज की तहकीकात की जाए। किसान को इस बात का पता नहीं चलता कि क्यों पानी नहीं आता। जब चीफ इंजीनियर भी दौरा कर आया है, सीनियर आफिसर्ज भी दौरा कर आए हैं तो पानी क्यों नहीं आता। किसानों का पानी कौन पूरा करेगा ? सरकार डिवैल्पमैंट के कामों पर पैसा खर्च करती है, सारे हिन्दुस्तान में रिकार्ड कायम कर दिया है लेनि महकमें के नीचे के कर्मचारी किस तरह तकलीफें पैदा करते हैं इसके बारे में सरकार को सख्त कदम उठाने चाहिएं। अंत में इतना ही कह कर मैं बैठ जाता हूं।

श्री के0एन0 गुलाटी(फरीदाबाद): मोहतरित चेयरमैन साहब, सदन के सामने सप्लीमैंअरी डिमांडज पेश हैं इन पर कई सदस्यों ने अपनै अपने जजबात का इजहार किया। मैं भी अपने विचार सदन के सामने रखना चाहता हूं। सबसे पहले मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे जजबात की तरजमानी चौधरी मेहर चन्द ने कर दी है, लेकिन फिर भी चार पांच मिनट लूंगा। पिछले पांच साल से हरियाणा फाइनैंशियल क्राइसिज में है। इरीगेशन डिपाट्रमैंट में लोगों को जून से तनख्वाह नहीं मिली है और सारी जनता में असंतोष फैला हुइा है। इस घाटे को मद्देनजर रखते हुए, सरकार सै कहना चाहता हूं कि वह अपने आमदनी और खर्च करने के जराये को बदले। मैं एक ही मिसाल आमदनी और खर्च की आप के सामने पेश करूंगा। अगर इसका प्रबंध न किया तो

फाइनैंशियल क्राइसिज आती ही रहेंगी। जहां तक आमदनी का ताल्लुक है, हमारे टैक्शेसन डिपार्टमैंट से एक भी टैक्स सही वसूल नहीं होता। टैक्स वसूली न होने का क्या कारण है ?

6.00 बजे।

कारण यह है कि हामरे लेबर आफिसर, सेल्ज टैक्स आफिसर, सिविल सप्लाई आफिसर के थरू ज्यादा से ज्यादा उठता है अगर एक हजार रूपया डुनेशन ली जाती है तो उस साल में पांच हजार रूपए की टैक्स में छूट देनी पडती है। अगर सरकार यह कदम उठा ले कि किसी अफसर के जरिए डुनेशन या स्माल सेविंग्ज फंड इकट्ठा नहीं करना है और उस पर सख्ती करे कि सही टैक्स इकट्ठा करो तो मैं दावा करता हूं कि पचास गुणा टैक्स और वसूल होगा तथा आमदनी के अंदर इजाफा होगा। इसी तरह चेयरमैन साहब, रजिस्ट्रार, सब रजिस्ट्रार आदि कई किस्म के टैक्स, कही सी0एम0 टैक्स, कही रैड क्रास टैक्स, कहीं कोई टैक्स और कहीं कोई टैक्स और डुनेशंज आदि वसूल करते हैं। ... .

श्री सभापतिः आप कौन सी डिमांड पर बोल रहे हैं ?

श्री के0एन0 गुलाटीः मैं डिमांड नं0 39 मिसलेनियस पर बोल रहा हूं और जैसे सब लोगों ने अपने अपनें ख्यालात रखे वैसे ही मैं भी आमदनी में बढौतरी करने का सरकार को एक तरीका बता रहा हूं। आज सब रजिस्ट्रार 50 हजार की रजिस्ट्री 5

हजार में कर देता है। सरकार को इससे कितना रैवेन्यू का लौस होता है। अगर सही रजिस्ट्री कर दी जाए तो सरकार की आमदनी में पचास गुणा और सौ गुणा इजाफा हो सकता है। जहां तक खर्च का ताल्लुक है, इसके बारे में चेयरमैन साहब, निवेदन यह है कि कंट्रैक्टर सिस्टम फेल हो गया है। लोएस्ट कोटेशन ली जाती है सिजसे काम अच्छा नहीं होता। उससे ऐफिडैविट लिया जाता है कि स्पैसिफिकेशूज के मुताबिक पूरा काम करूंगा और पूरा मैटीरियल लगाऊंगा लेकिन बाद में आठ आने मैटीरियल गायब हो जाता हें जनता को और हजारों पी0डब्लयू0डी0 वर्क्स को सरकार काम के लिए कन्ट्रैक्टर्ज को फसर्ट क्लास ईंटे और सीमैंट नहीं मिलता लेकिन कोठी वालों को काले धन वालों को वे चीजें मिल जाती है।। इसलिए जो कमीशन बंधी होती है कुछ अफसरान के साथ 10 प्रतिशत से लेकर 20 प्रतिशत तक इसे खत्म कर दिया जाए। कंट्रैक्टर सिस्टम की बजाए सरकार अपनी एजैंसी के थ्रू सारे काम कराए। मुझे यकीन है कि ऐसा करने से करप्शन खत्म हो जाएगी। सरकार सीमेंट और ईंटैं जल्दी से जल्दी भट्ठे वालों से ले सकती है बजाए कंट्रैकटर के।

अब, चेयरमैन साहब, मैं अन एम्पलायमैंअ की तरफ आता हैं। बडा शोर मच रहा है अन एम्पलायमैंट का। अन एम्पलायमैंट के अंदर अगर दो तरीके और नहीं अपनाएंगे तो यह मसला हल नहीं हो सकता। वे तरीके ये हैं कि जिस घर के अंदर एक नौकरी है उसको दूसरी नौकरी न दी जाएं जिस कैंडीडैट के

घर में पहले नौकरी नहीं है, चाहे काबलियत कम हो, उसको नौकरी दी दी जाये। तब गरीबी हटेगी, तब अन एम्पलायमैंट हटेगी। यदि जिस घर में मियां बीबी पहले ही मुलाजिम हैं और किसी और को भी नौकरी दे दी जाए तो यह अन एम्पलायमैंट खत्म नहीं हो सकती, करप्शन खत्म नहीं हो सकती और गरीबी भी खत्म नहीं हो सकती।

चेयरमैन साहब, सरकार और हम सब चाहते हैं कि ब्लैक मार्किट खत्म हो, डिसकरेज हो, लेकिन एक चीज की तरफ सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। मुझे याद है कि फरीदाबाद में चार आने गज खरीदी हुई जमीन दो सौ रूपए गज बेची गई। जो भी सैक्टर कें अंदर 6 सौ रूपए गज के हिसाब से नीलामी हुई। यहां गरीबी कैसे हटेगी ? या तो जमींदारों ाके सही पमैंट की जाए या गरीब आदमियों को चीप रेटस पर पलैाट दिए जाएं। काले धन वालों वे न दिए जाएं। गरीब बादमी जिसकी आमदनी बहुत कम है उसको असान किशतें पर जमीन ऐक्सवायर करके दी जार। जिसकी जमीन ऐक्वायर होती है उसको सही पैसे दिए जाएं। तब हमारे देश के अंदर हमारे हरियाणा के अंदर गरीबी हटेगी और ब्लैक मार्किट खत्म होगी।

चेयरमैन साहब, फरीदाबाद हरियाणा का दिल है। मेरे हल्के में दो लाख की आबादी है क्योंकि वहां बहुत सारी फैक्टरीज हैं लेकिन वह दो लाख जनता बहुत ही दुःखी है। सबसे ज्यादा रैवन्यु वहां से आता है। मुझे खुशी है कि सरकार ने फरीदाबाद

को इम्पौरटैंस देकर वहां कार्पोरेशन के रूप में एक कंप्लैक्स बनाया है लेकिन दु:ख होता है कि वहां से ज्यादा से ज्यादा रैवन्यू आने के बाद भी 2 लाख जनता का ख्याल नहीं रखा जाता। वहा पानी की कमी है, मच्छरों की ज्यादती है, गंदगी की ज्यादती है और हरि किस्म की ज्यादती वहां हैं। (विघ्न) इसलिए मेरी सरकार से प्रार्थना है कि बाकी जगहों की तरह फरीदबाद का भी ख्याल रखा जाएं

इसके अलावा चेयरमैन साहब, एक दिल की बात और कहना चाहता हूं और लीडर आफ दी हाउस से रिक्वैस्ट करना चाहता हूं और सच्चे दिल से कहना चाहता हूं कि यह जो रोज की तू तू मैं मैं अपोजीशन के अंदर है यह खत्म कर दी जाए क्योंकि हो सकता है कि किसी वक्त दुखभरी घटना हो जाए। मैं रिक्वैस्ट करूंगा कि चीफ मिनिस्टर साहब सिक्रेट बैलेट से अपोजीशन के लीडर को चुन लिया जाए ताकि सरकार इंतजाम भी ठीक हो और सही अपोजीशन का लीडर भी चुना जाएं

अब मैं चेयरमैन साहब, ज्यादा समय नहीं लेता लेकिन चौधरी मेहर चन्द की तरह दो शर जरूर कहूंगा क्योंकि आन नैशनल करैकटर बहुत कम है, ला लैसनैस बहुत बढ गई है और कुरप्शन भी बहुत है। शेर इस प्रकार हैं :–

खुदी का कर बुलन्द इतना कि हर तदबीर से पहले,

खुदा बन्दे से खुद पूछे कि तेरी रजा क्या है ?

मिटा दे अपनी हस्ती को गर तू मर्तबा चाहे,

कि दाना खाक में मिल कर गुलो गुलजार होता है।

चौधरी हरकिशन लाल कम्बोज (रोड़ी): मोहतरिम साहबे सदर, मैं चन्द मिनटों में अपनी तरफ से मुतालवा नंबर 30 तामीराते आमा और मुतालबा नं0 43 दरियाई योजना के बारे मैं कुछ अर्ज करूंगा। मुखलिफ पार्टी की तरफ से एक माननीय सदस्य ने डिमांड नं0 43 पर एतराज किया था कि यह नाजायज मांग है और यह मंजूर नही होनी चाहिएं उनका यह एतराज सरासर गलत है। रावी और ब्यास का पानी जो हरियाणा को जल्दी ही मिलने वाला है, उसे आगे तकसीम करने के लिए यदि पहले से हम कोई इंतजाम नहीं करेंगे तो एकदम जब पानी मिलेगा उसके बारे में क्या समझते हैं कि उस पानी का हम क्या करेंगे यह मुझे समझ नहीं आता। यह डिमांड सही है, मैं इसका समर्थना करता हूं ताकि रावी ब्यान का पानी मिलने से पहले पहले अपनी नहरें और मुनासिब इंतजाम को उस पानी को आगे इस्तेमाल करने के लिए करना हो वह कर लें। तो इस डिमांड की भी और दूसरी डिमांड की कि भी मैं ताईद करता हूं और सदन से प्राथना करता हूं कि ये डिमांडज पास होनी चाहिएं लेकिन मैं आपकी विसातत से चेयरमैन साहब, कुछ एक दो बातों की तरफ सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं।

चेयरमैन साहब, मेरें हलके में हर साल दरिया घग्गर में तुगियानी आने से 12–13 गांव को नुकसान होता है जिसकी तमाम खरीफ की फसल आम तौर पर और कई दफा रबी की फसल भी तबाह हो जाती है और लाखों रूपए का नुकसान उन किसानों को हर साल होता है। पिछले साल भी सरकार की तवज्जुह उससकी तरफ दिलाई गई थी लेकिन न मालूम उसकी तरफ आज तक क्यों ध्यान नहीं दिया गया। ओटू के नीचे नीचे तो उसे चैनेलाइज कर दिया गया है लेकिन ओटू हैड से ऊपर की तरफ उन 12–13 गांवों को दरिया घग्गर से बचाने के लिए बांध बनाने का अभी तक कोई इंतजाम नहीं किया गया। तो मैं इसके लिए सरकार का आपके द्वारा ध्यान दिलाना चाहता हूं कि बारिशों का मौसम खत्म होने के बाद जल्दी से जल्दी दरिया घग्गर के दोनों तरफ बाधं बना कर इन 12–13 गांवों को हर साल होने वाले नुकसान से बचाया जाए। एक साल में जितना नुकसान होता है उतने ही खर्चे से ये दोनों बांध बनाए जा सकते हैं

दूसरे मेरे हल्के में एक सुखचैन नहर है। इस नहर का जिक्र मैं तनी चार साल से लगातार कर रहा हूं। पंजाब सें यह सुखचैन नहर आती है। ऊपर से तो हरियाणा में रजिया ब्रांच आती है लेकिन रजिया ब्रांच से सुखचैन नहर और दूसरी कई नहरें निकलती हैं। शुरू में दस ग्यारह मील यह पंजाब के अंदर से गुजरती है और फिर आगे आकर इसका टेल पोर्शन हरियाणा के 20–25 गांव को सैराब करता है। पंजाब वाले मनमानी कर रहे हैं।

जमीदार लोगों को जब नहर की हसब जरूरत होती है तो वे उसे काट भी देते हैं और सरकारी कर्मचारी ओवरसीयर से लेकर मैं तो कहूंगा ऊपर एस0ई0 साहब तक जो हैं वे निहायत बदयंती से अपने हरियाणा के पानी को नाजायज तौर पर डायवर्ट कर रहे हैं और पंजाब के किसानों को दे रहे हैं। पहले भी वह हमारे हिस्से का पानी ले रहे थे और अब भी ले रहे हैं सारा नुकसान उन 20–25 गांवों को ही उठाना पडता है। हमारे इन गांवों की फसल बरबाद होती है। उस नहर में उनको पहले कोई मोघा नहीं था लेकिन अब उनहेंने पांच मोघे लगा लिए हैं। तकरीबन 1500 क्यूसिक पानी जो हरियाणा के हिस्से का है वह उसमें से पंजाब को भी दिया जाता है। यह कोई जस्टीफिकेशन नहीं है। उस समय तो सरकार के लिए मुश्किल था क्योंकि अकाली सरकार थी, फिर गवर्नर का राज्य आ गया परन्तु अब तो दोनों स्टेटस में कांग्रेस पार्टी की ही सरकार है, इसलिए इस मसले को बातचीज करके आसानी से हल किया जा सकता है।

मैं एक और बात की और भी सरकार का ध्यान दिलाना चाहूंगा यह जो सुखचैन नहर का मसला है उसे भी हल किया जाना चाहिए। यह मसला स्टेट लैवल पर हल हो सकता है। आपस में दोनों सरकारें मिलकर इस सुखचैन नहर को जो कि दुःखचैन नहर बनी हुई है और जिसके कारण हमें पूरा फायदा नहीं मिल रहा है, उसको फिर से सुखचैन नहर में तबदील करें। मैं इस बारे में एक सुझाव देना चाहता हूं। एक अलग से पक्की नहर बना दी

जाए ताकि पंजाब वाले उसमें न तो अपने मोघे ही लगा सकें और न ही नहर को काट सकें।

मेरे हल्के में साठ सत्तर गांव दरियाये घग्गर के शमाल की तरफ वाक्य हैं, बडे बडे ब्लाक हैं। इन साठ सत्तर गांव के अंदर बहुत कडवा पानी है। जमीन में जो पानी है, वह पीने के लायक नहीं है। मैंने इस ओर से सरकार का पहले भी ध्यान दिलाया था और आज फिर दिलाना चाहता हूं। उन गांवों की बहुत बुरी हालत है। मैंने सरकार को याददाहनी करायी है। उन देहातों के लिए पानी की कोई स्कीम बनाई गई थी। अलीका गांव में यह वाटर वर्क्स लगाने की योजना थीं इन साठ सत्तर गांवों के भाईयों की हालत अप्रैल और जून के महीने में बहुत ही बुरी होती है। बारिश शुरू होने से पहले उन गांवों के लोगों को बडी दूर दूर से पानी लाना पडता है। वे लोग या तो तालाबों से पानी लेते हैं या नहरों का पानी पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब किसी गांव के पास से जो नहर गुजरती है उसकी बारी न हो तो दूसरे पास के गांव से पानी लाना पडता है। जो जमीन के नीचे पानी है उससे तो कुरला भी नहीं किया जा सकता। वह बहुत ही कडवा पानी होता है। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि जल्दी से जल्दी वहा ंपर वाटर वर्क्स बनाया जाए। मैं इन अलफाज के साथ इन डिमांडज की ताईद करता हूं।

राव दलीप सिंह (कनीना) चेयरमैन साहब, सप्लीमैंट्री डिमांडज पर जो आज बहस हो रही है उसके बारे में मैं सिर्फ

इतना ही कहूंगा कि जो ब्यास प्रोजैक्ट के बारे में सात करोड 91 लाख रूपए की डिमांड रखी है यह बडे अच्छे काम के लिए है लेकिन साथ ही साथ मैं सरकार से यह वचन चाहूंगा कि इस रकम को खर्च करने के बाद जो पानी इस ब्यास प्रोजैक्ट से मिले वह डिस्ट्रिक्ट महेन्द्रगढ के लिए ही रिजर्व रखा जाए। यह पानी ज्यादा बैकवर्ड एरियाज के लिए ही होना चाहिए जैसे महेन्द्रगढ, रिवाडी तहसील, जो गुडगांव जिले की है। आपने देखा होगा कि जिला करनाल, रोहतक, जींद और हिसार के इलाकों में चावल और गन्ने की फसल पैदा होती है परन्तु महेन्द्रगढ के जिले ने क्या गुनाह किया है कि वे कभी भी पैदा न कर सकें। उन जिलों के अंदर कोई गांव ऐसा नहीं देखा गया जिसमें कुओं पर बिजली की मोटर न लगी हुई हो परन्तु हमारे महेन्द्रगढ जिले के अंदर 15 हजार रूपए में टयूबवैल लगता है और पांच हजार रूपए में कुआं बनता है। तो आप इससे अंदाजा लगाएं कि एक जमींदार इतना खर्च कैसे बर्दाश्त कर सकता है। कि बैकवर्ड एरिया के साथ इतनी डिस्क्रिमीनेशन हो, इतना जुल्म हो। चेयरमैन साहब, मैं आपके जरिए चीफ मिनिस्टर साहब से अपील करूंगा कि अगर वे इंसाफ पसंद हैं तो यह सारा पानी डिस्ट्रिक्ट महेन्द्रगढ के लिए रिजर्व रखा जाए। डिस्ट्रैट महेन्द्रगढ के लोग बडे ईमानदार और मेहनती हैं। उन्होंने अभी जो पीछे लडाईया हुई उनमें बडी कुर्बानियां दीं। वें हरियाणा में किसी से पीछे नहीं रहे। जिले महेन्द्रगढ के लोगाों ने अंग्रेजों के साथ भी खुली टक्कर 1857 में ली थी। उस वक्त जब महेन्द्रगढ पंजाब का हिस्सा था तब भी बैकवर्ड रहा और आज

जब हरियणाा प्रांत अलग से बन गया है तो भी पीछे क्यों रखा जाता है ? उन लोगों के लिए यह बायसे शर्म बात है कि कुछ लोग तो हरियाणा में आराम से बसते हैं, आराम से खाना खाते रहें लेकिन डिस्ट्रिक्ट महेन्द्रगढ के लोग दु:खी हों और परेशान हों, वे अपनी पढाई न कर सकें, कपडे ठीक तरह से न पवहन सकें। उस एरिया में जब कहत पड जाता है तो वहां के लोग इधर पंजाब में या दूसरी स्टेटस के अंदर चले जाते हैं इसलिए अंत में मैं सिर्फ इतनी प्रार्थना करूंगा कि सरकार हमें यह वचन दे कि यह पानी मेहन्द्रगढ के लिए रिजर्व होगा। अगर सरकार इसमें नैगलीजैंस करेगी तो it will be criminal on their part और हमारे इलाके के साथ बहुत अन्याय होगा। इस बात को फिर दोहरात हुआ अपना स्थान लेता हूं कि यह पानी जरूर महेन्द्रगढ के लोगों को दिया जाए।

श्री गौर शंकर (नरवाना): चेयरमैन साहब, मैं सबसे पहले अन एम्पलायमैंट की ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहूंगा। अन एम्पलायमैंट को दूर करने के बारे में मेरी एक सजैशन है कि जो हमारे आई0टी0आई0 के स्कूल हैं उनको बंद कर देना चाहिए। उन आई0टी0आई0 स्कूलों से जो बच्चे ट्रेनिंग लेकर निकलते हैं उनको काम नहीं मिलता है। इसलिए मेरी एक सुजैशन है कि जितनी फैक्टरीज हैं उनमें बच्चों को ट्रेनिंग दी जाए। जहां फैक्टरीज में इतने लोग काम करते हैं वहां पचास बच्चे और भी काम कर सकते हैं। 10 या पांच परसैंट के हिसाब से ट्रेनिंग के

लिए भेज दिया जाए और उन ट्रेनिंगज को पचास परसैंट फैक्टरीज वाले दें और पचास परसैंट सरकार दें। इस प्रकार से अपनी ट्रेनिंग के पश्चात वे उन ही फैक्टरीज में एडजेस्ट हो जाए। अगर किसी फैक्टरी में 100 आदमी काम करते हैं तो वहां पर 10 बच्चे ट्रेनिंग के लिए भेजे जाएं और उसी फैक्टरी में ट्रेनिग के बाद एजडेजस्ट कर लिए जउएं अरग वे उनको नौकरी पर न लगा सकें तो किसी दूसरी फैक्टरी में जाकर नौकरी कर लें। आई0टी0आई0 की ट्रेनिंग किए हुए बच्चों को कोई सर्विस नहीं मिलती है। इसलिए मैं हाउस का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि हमारे जो आई0टी0आई0 के ट्रेनिंग सैंटर हैं उनको बंद करके वहां पर फैक्टरीज लगा दी जाएं।

चेयरमैन साहब, अब मैं गऊशालाओं के बारे में कहना चाहता हूं। गऊशालाओं से न कोई आमदनी होती है, न ही वे कोई गाय या खागड वगैरह अच्छी नस्ल के पैदा करते हैं। इनमें जो मवेशी है उनसे काफी आमदनी हो सकती है। गऊशालाओं का एक बोर्ड बनाया जाए। इससे स्टेट को बहुत लाभ हो सकता है। दूसरे हमारे जो ब्लाक्स हैं उनकी बजाए 20—20 और 25—25 गांवों की आबादी के ऐसे ब्लाक्स बनाए जाएं जेसे लेकल बाडीज, म्यूनिस्पिल कमेटी होती हैं। इन ब्लाक्स से ज्यादा तरक्की हो सकती है, उनमें ज्यादा काम हो सकता है।

(इस समय श्री अध्यक्ष पदासनी हुए)

मैं आपके जरिए एक और भी रिक्वैस्ट करूंगा कि हमारे नरवाना में कोई भी इन्डस्ट्रियल अस्टेट नहीं है। अब तो हरियाणा के अंदर सब जगह बिजली चली गई है कोई कस्बा या टाऊन ऐसा नहीं है जहां बिजली नहीं है। इसलिए जींद जिले में भी इंडस्ट्रियल अस्टेट बनाई जानी चाहिए। नरवाना में इन्डस्ट्रियल अस्टेट बन सकती हैं और वह बनाई जानी चाहिए। हमारे एरिया में जो बरवाला नहर निकाली गइ है उसका नरवाना तहसील मैं कोई पानी नहीं दिया जाता है। नरवाना मे ंपानी की कमी है इसलिए उस नहर में से कुछ पानी वहां भी दिया जाए। मैं मुख्य मंत्री साहब से अर्ज करूंगा कि उस नहर में जितने भी मोघे लगाएं वे बेशक जमींदारों के खर्च पर लगा दिए जाएं। मैं अंत में फिर प्रार्थना करूंगा कि जो बातें मैंने कहीं हैं उन पर जरूर ध्यान दिया जाएं

मुख्य मंत्री (चौधरी बंसी लाल): स्पीकर साहब, पिछले करीब चार घंटे से या सवा चार घंटे से हमारे सप्लीमैंट्री एस्टीमैटस की डिमांडज पर बहस हो रही है। इसमें हमारे सदन के कई साथियों ने, कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी और विरोधी पार्टियों की तरफ से भी , भाग लिया है। इसमें कई अच्छे सुझाव भी आये और कई स्पीचें बडी गैर जिम्मेदाराना भी हुई। जो स्पीचें सबसे ज्यादा गैर जिम्मेदाराना हुई, उनमें मैं कहूंगा सबसै पहले स्पीच चौधरी रिजक राम की थी जिसमैं न कोई सुझाव था, न कोई अच्छी बात थी और न कोई काम का क्रिटिसिज्म था। वह

एक गैर जिममेदाराना तकरीर थी। इसी तरह से दूसरी स्पीच श्री शिव राम वम्र की थी। उन्होंने कहा कि हरियाणा प्रान्त की सरकार का दिवाला निकल गया। स्पीकर साहब, हरियाणा प्रान्त की सरकार का तो दिवालन नहीं निकला, अलबत्ता, जनसंघी भाईयों की, अकल का दिवाला जरूर निकल गया है। जो इस तरह की बातें कर रहे हैं। (सरकारी बैंचों की ओर से तालियां) तीसरी बात जो एक खास गैर जिम्मेदाराना ढंग से कही गयी, वह गुलाटी साहब की तरफ से आयी। खैर, मैं इन तीनों मैम्बरों सें यह बात एक्सपैक्ट भी कर सकता था। इससे मुझे कोई ताज्जुब भी नीं हुआ कि इन लोगों ने ऐसी बातें क्यों कहीं ? स्पीकर साहब, वैसे तो सप्लीमैंट्री की जो हमारे डिमांडज हैं, वह लिमिटिड सब्जैक्टस के ऊपर हैं लेकिन मुझे इस बात पर कोई एतराज न पहले था, न अब है और न ही अगर कोई कल को एप्रोप्रिएशन बिल पर इर रैलवैंट बोलेगा तो होगा। स्पीकर साहब, हम तो यह जानना चाहते हैं कि कहां कहां पर हम ठीक काम कर रहे हैं और कहां कहां पर हमसे कोई गलती हो रही है। अगर किसी जगह पर कोई गलत काम हो रहा है, तो हम उसमें अपनी गलती को सुधारने की कोशिश रहेंगे। स्पीकर साहब, हम आज डिवैल्पमैंट के काम करने में सरकार की सहायता करें। उनको सिर्फ यही काम नहीं है कि जो काम सरकार करें, वे उसी काम की नुक्ता चीनी करें। अब हकीकत यह हो गयी है कि काम करना, अपोजीशन पार्टी वालों के हिसाब से जुर्म हो गया है। काम न करें तो वैसे खराब, जनता के हिसाब से खराब, और अगर काम करते हैं तो अपोजीशन वालों के

हिसाब से खराब, मगर जब ये भाई देहातों में या शहरों में जाकर सरकार की नुक्ता चीनी करते हैं तो इनको मुंह की खानी पडती हैं। जनता वहा ंपर इन्हें बोलने नहीं देती, इसलिये यहां आकर, गैर जिम्मेदाराना बातें कह कर अपने दिल के गुबार निकालते हैं। इनके दिल के गुबार निकालने से हमें न तो कोई नुकसान है और न ही होने का कोई डर है। स्पीकर साहब, यहां पर तकरीर करते हुए विरोधी पार्टी के एक सदस्य श्री फूल चन्द ने यह कहा कि रोहतक जिले में पानी कम मिलता है, हमें यह एप्रीहेन्शन है कि पानी कम क्यों मिलता है । कई दिनों से जब से यह अधिवेशन शुरू हुआ, कांगों (कांग्रेस ओ) वालों की तरफ से यह कोशिश हो रही है, चाहे वह चौधरी रिजक राम जी हों या दल सिंह जी हों, या चौधरी फूल चन्द जी हों, कि जितना हो सके, हाउस को मिसलीड करें। जितना हो सके, हाउस के मैम्बरों को या जो दर्शक गैलरी में लोग बैठे हैं, उनको यह जंचायें कि हरियाणा दमें कोई गलत काम हो रहे हैं यह गैर जिम्मेदारी की बातें हैं और ये लोग ऐसी गैर जिम्मेदारी की बातें कह कर सरकार को अपने सही रास्ते से नहीं हटा सकते। स्पीकर साहब, जब से यह सरकार आयी है, उस वक्त से आबपाशी का पानी, रोहतक जिले में बढाया गया है। यही नहीं, बडी सबस्टैंशियल क्वांटिटी में बढाया गया है। अगर रोहतक जिले में कभी पानी कम आया था या रोहतक जिले में कभी कम पानी होता था तो जो तकरीर कर रहे थे चौधरी फूल चन्द जी, उनके गुरू चौधरी रिजक राम जी जब इरीगेशन एण्ड पावर मिनिस्टर थे उस वक्त था। उनके वक्त में रोहतक जिले का

भटठा बैठा था, हमारे वक्त में नहीं। स्पीकर साहब, एक गलती आपके सैक्रिटेरियट से भी हो गयी। वह यह कि जो हमारे दो पुराने इरीगेशन एण्ड पावर मिनिस्टर चौधरी रिजक राम और चौधरी दल सिंह हैं, इन दोनों फयुज हुए बल्बों को एक ही सीट पर बिठा दिया। इसलिये इन्हें अब अकल कैसे आये (सरकारी बैंचों की ओर थम्पिंग) क्योंकि अकल के बल्ब तो इनके फयूज हो गये, अब अकल की बात कहां से कहं। यह गलती आपके सैक्रिटेरियट से हो गयी। स्पीकर साहब, यहा ंपर बहुत सी बातें कहीं गयी हैं। चौधरी मनफूल सिंह, चौधरी मेहर चन्द जी और दूसरे कुछ सदस्यों ने महकमा नहर के अधिकारियों की कुछ गलतियों की तरफ तवज्जुह दिलायी। मैं किसी को डिफैंड नहीं करता लेकिन मैं यह कहता हूं कि हमने इस बात की पूरी कोशिश की है कि पूरे प्रान्त में नहर के अधिकारी ठीक ढंग से काम करें। स्पीकर साहब, इस बात को आपको भी पता है, दूसरे भी बहुत से सदस्यगण जो इस हाउस में हैं, उनको भी नौलेज में है कि यहां से यानी हैडक्वार्टर से टीम बना बना कर, मिनिस्टर की, सैक्रेट्री की, आई0जी0 की, चीफ इंजीयिर की या दूसरे बडे अफसरों की लीडरशिप में, मैंने भेजी हैं। और throughout the state at a time पार्टिया भेजी हैं कि चैक करें कि कहीं पर नहर में कट तो नहीं लगा। कहीं किसी जगह नहर के पानी का गलत इस्तेमाल तो नहीं हो रहा, कहीं मोरी तो नीची ऊंची नही लगी। स्पीकर साहब, गलती करते हुए कुछ आदमी पकडे गएं मैं आपको बताऊं ज्यादातर वहीं आदमी पकडे गये, जो नुक्ताचीनी करने वालों के अरीब करीब बैठते हैं। ज्यादातर वही

आदमी पकडे गये जाो अपने आपको बहुत बडा खानदानी और बडा आदमी कहलाते हैं। हमने उनको पकडने की पूरी कोशिश की, और आज भी पूरी कोशिश करते हैं। यही माननीय सदस्गण, जो आज आन दी फलोर आफ दी हाउस महकमा नहर को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, जब हम उनको पकडते हैं तो सबसे पहले उनके सिफारिशी आये हैं। या तो ये महकमें की नुक्ताचीनी कर लें या फिर सिफारिशें कर लें। दोनों में से एक काम कर लें। मेरे साथ तो ऐसा हुआ है कि किसी के मौके पर पकडने की रिपोर्ट आयी, मैंने उसको सस्पैंड किया, चार्जशीट किया और इसी हाउस के मैम्बर या पब्लिक के दूसरे कुछ जिम्मेदार आदमी उनके सिफारिशी चल कर आये कि अब गलती हो गयी, आईन्दा नहीं करेंगे, माफ कर दो। जो आदमी शिकायत करने वाले थे, वही आदमी उनके गवाह बने। हमारे पल्ले कुछ नहीं पडा, उल्टा सरकार को नीचा देखना पडा। हाउस में तकरीर कर देना बडा आसाना है क्योंकि यह एक प्रिविलेज्ड जगह है। मैं तमाम सदस्यगण से प्रार्थना करूंगा, आपके जरिए स्पीकर साहब, कि यह हाउस के बाहर अधिकारियों के ऊपर इल्जाम लगायें और उसके साथ एफीडैविट दें। मैं उसके ऊपर इन्कवायरी इन्स्टीच्यूट करूंगा और जिस अफसर के खिलाफ, कोई चीज साबित होगी, उसे माफ नहीं करूंगा। यहां तकरीर करें और बाहर जाकर उनकी सिफारिशें करें, दोनों बातें एक साथ नहीं चलतीं। मुझे पिछले चार साल की एडमिनिस्ट्रेशन का तजुर्बा है कि 99 प्रतिशत केसिज में यहां उनके

खिलाफ तकरीर करने वाले, सबसे पहले उनकी सिफारिशें लेकर आते हैं, मैंने यह देखा है।

स्पीकर साहब, आबियाने के रूल्ज पुराने बने हुए हैं। यह बात भी यहां हाउस में आयी। चौधरी मेहर चन्द जी, चौधरी मनफूल सिंह जी तथा दूसरे एक दो साथियों ने इस बारे में चर्चा की। सरकार को इस बात में कोई एतराज नहीं होगा कि जो जो रूल्ज आज के हिसाब किताब से या आज के जमाने की रफ्तार के हिसाब से मेल नहीं खाते हैं उन्हें बदला जाये। सरकार उन रूल्ज को बदलने के लिए हर वक्त तैयार है, लेकिन मैं कहूंगा कि आनरेबल मैम्बर्ज कुछ सुझाव हमें लिख कर भेजें। यदि वे हमें लिखकर नहीं भी भेजेंगे तो भी मैं उनकी जांच करवाऊंगा लेकिन मैं तमाम मैम्बरान से आपके जरिये फिर यह प्रार्थना करूंगा कि वे, जो कोई भी उनके सुजैशन्ज हैं, हमें लिखकर भेज दें ताकि हम उनको एग्जामिन करा सकें और अगर मुनासिब हो तो उनाके रूल्ज में इन्सर्ट कर सकें।

स्पीकर साहब, आज जो सप्लीमैंटरी डिमांडज पेश हुई हैं उनमें सबसे बडी राशि 7 करोड 91 लाख रूपए की मल्टीपरपज प्रोजैक्ट के लिए है। इसके ऊपर जो सबसे ज्यादा रैलेवैंट स्पीच मैंने समझी वह हमारे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री राम सरन चन्द मित्तल की थी। पंडित चिरंजी लाल, राव दलीप सिंह ने भी जो बातें कहीं वे भी बहुत रैलवैंट थी। एक बात मैं महसूस करता हूं कि अगर हमने फोरी तौर से पूरे महेन्द्रगढ जिले को, गुडगांवा के

रिवाडी सब डिविजन, जाटूसाना, पटौदी, सोहना, बावल इन सभी इलाकों में नहर से लिफ्ट के जरिए अगर पानी नहीं चला दिया तो गवर्नमैंट के पार्ट पर और किसी भी जिम्मेदार आदमी के पाट्र पर क्रिमिनल नेगलीजैंसे होगा। आने वाली पीढियां कभी भी माफ नहीं करेगी। स्पीकर साहब, मैं इस बारे में अपने व्यूज इन मैम्बरान साहिबान के साथ एसोसिएट करता हूं और आपके जरिए इस सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अब इससे आगे इस सरकार को सबसे पहला काम महेन्द्रगढ जिले के ड्राउट अफैक्टिव एरियाज को पानी देना है (तालियां) इसके साथ साथ हम जाटुसाना, रिवाडी, पटौदी, सोहना, बावल के इलाकों को पानी देंगे।

स्पीकर साहब, पिछले दिनों हमारी गवर्नमैंट आफ इंडिया ने एक कमीशन बनाया जिसे नैशनल कमीशन आफ एग्रीकल्चर कहते हैं। उसके चेयरमैन श्री नाथू राम मिर्धा और वाईस चेयरमैन श्री सिवारमन हैं। उन्होंने पिछले दिनों हमारी स्टेट को तीन दिन तक टूर किया। उन्होंने एक रिपोर्ट दी है। करीब दो तीन पैरा इससे खास कर ताल्लुक रखते हैं। वैसे तो रिपोर्अ काफी लम्बी है। वे पैरे मैं आपके जरिए सदन को पढकर सुनाता हूं। उन्होंने लिखा है कि –

"The chronic drought affected areas in the State of Haryana lay to the south west of the State in the areas brodering the districts of Sikar, and Jhunjhunu in Rajashtan. This area is a plateau rising gradually from plains of Hissar

and Rohtak and going up towards the hills separating Rajasthan from Haryana. This plateau lise mainly in Mohindrgarh District which district is almost completely chronic drought affected except for a small plains portaion. The southern portion of Hissar in the Siwani and Jui area is alo within this palteau. A samall portion of Rohtak and a portion of Gurgaon in the Rewari area also falls in this plateau ....."

स्पीकर साहब, पीछे मैं जब चर्चा कर रहा था तो झज्जर तहसील भूल गया था। हमारे इस प्रोग्राम में झज्जर तहसील और नाहड तब तहसील का हिस्सा भी शामिल है। जिनको कि पानी दिया जाना जरूरी है। स्पीकर साहब, आगे वे लिखते हैं .....

..... It is chronically drought afftect. It is reported that in nearly seven years out of ten years the rain fall is capricious. In addition, district sand blown with a westerly hot breeze and saline ground water. The area, therefor, qualifies both under the chronic drought affectd area scheme of the Centre and also the desert development programme.

दूसरे पहरों में वे कहते हैं।

"The Commission went to this area to find out what sort of programmes are to be taken up to develop this area. Water is of course the best answer to desert conditions but one rarely gets an opportunity to avail of supplying water to derest areas is bound to be costly. It also draws upon water

of other cathment and basins, the diversion of which may be resented by the population of those basins. Three Lift Irrigation schemes based on the Western Jamuna Canal system and utilizing the high rainy season discharges in Jamuna from July to September, have already been sacntioned and are being rapidly completed. A fourth one is under contemplation and if all goes well should be started in the next year..... ".

The fourth one is Pandit Jawahar Lal Nehru Feeder and Pandit Jawahar Lal Nehru canal and Mohindergarh canal will be a part it. They further write-

"..... These lift irrigation schemes will give a very sound base for the desert development and improving the agriculture in the area, The Commission, therefore, proceeded to examine the problem on the assumption that these programmes of lift irrigation would be pushed throuth quickly and further steps necessary to carry the benefits to as large a population as possible should be planned in the fifth plan formulation of chronic drought affected schemes and desert development in this area."

स्पीकर साहब, यह फाइडिंग्ज हैं हमारे नेशनल कमीशन आफ एग्रीकल्चर की। बावल स्कीम के बारे में उनहोंने कहा है। जैसा कि पहले उन्होंने कहा है आगे वे कहते हैं :–

"That this area is both a chronic drought affected and a desert....." We have prepared a programme to ameliorate it. The Commission is of the view that this should be put through as quickly as possible, this Bawal scheme which will

be Jawahar Lal Nehru canal. The limitation is obviously that of funds. It means the Commission has at many places recommended that we should get funds for this. The Commission has also stated-

"The State Authorities have prepared a programme for rupees so may which will irrigfate one part of Mohindergarh district....."

तो महेन्द्रगढ तथा दूसरी जगहौं को पानी देने की स्कीम जैसे ही कामयाब हो जाएगी मैं समझता हूं हमारे प्रान्त से कहत हमेशा के लिए उड़ जाएगा। स्पीकर साहब, कमीशन के चेयरमैन और वाईस चेयरमैन ने अपनी रिपोर्ट में एक छोटा सा पैरा और लिखा है। अभी कुछ साथी इरीगेशन आफिसर्ज की बुराई कर रहे थे। उनके लिए मैं यह छोटा पैरा पढकर सुनाता हूं–

"One important aspect which struct the Commission most was the tremendous speed with which the lift irritation scheme has been ocmpleted in this part of the country....."

That is a compliment to our officers. The Commission further says-

"By any standard this is an engineering feat of which any country should be proud ....."

(Thumping from the Treasury Benches). These are the compliments which the Commission has paid to our officers, and further they say-

"Haryana evidently has capacity to organise and push through the schemes. Considerting that many of our large irrigation projects and particularly the canal systems have been held up in may parts of the country by incomplete work and land acquisitioni disputes, it was most encouraging to see a large lined canal with several pumping stations completed well in time."

This is what the Commission says, the National Commission says and here our people say that our officers are not good.

And then, Speaker Sahib, the Commission further says-

"The time itself was set for furious pace. Considering from this aspect the Commission has no doubt at all that the desert and drought problems of Mohindergarh area would be solved within the next two or three years again provided the funds for the Bawal Lift Scheme are found."

Speaker Sahib, further they say-

"The Commission also feels that as this is such a chronic drought affected area and a desert area there is a case for a special help to the lift irrigation scheme as a permanenet solution to both the problems."

I think, the Commission has left nothingh to comment now.

यहां अभी जनसंघ के एक साथी ने बडे जोर से कह दिया कि सरकार का तो दिवाला निकल गया है। स्पीकर साहब,

मैंन बताया कि हमारी सरकार का तो दिवाला निकला नहीं। अगर हमारे पास पैसा नहीं होगा तो जो हमारी सरकार दिल्ली में है वहां से पैसा मिल जाएगा। मगर जनसंघ की अक्ल का दिवाला जरूर निकल गया है और हमेशा के लिए निकल गया है और अकल कभी लौट कर इनके पास नहीं आएगी। स्पीकर साहब, कल या परसों अखबार में एक रिपोर्ट आई, बडी मिस लीडिंग सी रिपेार्ट थी। आमतौर से मैं अखबार नहीं पढता मगर मेरे सामने पब्लिक रिलेशन्ज डिपार्टमैंट वालों ने एक कटिंग रख दी। चण्डीगढ़ से अंग्रेजी का एक गैर जिम्मेदार अखबार निकलता है और एक गैर जिम्मेदार कमैंट उसने छापी कि रिवाड़ी लिफ्ट इरीगेशन स्कीम पर इतना रूपया जाया गया। वह समझता तो यह था कि यह चोट मौजूदा चीफ मिनिस्टर को लगेगी मगर उस अखबार ने तीर पर तीर चलाए, मेरे सामने उसके सारे हथियार बेकार हो गए क्योंकि यह अखबार बोगस है।

स्पीकर साहब, वह रिवाड़ी लिफ्ट स्कीम मौजूदा गवर्नमैंट के वक्त में नहीं बनी थी। वह राव बीरेन्द्र सिंह जी के वक्त में और चौधरी रिजक राम जी के वक्त में बनी थी। बगैर किसी प्रोग्राम के बगैर किसी योजना के और बिना किसी कन्टूर के यह नहर बनाई गई। इसमें मौजूदा सरकार का कोई हाथ नहीं है, हमारी इसमें कोई गलती नहीं है। किसी गैर जिम्मेदार सरकार के वक्त में यह नहर बनी और एक गैर जिम्मेदार अखबार ने जो

कि चण्डीगढ से छपता है, एक टिप्पणी छाप दी, हसमें हमारा क्या दोष है ?

एक आवाजः कौन सा अखबार था ?

चौधरी बंसी लालः चण्डीगढ से एक ही अखबार छपता है और वह भी गैर जिम्मेदार अखबार है।

स्पीकर साहब, इसी सप्लीमैंट्री डिमांडज पर चर्चा करते हुए चौधरी मनफूल सिंह जी ने एक बात कही कि हरियाणा विधान सभा लाईब्रेरी के लिए एक लाख रूपया देना ठीक है लेकिन पंजाब और हरियाणा के वक्त की जो असैंबली और विधान परिषद की लाइब्रेरी थी उसका भी डिवीजन होना चाहिए, मैं उनके इस मत से बिल्कुल सहमत हूं और हमने यह मामला केन्द्र सरकार के साथ टेक अप किया था और अब फिर करेंगे और हम कहेंगे कि हमारे हिस्से की किताबें हमें मिलनी चाहिएं मैं इस मामले में चौधरी मनफूल सिंह जी से सैंट परसैंट सहमत हूं। पंडित चिरंजी लाल जी ने यहां इन डिमांडज पर बोलते हुए जो बातें कहीं, मैं समझात हूं कि सभी बातें रेलवैंट थीं। पंडित चिरंजी लाल जी और चौधरी रिजक राम जी एक ही जगह सोनीपत में प्रैक्टिस करते हैं, अच्छा होता कि यदि वे कोई कंस्ट्रक्टिव बात पंडित चिरंजी लाल जी से सीख लेते। स्पीकर साहब, मुझे तो ऐसा लगता है कि सारी अच्छी अच्छी बातें पंडित चिरंजी लाल जी में चली गई हैं और चौधरी रिजक राम जी इस बारे में खोखले रह गए हैं।

चौधरी रिजक रामः स्पीकर साहब, उन्होंने सारी बातें मेरी ही कहीं हैं।

चौधरी बंसी लालः स्पीकर साहब, इस सदन में यह भी कहा गया, शायद चौधरी रिजक राम जी ने यह कहा है कि किसानों को यह नहीं बताया जाता कि कौन सी धरती कैसी है। सायल वाटर टैंसटिंग के लिए कोई फैसिलिटी नहीं है। मैं उनको बताना चाहता हूं कि हम हर तरह की किसानों को एडवाईज देते हैं सारी बातें करते हैं और इसके इलावा हम और भी मदद करना चाहते हैं। यूं ही चौधरी रिजक राम जी क्रिटीसाईज करने के लिए भाषण दिया है, कोई कंस्ट्रक्टिव बात, सुझाव तो उन्होंने दिया ही नहीं।

चौधरी रिजक रामः स्पीकर साहब, उन्होंने सुना ही नहीं। मैंने कहा था सालय टैसटिंग के लिए 4 प्रयोगशालाएं हैं।

चौधरी बंसी लालः स्पीकर साहब, आगे चल कर एक जनसंघी सदस्य चौधरी शिव राम वर्मा ने कहा कि बिजली का जितना काम हुआ है, वह गलत हुआ हैं, बगैर सोचे समझे हुआ है। चौधरी शिव राम वर्मा जी की नजरों को हर सही बात गलत दिखर्इा देती है क्योंकि जनसंघ वाले तो कभी ठीक लाईन पर सोचते ही नहीं हैं। यह तो जब असैम्बली में भी आते हैं तो मेरे ख्याल में एक कदम आगे रखते हैं तो दो कदम पीछे रखते हैं। स्पीकर साहब, मैं इनको यह बतदा देना चाहता हूं कि सरकार का

जो बिजली का सिस्टम है, सरकार ने जो रूरल इलैक्ट्रीफिकेशन की है वह सारे हिन्दुस्तान में सबसे बैस्ट है, सबसे शानदान सुन्दर की हे। अगर कोई गैर जिम्मेदारी से यह हमें कहीं कि यह गलत काम हुआ है तो उनके कहने से यह काम गलत नहीं हो सकता। स्पीकर साहब, इसके इलावा कुरप्शन के बारे में कुछ बातें यहा कहीं गई हैं। मैं यह नहीं कहता कि कुरप्शन नहीं है, क्योंकि ऐसा राम राज्य अभी आया ही नहीं है कि कुरप्शन न हो लेकिन इसके लिए हम भरसक प्रयत्न करते हैं, कोशिश करते हैं कि कुरप्शन कैसे होती है। कुरप्शन तब होती है जब पब्लिक का कोई आदमी किसी को पैसा देता है। हम तो चाहते हैं कि कोई पब्लिक का आदमी पैसा न दे और अगर लोगों से कोई अफसर पैसा मांगते हैं तो वह हमारे पास आएं, हमें बताएं हम उनको रोकंगे। हम यह नहीं चाहते कि कोई रिश्वत लेकर के काम करे, हम यह भी नहीं चाहते कि कोई अधिकारी किसी काम में कोताही करे, किसी काम में ढील करे, हमें बताओ, हम कुरप्शन को रोकेंगे और जो भाई कहने वाला है वे हमें पर्टीकुलर केसिज के बारे में बताएं। हम उसका इलाज करने की कोशिश करेंगे लेकिन इस तरह से खाली कहने से यह बंद नहीं होगी जब तक कि हमें कोई इसका ठोस सबूत न मिले। स्पीकर साहब, मेरे एक भाई ने यहां पर यह भी कहा है कि एम0एस0एस0 बोर्ड में तीन तीन हाजर रूपए लेकर एक एक टीचर की एप्वायंटमैंट होती है। मैं उस शख्स से कहूंगा कि इस हाउस से बाहर जाकर वह हलफिया बयान दें, जिस आदमी ने तीन हजार रिश्वत ली है, उस आदमी का नाम बताएं। हम केस

रजिस्टर करवाते हैं। यहां हाउस की छत के नीचे जहां कि प्रोटैक्शन मिलती है, वहां ब्लैक मेल कर लें और बाहर जाकर कहने की हिम्मत है तो वह एफीडेविट दे, हम उसे हवालात में देकर केस चलाएंगे। यूं ही गैर जिम्मेवारी के साथ ऐसी बात कह देना, यह ठीक नहीं। स्पीकर साहब, गुलाटी साहब भी तकरीर कर रहे थे, वह गैर जिम्मेवार तकरीर थी और तकरीर के लिए तकरीर कर रहे थे। (व्यवधान)

बहिर्मन

श्री के0एन0 गुलाटीः स्पीकर साहब, मैं वाक आऊट करता हूं। (हंसी)

अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान (पुनरारम्भ)

चौधरी बंसी लालः स्पीकर साहब, यह परमानैंट वाक आऊट कर जाएं तो ठीक रहे। (हंसी) स्पीकर साहब, हकीकत यह नहीं है कि पांच पांच रूपए में फरीदाबाद में सीमेंट की बोरी बिकती है बल्कि हकीकत यह है कि शायद गुलाटी साहब अधिकारियों को रोब दिखा कर सीमेंट लेना चाहते हैं। हाथोंपार्ठ तक की भी नौबत आ जाती होगी। तो अगर ऐसें एम0एल0एज0 हों तो बताइए ऐसे आदिमियों को हमारे पास क्या इलाज है। (व्यवधान) स्पीकर साहब, इसके साथ साथ कई और सुजैशन्ज कई आनरेबल सदस्यगणों ने दिए। जो अच्छे सुजैशंज होते हैं उन सब सुझावों पर हम विचार करेंगे। हमारी पूरी कोशिश होगी कि जो

सुजैंशज अपोजीशन वाले हमें दें, हम उन पर गौर करेंं। उन पर अमल करने की कोशिश करें। स्पीकर साहब, जो उन्होंने सरकार पर और सरकारी मशीनरी के ऊपर तरह तरह के इलजाम लगाने की कोशिश की है, वह बिल्कुल निराधार, गलत और बेबुनियाल है और सिर्फ इल्जाम लगाने की नीयत से ही ऐसा कहा गया है। स्पीकर साहब, मैं आखिर में एक बार फिर कहूंगा कि हमारे जो ड्राउट इफैक्टिड एरिया, जैसे महेन्द्रगढ, झज्जर, रिवाडी बाकी बचते हैं उस इलाके के लिए जैसे ब्यास, रावी का पानी आएगा, हम मौजूदा वैस्टर्न यमुना कैनाल का भी पानी बढाएंगे। स्पीकर साहब, एक बात चौधरी फूल सिंह जी ने कही कि रोहतक जिले में पानी कम आ रहा है, यह तो मिस लीडिंग सी स्टेटमैंअ है, इस बात को कोंई नहीं मानेगा। उनको पानी का पता नहीं कि पानी क्या होता है। (व्यवधान) हमारा भरसक प्रयत्न होता है कि ज्यादा से ज्यादा डिवैल्पमैंट का काम करें और मैं अपोजीशन के मैम्बरों को एक बात का आश्वासन देना चाहता हूं कि अगर किसी भी जगह किसी डिवैल्पमैंट के काम में सरकार की तरफ से कोई कोताही देखें और सरकार की तरफ से किसी भी काम में किसी प्रकार की कमी देखें, किसी अधिकारी में कोई नुक्स देखें, हमें बताएं तो हम जरूर एक्शन लेंगे। अपोजीशन की तरफ से कोई अच्छा सुझाव आएग तो सरकार उसको बडी खुशी के साथ मानेगी। हम डिवैल्पमैंट के काम में अपोजीशन की राय लेने के लिए हर वक्त तैयार हैं उनकी हरेक अच्छी बात को मानने के लिए तैयार हैं लेकिन जो चौधरी रिजक राम जी की अपोजीशन के लीडर न

बनने वाली बात है, इसमें हम क्या करें। चौधरी हरद्वारी लाल के साथ मैम्बर हैं तो वह लीडर आफ दी अपोजीशन हैं, हमें तो चौधरी रिजक राम का भी कोई एतराज नहीं है लेकिन जब उनके साथ मैंबर नहीं हैं तो हम इसमें क्या कर सकते हैं। हमारी तरफ से तो कोइ भी हो जिसके साथ मैम्बर हों और आप लिख कर भेज दें हम उसको लीडर आफ दी अपोजीशन मान लेंगे। लेकिन जैसे चौधरी हरद्वारी लाल जी कह रहे थे कि बराती को डूमनी तरह तरह की सीठनियां देती रहीं ऐसी बातों में चौधरी रिजक राम जी को बचना चाहिए क्योंकि वह अच्छी बातें नहीं हैं। मैं अंत में फिर निवेदन करना चाहता हूं कि अगर वे कोई अच्छा सुझाव दें तो हम हर वक्त उसे मानने के लिए तैयार हैं इन शब्दों के साथ मैं प्रार्थना करता हूं कि सदन इन सप्लीमैंटरी डिमांडज को पास करें।

श्री अध्यक्षः प्रश्न यह है–

कि एक अनुपूरक रकम, जो 123870 रूपये से अधिक न हो, 9–भू–राजस्व के सम्बंध में 31 मार्च, 1973 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को देने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

मुख्य मंत्री तथा बहुत से सदस्यः स्पीकर साहब, बाकी की आप सारी डिमांडज इकट्ठी ही ले लें।

श्री अध्यक्षः यदि मैम्बर्ज की यही इच्छा है तो मैं इकट्ठी ही पुट कर देता हूं। प्रश्न यह है–

कि एक अनुपूरक रकम, जो 654000 रूपये से अधिक न हो, '18–संसद' के सम्बंध में 31 मार्च, 1973 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को देने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक रकम, जो 70000 रूपये से अधिक न हो, '22–जेलें' के सम्बंध में 31 मार्च, 1973 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को देने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक रकम, जो 10 रूपये से अधिक न हो, 'सिंचाई स्थापना पर प्रभार' के सम्बंध में 31 मार्च, 1973 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को देने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक रकम, जो 1750000 रूपये से अधिक न हो, '50–लोक निर्माण कार्य' के सम्बंध में 31 मार्च, 1973 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को देने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक रकम, जो 10 रूपये से अधिक न हो, '70–वन' के सम्बंध में 31 मार्च, 1973 को समाप्त होने वाले वर्ष

के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को देने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक रकम, जो 1250010 रूपये से अधिक न हो, '71—विविध' के सम्बंध में 31 मार्च, 1973 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को देने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक रकम, जो 79100000 रूपये से अधिक न हो, '98—बहुउद्देशीय नदी स्कीमों पर पूंजीगत परिव्वय' के सम्बंध में 31 मार्च, 1973 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को देने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक रकम, जो 10 रूपये से अधिक न हो, '99—सिंचाई इत्यादि निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय (वाणिज्यिक)' के सम्बंध में 31 मार्च, 1973 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को देने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक रकम, जो 100 रूपये से अधिक न हो, '103—लोक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय' के सम्बंध में 31 मार्च, 1973 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को देने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक रकम, जो 10 रूपये से अधिक न हो, 'स्थानीय निधियों तथा गैर सरकारी पार्टियों आदि को कर्जे' के

सम्बंध में 31 मार्च, 1973 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को देने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

6.52 सायं

श्री अध्यक्षः सभा कल 9.30 बजे तक स्थगित की जाती है।

(तत्पश्चात सभा 22 अगस्त 1972 के 9.30 बजे प्रातः तक स्थगित हो गई।)